Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 9 Issue - 01 November- 2025
Total Pages - 76 Price - Rs. 100

खास स्टोरी

प्रवासियों का दिल जीतने का जतन

- गवर्नेंस का गुजरात मॉडल
- इन-लैंड पोर्ट की पटकथा

PRAVASI RAJASTHANI DIVAS

प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस

10 दिसंबर, 2025 @ जयपुर

राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सशक्त महिला - समृद्ध राजस्थान

5 लाख लाभार्थी महिलाएं
₹170 करोड़ का भुगतान
मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना

24,686 कन्याएं
₹96.24 करोड़ का अनुदान
कन्या विवाह

बालिका जन्म पर **₹1 लाख से**
बढ़ाकर ₹**1.50 लाख**
लाडो प्रोत्साहन योजना

20 प्रतिशत
की वृद्धि
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय

2,216 पद
स्वीकृत
तीन महिला बटालियन

9.92 लाख महिलाएं
₹531 करोड़ का अनुदान
देय राशि **5,000 से बढ़ाकर 6,500**
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

7,446 लाभान्वित जोड़े
₹20.36 करोड़ का अनुदान
सामूहिक विवाह योजना

₹450 में घरेलू गैस सिलेंडर
₹867 करोड़ का अनुदान
मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना

19.24 लाख पेंशनरों को
₹6,234 करोड़ का भुगतान
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

20 प्रतिशत बढ़ाकर
₹6,428 प्रतिमाह
साथिन का मानदेय

1.37 लाख स्वयं सहायता समूहों को
₹669 करोड़ की राशि
महिला आजीविका संवर्धन

19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण
12.06 लाख महिलाएं
लखपति दीदी

500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट
500 स्कूटी
2,000 कॉन्स्टेबल पदों का सृजन
महिला सुरक्षा

90 वन धन विकास केंद्र गठित
15,878 जनजाति महिलाएं लाभान्वित
पीएम-जन मन योजना

10.51 लाख साइकिलें
39,586 स्कूटियां
छात्राओं को वितरण

4.18 लाख पेंशनरों को
₹647.58 करोड़ का भुगतान
विधवा पेंशन योजना

₹215.66 करोड़
2,418 ऋण आवेदन
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

2.21 लाख को
₹4,992 करोड़
स्वयं सहायता समूहों को ऋण

58,397 छात्राओं को
₹102.80 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
कृषि अध्ययन को बढ़ावा

1.22 करोड़ महिलाओं एवं
बालिकाओं को
प्रति माह 12 नैपकिन
निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन

4.14 लाख बालिकाएं
₹181 करोड़
बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं में सहायता

राजस्थान संवाद

दो वर्ष की उपलब्धि - आत्मनिर्भर महिला शक्ति

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume - 9 Issue - 1 November 2025

Editorial Board

Patron

Shri Madhusudan Dadu, National President	09810256494
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

Editor

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

Co-Editor

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	3	प्रवासियों का निवेश	41
सन्देश	5	राजस्थानी जैसा जीवठ	42
दिल जीतने का जतन	15	उद्यमिता का पाठ	43
गुजरात मॉडल	20	जड़े मजबूत रहें	44
इनलैंड पोर्ट	26	Economic Growth	46
हमारी जमीन हमारा तेल	31	Mineral in Rajasthan	55
नयी सोच	33	डेस्टिनेशन वेडिंग	60
नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री	35	राजस्थानी माइंडसेट	65
डिग्री नही, कौशल	36	पधारो म्हारो देश	67
पुरखों की धरती	37	दिसावर से वापस देस	70
जापान से सीख	38	IIF UDYAM	71
बिजनेस सेन्टर सिंगापुर	39	Odisha Industrial -	73
याद आती है मरूधरा की माटी	40	L UB News in Brief	74

Price - 10/- *Life Membership 1000/-*

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582

Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011
Ph.: 0712-2533552

New Export Rule Going to be Trust-based Business

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain

kkjain383@gmail.com

The recent government's decision to allow exporters to self-declare origin of goods (certificate of origin or CoO) under the India-EFTA free trade is a significant and genuinely progressive step towards "ease of doing business" for Indian exporters.

The Indian exporters will now be enable to collecting documents, applying for the certificate, and then endlessly waiting for the approval from the authorities before shipping their goods. The move will thus not only save time, effort, and money of our exporters, thus signalling a trust in the export fraternity.

Moreover, the move reflects a broader shift in our trade policy, which is now aimed at reducing compliance and building a trust-based facilitation model that empowers the exporters. New provisions will enable exporters to claim tariff benefits that are available in the FTA signed with an association or union.

With the Indian-EFTA agreement, our exporters will now not only have broader access to key European markets like Norway and Switzerland, but will also benefit from a conducive environment for trade and investment.

These steps may be small, but are significant as they are not only procedural changes. They are in actual fact crucial to build trust among our export community and empower them at the global level. These measures can go a long way in enhancing our nation's competitiveness in global value chains.

This step of self-declaration of origin of goods under the EFTA will pave the way for similar provisions under other Free Trade Agreements (FTAs) as well, thus marking a new dawn built on trust that will enable seamless trade facilitation for Indian businesses.

❑❑❑

ONGC
ENERGY: Now AND Next
Innovating Now
Shaping Next
NET
ZERO
by 2038
Scope-1 and Scope-2
We are ENERGY Now and Next

भारत का भविष्य कॉर्पोरेट्स नहीं, बल्कि लाखों छोटे हाथों में है

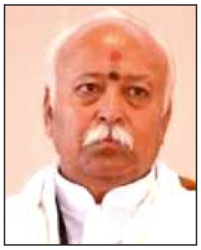

प्रेरक पाथेय
डॉ. मोहनराव भागवत
सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

(लघु उद्योग भारती कर्नाटक स्टेट इकाई की ओर से बेंगलुरु में आयोजित इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो आईएमएस – 2025 के सातवें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के संबोधन का संपादित अंश)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की आर्थिक मजबूती का आधार हैं। देश की अर्थव्यवस्था में लचीलापन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कुछ बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि एमएसएमई सेक्टर में लाखों छोटे हाथों के एक साथ काम करने से उपजी है।

भारत की आर्थिक ताकत कुछ बड़े उद्योगों में नहीं, बल्कि लाखों छोटे हाथों के एक साथ काम करने में निहित है – जब उद्यमी केवल लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करते हैं, तो राष्ट्र, समाज और मानवता सभी की जीत होती है।

एमएसएमई न केवल अर्थव्यवस्था को अचानक बाज़ार में उतार–चढ़ाव या टैरिफ परिवर्तनों जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाते हैं, बल्कि रोज़गार भी पैदा करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं।

पिछले पाँच से दस वर्षों में, भारत का एमएसएमई क्षेत्र लगातार परिपक्व हुआ है और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि ये उद्यम देश के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं।

केंद्रीकृत बड़े पैमाने पर उत्पादन के विपरीत, जो अक्सर रोज़गार कम करता है और निर्भरता बढ़ाता है, एमएसएमई उत्पादन वितरित करते हैं, स्थानीय रोज़गार सृजित करते हैं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दोनों को बढ़ावा मिलता है।

बड़े उद्योगों और छोटे उद्यमों को एक–दूसरे के पूरक होने चाहिए। इससे संतुलित विकास सुनिश्चित होता है और कारीगरों से लेकर उद्योगपतियों तक, उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी हितधारकों को लाभ होता है।

लघु उद्योगों का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था, लघु उद्योग भारती की उद्यमियों के लिए विचारों के आदान–प्रदान, सहयोग और राष्ट्रीय विकास में सामूहिक योगदान के लिए जो एक मंच बनाया, वो प्रशंसनीय है।

भारत के ऐतिहासिक आर्थिक मॉडल का उल्लेख यहां करना आवश्यक है जिसमें 1 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, कृषि, व्यापार और उद्योग एक–दूसरे के पूरक बनकर सामंजस्यपूर्ण रूप से सह–अस्तित्व में थे। खेतों में काम करने वाले मज़दूर, कारखाने के कर्मचारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी एक एकीकृत प्रणाली में भाग लेते थे जिसने समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। हमें आज सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए इस एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण करना होगा।

भारतीय उद्यमिता केवल लाभ से नहीं, बल्कि कर्तव्य, सेवा और सामाजिक कल्याण से प्रेरित होती है। व्यापार और उद्योग को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक प्रगति के लिए भी कार्य करना चाहिए। यह दृष्टिकोण वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता को मज़बूत करता है।

उत्कृष्टता भारत की वैश्विक पहचान का मूल है। हमारे उत्पाद और सेवाएँ उच्चतम मानक की होनी चाहिए। जब हम उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, तो दुनिया इस पर ध्यान देगी और हमारे तरीके दूसरों के लिए एक मानक स्थापित करेंगे। उद्यमियों को छोटी शुरुआत करने लेकिन बड़ा सोचने के लिए भी आवश्यकता है जिससे उनका प्रभाव परिवारों और गाँवों से पूरे राष्ट्र और अंततः मानवता तक फैले।

उद्यमियों की ज़िम्मेदारी और शक्ति–चाहे उन्हें दैवीय या प्राकृतिक रूप से प्रदत्त माना जाए–को पोषित और विस्तारित किया जाना चाहिए।

जब प्रतिस्पर्धा को सहयोग और सामाजिक ज़िम्मेदारी से संतुलित किया जाता है, तो सभी को लाभ होता हैः व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व। एमएसएमई सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र नहीं है; वे वह ताकत हैं जो समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण और लचीले भारत का निर्माण कर सकते हैं, तथा विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मान्य डॉ. कृष्ण गोपाल जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र जी, श्री सांकलचंद बागरेचा जी सहित बड़ी संख्या में कॉरपोरेट हाउस के प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।

❑❑❑

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister
India

Shri Bhajanlal Sharma
Hon'ble Chief Minister
Rajasthan

Shri Rajyavardhan Rathore
Hon'ble Minister for
Industry and Commerce
Rajasthan

Shri K.K. Vishnoi
Hon'ble Minister of State for
Industry and Commerce
Rajasthan

प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस

पर पधारे समस्त प्रवासी राजस्थानी उद्यमी बंधुओं का

सीईटीपी फाउंडेशन, पाली मारवाड़ हार्दिक अभिनन्दन करता है

विकसित भारत-2047 का आह्वान

आत्मनिर्भर बने प्यारा राजस्थान

अशोक लोढ़ा
अध्यक्ष

सूर्यप्रकाश चोपड़ा
सचिव

प्रवीण कोठारी
कोषाध्यक्ष

--- निदेशक मण्डल ---

श्याम अरोड़ा, राजेंद्र भंडारी, अमित गेमावत, जगदीश बोहरा, संदीप मेहता, मोहम्मद सलीम, विनय जैन, महावीर मेहता, रतन मालू, प्रकाश पंवार, रवि मोहन भूतड़ा, कमलेश जैन, किशोर मेहता, नीलेश सेमलानी

सीईटीपी फाउंडेशन (पाली)

संयुक्तजल परिशोधन संयंत्र, मंडिया रोड, पाली मारवाड़-306401 (राज.)
Web: www.cetppali.com / Email : pwpctrf@gmail.com Ph. 02932-230076

मुख्यमंत्री
राजस्थान

मुख्यमंत्री जी री चिट्ठी प्रवासी बंधुओं र नाम...

प्रिय प्रवासी बंधु!

राजस्थान केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध विरासत और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ ये प्रदेश आज विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुका है। इस पहचान के विस्तार और प्रतिष्ठा में हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई–बहनों की भूमिका अत्यंत प्रेरणादायक है। आपने न केवल अपनी कर्मभूमि पर सफलता का परचम लहराया है, बल्कि अपनी मातृभूमि के संस्कारों और मूल्यों को गर्वपूर्वक विश्व भर में प्रतिष्ठित किया है।

राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आपके उत्कृष्ट योगदान और राजस्थान की माटी से आपके अटूट संबंधों को सम्मान देने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस और प्रवासी राजस्थानी सम्मान जैसी अभिनव पहल की गई है।

आपके साथ संपर्क सेतु के रूप में कार्यरत राजस्थान फाउंडेशन के नेटवर्क को विस्तार देने के लिए देश के 14 प्रमुख शहरों के साथ ही न्यूयॉर्क, लन्दन, टोक्यो, सिंगापुर, दुबई, रियाद और काठमांडू जैसे 12 बड़े वैश्विक शहरों में नए चैप्टर्स स्थापित किये हैं। प्रवासियों के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग देने के लिए एक विशेष विभाग का गठन किया गया है। साथ ही, आपकी समस्याओं के समाधान हेतु एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। राजस्थान में आपके परिवारों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

आपके विचार, अनुभव और उपलब्धियां राजस्थान की विकास–यात्रा को नयी दिशा और गति भी प्रदान करती है। आपका योगदान राजस्थान को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक प्रतिष्ठा से संपन्न बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपनी जड़ों, संस्कृति और मातृभूमि से जुड़े रहें और राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाने में राज्य सरकार का सहयोग करें।

शुभकामनाओं सहित,

(भजन लाल शर्मा)

उच्च शिक्षा में प्रगतिशील परिवर्तन और वैश्विक सहयोग

आह्वान
डॉ. प्रेमचंद बैरवा
उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

राजस्थान आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ, सशक्त और भविष्यगामी राज्य बन चुका है। विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले इस प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तृत और विविध ढांचा विकसित हुआ है। वर्तमान में राज्य में 101 विश्वविद्यालय, 665 राजकीय महाविद्यालय और 2570 निजी महाविद्यालय सक्रिय हैं, जहाँ 28 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 28.6 का सकल नामांकन अनुपात (GER) राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि 0.97 का जेंडर पैरिटी इंडेक्स शिक्षा में बढ़ते समावेशन और लैंगिक समानता को दर्शाता है।

पिछले दो वर्षों में सरकार ने उच्च शिक्षा को कमजोर, वंचित, दूरस्थ और आदिवासी समुदायों तक पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 71 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना से हजारों युवाओं को उच्च शिक्षा की प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू करने में भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सेमेस्टर प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में लागू कर दिया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय मूल्य पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाए गए हैं, जिससे शिक्षा आधुनिक होने के साथ सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी हुई है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को 330 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनसे ICT लैब, उन्नत शिक्षण संसाधन, शोध सुविधाओं और सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों का विकास जारी है। रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Apprenticeship Embedded Degree Program प्रारम्भ किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ वास्तविक कार्य अनुभव भी मिलेगा। राज्य में फिनिशिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, जो उद्योग आधारित कौशल और कॉरपोरेट प्रमाणन प्रदान करेंगे। विदेशी भाषा संचार कौशल

योजना के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शुरू कर वैश्विक रोजगार अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही जिला व संभाग मुख्यालयों पर BBA, BCA, MBA और MCA पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

तकनीकी एकीकरण के क्षेत्र में सभी महाविद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा प्रत्येक संभाग में स्मार्ट साइंस लैब स्थापित की गई है। Rising Rajasthan Summit के दौरान उच्च शिक्षा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जो भविष्य में उद्योग सहयोग और कौशल विकास को नई दिशा देंगे। विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्य की दिशा में राज्य स्मार्ट अवसंरचना, उद्योग–अकादमिक सहयोग, शिक्षक सशक्ति–करण, पाठ्यक्रम सुधार और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से उच्च शिक्षा को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इस transformative यात्रा में आपका अब तक का सहयोग प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रहा है।

इसी परंपरा को सुदृढ़ करते हुए, हम आप सभी प्रवासी राजस्थानियों को पुनः सादर आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी मातृभूमि की उच्च शिक्षा प्रणाली से और गहराई से जुड़ें तथा विश्वस्तरीय college buildings, smart classrooms, digital libraries, ICT labs और research centres के निर्माण में योगदान दें। आपकी विशेषज्ञता, निवेश, मार्गदर्शन और सहयोग से राजस्थान न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप सक्षम उच्च शिक्षा अवसंरचना विकसित करेगा, बल्कि 60% GER के लक्ष्य को भी पूर्ण कर सकेगा।

प्रवासी राजस्थानी दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस शिक्षा यात्रा में सहभागी बनें और विकसित राजस्थान @2047 के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। आपका योगदान न केवल उच्च शिक्षा को समृद्ध करेगा, बल्कि राजस्थान के भविष्य को भी नई दिशा देगा।

❑❑❑

मरूधरा की धरा, विश्व पर्यटन का ध्रुवतारा

राजस्थान को आधुनिक, भव्य और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाने का सामूहिक संकल्प

पधारो राजस्थान

दीया कुमारी

उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री,
पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति
राजस्थान सरकार

प्रिय प्रवासी राजस्थानी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा स्नेह, शुभकामनाएं और हार्दिक अभिवादन।

राजस्थान केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि साहस, संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिकता और अतिथि–सत्कार की अनूठी भावना से निर्मित एक समृद्ध सभ्यता है। आज यह प्रदेश वर्षभर चलने वाले ऑल–सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी स्वयं देश के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पर्यटन को राष्ट्रीय विकास की धुरी बना रहे हैं। उनके विज़न के अनुरूप राजस्थान का लक्ष्य है कि 2047 तक हम अपने राज्य को विश्व–स्तरीय, आधुनिक और सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करें।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम पर्यटन के लिए आधुनिक सुविधाओं, ढांचागत विकास, निवेशोन्मुख वातावरण तथा नई नीतियों के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन की नई कथा लिख रहे हैं।

प्रवासी राजस्थानियों का सम्मान-सामूहिक शक्ति का उत्सव

राजस्थान सरकार 10 दिसंबर, 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कर रही है। यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि उन लाखों प्रवासी भाइयों–बहनों की कर्मशीलता, उद्यमिता और मूल्यों का भी सम्मान है जिन्होंने दुनिया भर में राजस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाई।

राजस्थान की मिट्टी में जन्मा हर व्यक्ति परिश्रम, त्याग और अदम्य साहस का प्रतीक होता है। उद्योग–व्यापार, कला–संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप्स या सामाजिक सेवा–हर क्षेत्र पर प्रवासी राजस्थानियों के योगदान ने हमारी परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई है।

हमारी सरकार इस योगदान को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा में आपको सबसे महत्वपूर्ण भागीदार मानती है।

निवेश, नवाचार और सहभागिता-राजस्थान में नए अवसरों के द्वार- राजस्थान आज उद्यमिता के लिए अनुकूल नीतियों और पारदर्शी कारोबारी वातावरण के साथ अग्रसर है।

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति**
- MSME, **स्टार्टअप्स और महिला उद्यमिता को बढ़ावा**
- **परंपरागत कलाओं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहन**
- **आधुनिक कौशल विकास की पहल**

राजस्थान का प्रत्येक जिला अपनी विशिष्ट पहचान, पंच

गौरव और पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ निवेश के नए अवसर प्रस्तुत करता है।

ऑल-ईयर-राउंड टूरिज्म-राजस्थान का नया वैश्विक स्वरूप- राजस्थान आज सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिकता, आधुनिक दृष्टिकोण और इनोवेटिव नीतियों के साथ एक सर्व–ऋतु पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है।

सर्दियाँ - फोर्ट्स, पैलेसेस, हैरिटेज सर्किट, विंटर फेस्टिवल्स, MICE इवेंट्स और अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस–राजस्थान को विश्व पटल पर चमकाने वाले आकर्षण।

गर्मी - डेज़र्ट एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ सफ़ारीज़, माउंट आबू जैसे हिल रिट्रीट्स और शांत झीलों का सौंदर्य–पर्यटकों के लिए अनूठा अनुभव।

मानसून - हरित लैंडस्केप, वाटरफॉल्स, घाटियाँ, क्राफ्ट बाज़ार और सांस्कृतिक महोत्सव–राजस्थान के सौंदर्य का नया रूप।

बॉर्डर टूरिज्म - वीरता, इतिहास और स्थानीय संस्कृति का अद्वितीय संगम।

हाल ही में लंदन के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट–2025 और जयपुर में आयोजित IIFA ने राजस्थान को नई वैश्विक पहचान दी है।

पर्यटन विकास की नई दिशा-परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम - सरकार निवेशोन्मुख, सरल और पारदर्शी माहौल तैयार कर रही है।

- नई राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी
- UD टैक्स में राहत
- Investment - Friendly Reforms

राजस्थान की विविध पहचान को सुदृढ़ करने हेतु-

- महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट
- ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट
- धार्मिक पर्यटन सर्किट– खाटूश्यामजी, पुष्कर, नाथद्वारा, श्री महावीर जी, गलता तीर्थ
- ग्रामीण पर्यटन – होम स्टे, फार्म टूरिज्म, कैरावैन पार्क्स, कैंपिंग साइट्स

उदयपुर को Best Wedding Destination और राजस्थान को Best Cultural Destination का सम्मान मिला है, वहीं जयपुर दुनिया के Top 5 Cities में शामिल हुआ है। यह वैश्विक मान्यता पर्यटन के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण है।

भविष्य की बड़ी पहलें-कन्वेंशन्स, फिल्म पर्यटन और ट्रेवल मार्ट्स- नई पर्यटन नीति और नई फिल्म नीति राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई दिशा देंगी। कोटा–हाड़ौती ट्रेवल मार्ट (2–4 जनवरी, 2026) कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां की अनूठी विरासत प्रस्तुत करेगा। बढ़ती पर्यटक संख्या यह दर्शाती है कि राजस्थान आज यात्रियों की पहली पसंद बन चुका है।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष संदेश-आप ही हमारी धरोहर के वैश्विक दूत- उद्योग टाइम्स के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ–

राजस्थान की इस नई प्रगति यात्रा का सक्रिय हिस्सा बनें। अपने अनुभव, विशेषज्ञता, निवेश, नवाचार और प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ के युवाओं, उद्यमियों, कारीगरों और संस्कृति–धरोहर के संरक्षकों को सशक्त करें।

आप पूरे विश्व में राजस्थान की संस्कृति, मूल्यों और उद्यमिता के प्रतिनिधि हैं। आपकी ग्लोबल रीच और आपका अनुभव राजस्थान के पर्यटन को विश्व का सिरमौर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रवासी राजस्थानी मिलकर मरूधरा की इस महान धरती को आधुनिक, भव्य और विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

राजस्थान बुला रहा है - आइये, अपनी मातृभूमि की इस परिवर्तन यात्रा में सहभागी बनिए।

□□□

राजस्थान बना निवेश के लिए पहली पसंद

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
कैबिनेट मंत्री,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
राजस्थान सरकार

सम्माननीय प्रवासी बंधुगण! राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में उद्योग लगाने की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान, तेज़ और भरोसेमंद हुई है। अब निवेशकों को जमीन, अनुमति और अन्य सुविधाएँ बिना परेशानी, कम समय और एक क्लिक में मिल रही हैं। इसी कारण राजस्थान आज देश और दुनिया के निवेशकों की नई पसंद बन चुका है। बीते वर्ष निवेश प्रयासों में 32 देशों ने ₹35 लाख करोड़ के निवेश समझौते किये, 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए, 1952 औद्योगिक प्लॉट के साथ 3100 से अधिक MSMEs को सहायता मिली।

उद्योग लगाने की प्रक्रिया में बदलाव से अब जमीन का आवंटन ऑनलाइन होता है, MSME को 30 दिनों में मंजूरी मिलती है और देरी होने पर अनुमति अपने आप मंजूर मानी जाती है। फ़ैक्टरी और बॉयलर की अनुमति भी ऑनलाइन है और 10 कर्मचारियों तक दुकान खोलने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहती।

उद्योगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने 6 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में फायर टेंडर की सुविधा दी है। 281 किमी. लाइन अपग्रेडेशन, 210 किमी अंडरग्राउंड केबलिंग, 5845 स्ट्रीट लाइटें और औद्योगिक ढाँचे पर ₹2777 करोड़ का निवेश से उद्योगों को बिजली और सुरक्षा सुनिश्चित की है।

कई पुराने और बेकार नियम हटाए गए हैं। 877 उद्योगों को पर्यावरणीय अनुमति से छूट दी गई, 45 पुराने कानून समाप्त किए गए और अब जमीन की जानकारी ऑनलाइन नक्शे पर तुरंत दिखाई देती है। शिकायत भी ऑनलाइन तुरंत ट्रैक हो जाती है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान ने "Minimum Government, Maximum Governance" और "Maximum Transparency, Maximum Trust" को हकीकत में बदल दिया है। सरल प्रक्रियाओं, तेज़ मंजूरियों और सुरक्षित वातावरण के साथ राजस्थान आज साफ संदेश दे रहा है –राजस्थान is Open for Business, और आने वाले समय में राजस्थान भारत की उद्योग क्रांति में अहम भूमिका निभाने जा रहा है।

□□□

विकसित राजस्थान के निर्माण का लें संकल्प

के. के. बिश्नोई
राज्य मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य
राजस्थान सरकार

प्यारे प्रवासी बांधवजन, आपकी अपनी मायड़ धरा पर स्वागत!

अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हम 10 दिसम्बर, 2025 को प्रथम "प्रवासी राजस्थानी दिवस" के ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, राज्य को निवेश, उद्योग, नवाचार, पर्यटन, कौशल विकास और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य की ओर तेज गति से अग्रसर है। लगभग दो वर्ष के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने 23 नई नीतियों को लागू किया है और 13 नई नीतियाँ लागू करने की प्रक्रिया में हैं। ये नीतियाँ लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी, डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, सिविल एविएशन, माइनिंग, AVGC-XR, स्किल डेवलपमेंट जैसे उभरते क्षेत्रों को नई दिशा दे रही है।

क्लीन और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, डिफेंस एवं ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिल्म टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इको–टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं।

आज राजस्थान न केवल निवेश के लिए सुरक्षित प्रदेश बना है, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 7 लाख करोड़ रुपए के MOU का ग्राउंड ब्रेकिंग किया जा चुका है। इन MOUs में से लगभग 1400 करोड़ रुपए के 20 MOUs में विदेशी निवेश है। जो राजस्थान के निवेश अनुकूल वातावरण को दर्शाता है। ये निवेश रिन्यूएबल एनर्जी, खनन, पर्यटन, कृषि और कृषि–प्रसंस्करण, मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और विद्यालय शिक्षा, सिविल एविएशन जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। इन सभी उपलब्धियों के केंद्र में है, Ease of Doing Business, पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज निर्णय क्षमता।

यह गर्व का विषय है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान को Ease of Doing Business में 'Top Achiever State' से नवाज़ा है। यह उपलब्धि ई–गवर्नेंस, पारदर्शी प्रक्रियाओं और प्रभावी मॉनिटरिंग का परिणाम है। राजस्थान आपसे जुड़े बिना पूर्ण नहीं। आपका ज्ञान, आपकी वैश्विक दृष्टि, आपका अनुभव और आपकी उद्यमशीलता राजस्थान की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आइए, विकसित राजस्थान के निर्माण में साझेदारी करें।

□□□

राजस्थान के औद्योगिक विकास को समर्पित 'प्रवासी दिवस'

अविनाश गहलोत
मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
राजस्थान सरकार

सभी प्रवासी बंधुओं का सादर अभिवादन।

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार 10 दिसंबर, 2025 को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस पर जयपुर में दुनियाभर के प्रवासियों का सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस विशेष अवसर पर जिन प्रवासियों ने सामाजिक सरोकारों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जायेगा। इस अभिनव कार्यक्रम में अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित भारत के भी विविध प्रांतों से बड़ी संख्या में सफल प्रवासी उद्यमी एक साथ आ रहे हैं। भारत सरकार के "विकसित भारत–2047" के संकल्प को देखते हुए राज्य सरकार भी राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित कर, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के सार्थक प्रयासों से समस्त भारत एवं विदेशों में रहने वाले प्रवासियों एवं प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में निवेश की सरल एवं सुगम विधि अपनायी गई है जिसमें एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाएं (Single Window) प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'वोकल फॉर लोकल' का जो प्रेरक संदेश पूरे देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने के लिए ही प्रवासी राजस्थानी उद्यमी अपने प्रदेश में निवेश कर न केवल विश्वस्तरीय उत्पाद बनाएंगे, बल्कि रोजगार सृजन कर यहां की कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेंगे।

प्रदेश में गरीबों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनेक प्रकार के व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं तथा राज्य के समस्त वृद्धजनो, दिव्यांगजनों, अनु.जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और अति पिछड़ा वर्ग को पेंशन, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रदान की जा रही है।

लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय पत्रिका ने प्रवासी दिवस पर जो उपयोगी विशेषांक प्रकाशित किया है, उसके लिए संगठन साधुवाद का पात्र है।

□□□

उद्योग उत्थान से प्रदेश और राष्ट्र की प्रगति के वाहक बनें राजस्थानी

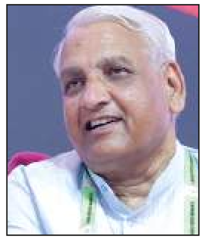

प्रकाश चंद्र
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री
लघु उद्योग भारती

लघु उद्योग भारती

प्रवासी राजस्थानी दिवस पर जयपुर पधारे सभी उद्यमी बंधुओं का उनकी धरा पर अभिनन्दन।

राजस्थान और यहां के उद्यमियों को विश्वभर में आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपनी उद्यमिता और कर्मठता के बल पर अपना स्वयं का परिचय गढ़ा है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में उद्योगों में तकनीक और नवाचार की भूमिका बढ़ गई है। पारम्परिक उद्योगों के साथ नए उद्योगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कम कीमत में गुणवत्तापरक उत्पाद के लिए रणनीतिक प्रबंधन और कुशल कार्मिकों का कौशल दोनों आवश्यक हैं। लेकिन रोजगार सृजन उद्योग की स्थापना के मूल में होना चाहिए। आपके उद्योग प्रदेश में लगें, तो यहां के युवाओं को भी उनकी गुणता और क्षमता के हिसाब से रोजगार के अवसर मिलें। ये उद्देश्य भी हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होना चाहिए।

लघु उद्योग भारती ने विगत तीन दशकों में एमएसएमई सेक्टर के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए अथक परिश्रम कर उन्हें स्थापित किया है। राजस्थान में भी अधिकांश उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं जहां रोजगार भी सृजित होता है।

उद्योगों में तकनीक के अधिक समावेश और उनके नित–नए मॉडल आने से उनके उचित संचालन और मेंटेनेंस की भी नई चुनौती उद्योगों के समक्ष आ रही है। इसके लिए कौशल युक्त कार्मिकों (Skilled Workforce) की बड़ी संख्या में आवश्यकता है जिसके लिए लघु उद्योग भारती ने राजस्थान में पाली, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के माध्यम से महिलाओं और युवकों को विभिन्न ट्रेड में कौशल युक्त बनाया है, जिससे राजस्थान में लगने वाले उद्योगों की इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा सके।

अपनी मातृभूमि से सतत संपर्क और जुड़ाव का इससे बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं कि यहां आप उद्योग लगाएं और प्रदेश की प्रगति में सीधे भागीदार बनें।

आपकी सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।

□□□

सुत न..... मायड़ हेलो मारे रे!

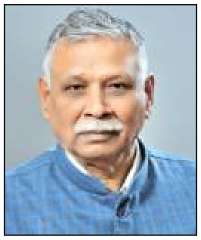

योगेंद्र शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती,
राजस्थान

लघु उद्योग भारती

परम आदरणीय प्रवासी बंधुओं!

सादर सप्रेम वंदन!

देश ही नहीं, विश्व के सुदूर स्थानों पर, राजस्थान के पुत्रों ने जो यश, संपदा और सम्मान अर्जित किया है, इसका शायद ही विश्व में कोई अन्य बराबरी करने वाला होगा। इस सुंदर माथे पर तिलक इस बात से लगता है कि पीढ़ियों से देस से दूर रह रहे आप सभी ने देस की भाषा, देस का भोजन, देस की संस्कृति को बिसराया नहीं!

आज भी चिक पेट (बंगलुरु) या साहूकार पेट (चेन्नई) की गलियों में, या नलबाड़ी (आसाम) के पर्वतों में केर–सांगरी और गट्टे की सब्जियां रसोई में महकती हैं, तो एक बार हींवड़े में टीस सी पैदा कर देती है। बड़ा बाजार कलकत्ते में कुछ समय पहले तक रंगीन पगड़ियाँ और काली टोपियाँ, अपनी थाती से जुड़े देसियों का गर्विला परिचय होता था।

आज भी बजाज, खेतान, अग्रवाल, बिड़ला, गोयनका, सिंघानिया, मित्तल और भी कई, इस भूमि के सुपुत्रों के गौत्र नहीं, वरन् पताकाएँ हैं जो इस भू के कोने कोने पर फहरा रही हैं। आप देस से दूर हुए। वह एक समय की मजबूरी थी। लेकिन समय ने फिर करवट ली है। दोनों हाथ पसारे मायड अब आपको अपनी छाती से लगाने की बाट जोह रही है।

आप अपने देस आयें – अपने उन बच्चों को अवश्य लायें जिन्होंने शायद इसे सुना ही है, इसकी मिट्टी को कभी सूंघा नहीं, न इसकी धरती का पानी पिया।

आप अपने देस आयें – अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए, दादो सा और दादी सा की स्मृतियों के लिए। और अगर आपको यहाँ की गलियों में कभी घोड़ा पछाड़ या सतौलिया खेलने का सौभाग्य मिला, तो उसके लिए।

आप देस आएं – क्यूंकि आप देस से भले दूर हुए हों, देस कभी आपसे दूर नहीं हुआ। अतः आप सभी बंधुओ से विनम्र निवेदन है कि आप अपने निवेश द्वारा राजस्थान के साथ सजीव संपर्क बनावे !

इसी अपेक्षा एवं आकांक्षा के साथ

पधारो थारे देस रे!

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा दपि गरीयसी।।

LUB proudly participated in the MoU signing ceremony between Government e-Marketplace (GeM) and the United Nations at New Delhi on 20th Nov. Shri Anurag Awasthi, Chief Manager, GeM and Shri Ajit B. Chavan, CEO, Shri Janak Bhatia, Joint National Treasurer, and Smt. Aarti Sehgal, General Secretary LUB Delhi were present. The discussions reaffirmed a shared commitment towards empowering MSMEs and enhancing their participation in global procurement platforms.

इंडिया स्टोनमार्ट-2026 की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित

इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की तैयारियों को लेकर प्रबंध निदेशक, RIICO की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव श्री नरेश पारीक, संयोजक इंडिया स्टोनमार्ट श्री नटवरलाल अजमेरा, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अंजू सिंह, उपाध्यक्ष श्री महेंद्र खुराना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (CDOS) से उपाध्यक्ष श्री दीपक अजमेरा, सीईओ श्री मुकुल रस्तोगी, गवर्निंग बोर्ड मेंबर श्री राजेश मित्तल एवं श्री ललित आहूजा तथा श्री विवेक जैन ने भाग लिया।

रीको एमडी ने अंतरराष्ट्रीय स्टोन एसोसिएशनों की भागीदारी, ब्रांडिंग, वैश्विक प्रमोशन विज़िट फीडबैक, अवसंरचना प्रबंधन, रोड शो कार्यक्रम, और प्रचार–प्रसार गतिविधियों की समीक्षा की। चीन, तुर्किये सहित कई देशों से पवेलियन और ट्रेड डेलिगेशन को लेकर भी सकारात्मक रिपोर्ट साझा की गई। गौरतलब है कि कुल प्रदर्शनी क्षेत्र का 72 प्रतिशत भाग यानी 18,000 वर्ग मीटर बुक हो चुका है।

राजस्थान सरकार

जयपुर विकास प्राधिकरण

आधुनिक और तेज विकास

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

शिलान्यास ₹320 करोड़

एलिवेटेड रोड

गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थडी के पास तक एलिवेटेड रोड का निर्माण।	21885.20 लाख

सीवरेज कार्य

जोन–पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) क्षेत्र से लगते हुए सांगानेर क्षेत्र जोन–2 में स्वर्ण विहार एसटीपी के अन्तर्गत सीवर लाईन बिछाने का कार्य।	3096.00 लाख
जोन–पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) क्षेत्र से लगते हुए सांगानेर क्षेत्र जोन–3 में स्वर्ण विहार एसटीपी के अन्तर्गत सीवर लाईन बिछाने का कार्य।	2120.00 लाख
सांगानेर के बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य हेतु मुख्य ट्रंक लाईन (पार्ट–1) बिछाने का कार्य।	3007.00 लाख

सड़क निर्माण कार्य

वंदे मातरम सड़क गोपालपुरा बाईपास से पत्रकार रोड जंक्शन तक सड़क सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य	1172.92 लाख
जोन–11 क्षेत्र में अजमेर रोड से जयसिंहपुरा रोड वाया 200 फीट सेक्टर रोड पर ड्रेन का निर्माण कार्य।	339.64 लाख
जोन–8 क्षेत्र में इस्कॉन रोड पर मीडियन रेलिंग तथा सड़क के दोनों और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य।	284.11 लाख
जोन–11 क्षेत्र के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मदरामपुरा कच्ची बस्ती जविप्रा स्कीम में मुख्य अप्रोच रोड एवं अन्य आंतरिक रोड निर्माण कार्य।	122.89 लाख

लोकार्पण ₹130 करोड़

सीवरेज कार्य

(अ) पैकेज–I फेज–II के तहत	2847.00 लाख
(ब) पैकेज–III फेज–II	2503.00 लाख
(स) पैकेज–II फेज–II	1571.00 लाख

रोडकट का मरम्मत कार्य

जोन–8 क्षेत्र में बीसलपुर जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क हेतु रोडकट का मरम्मत कार्य।	1122.13 लाख
जोन–8 क्षेत्र में बीसलपुर पाईप लाईन के लिए पीएचईडी द्वारा की गई सड़क का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य (फेज–द्वितीय) पार्ट–प्रथम।	538.47 लाख
जोन–8 क्षेत्र में बीसलपुर पाईप लाईन के लिए पीएचईडी द्वारा की गई सड़क का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य (फेज–प्रथम)।	519.87 लाख

अन्य विकास कार्य

जोन–8 क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रीकास्ट आरसीसी कर्ब स्टोन और इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य	108.67 लाख

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
श्री भजनलाल शर्मा जी
के कर कमलों द्वारा
विकास कार्यों का
लोकार्पण एवं शिलान्यास
किया गया।

सेक्टर सड़कों / आंतरिक सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

जोन–8 क्षेत्र में 200 फीट सेक्टर रोड से 160 फीट सेक्टर रोड मुहाना मण्डी रोड तक एवं 200 फीट सेक्टर रोड से मांग्यावास सर्किल 220 केवी एच टी लाईन तक का 200 फीट सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	781.03 लाख
जोन–पीआरएन (साउथ) क्षेत्र में सेक्टर एच की आन्तरिक सड़कों पर बीसलपुर पाइप लाइन के लिए पीएचईडी द्वारा किए गए सड़क कट का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य।	629.00 लाख
जोन–8 क्षेत्र में पीआरएन 200 फीट सेक्टर रोड से 200 फीट सेक्टर रोड को जोड़ने वाली 100 फीट सेक्टर सड़क, 100 फीट सेक्टर रोड से जोन–8 बाउंड्री को जोड़ने वाली 100 फीट सेक्टर सड़क एवं केसर चौराहे से 200 फीट रोड को जोड़ने वाली 80 फीट सेक्टर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	645.20 लाख
जोन–पीआरएन (दक्षिण) क्षेत्र में सेक्टर–एच, आई व जे की अनुमोदित कॉलोनियों में आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य।	439.80 लाख
जोन–8 क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर सड़कों का नवीनीकरण कार्य।	378.96 लाख
जोन–पीआरएन (दक्षिण) क्षेत्र में न्यू सांगानेर रोड से बाबा पैराडाइज तक 100 फीट चौडी सेक्टर सड़क का निर्माण कार्य।	215.28 लाख
जोन–पीआरएन (दक्षिण) क्षेत्र में छूटी / शेष सेक्टर सड़कों एफ–8, ई–12 एवं डी–16 सड़कों का निर्माण कार्य।	213.21 लाख
जोन–11 क्षेत्र में गणपतपुरा में सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	151.33 लाख
जोन–11 क्षेत्र में सी.सी एव बी.टी सड़क का नवीनीकरण का कार्य अजमेर रोड के पास ।	151.34 लाख
जोन–8 क्षेत्र में मोती नगर से रामपुरा फाटक वाया दादूदयाल नगर एवं कल्याणपुरा सरकारी स्कूल तक सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य ।	84.50 लाख
जोन–8 क्षेत्र में सांगानेर स्टेडियम से जयपुर नगर निगम ग्रेटर सांगानेर कार्यालय तक 80 फीट सड़क का नवीनीकरण कार्य।	86.90 लाख

राजस्थान संवाद

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004

निवेश के लिए प्रवासियों का दिल जीतने का जतन

सरकार के तंत्र के पास ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे वे अपनी मेहनत, लगन और इससे अव्वल राजस्थान और अपने दायित्व के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा से स्वर्णिम अवसर में बदल सकते हैं।

प्रवासी
डॉ. संजय मिश्रा
को-एडिटर
उद्योग टाइम्स
dr.sanjay.jpr@gmail.com

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एक वर्ष के बाद प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के उत्सव को आयोजित करने के लिए प्रदेश की राजधानी जयपुर एक बार फिर तैयार है। प्रवासियों के लिए दिवस की घोषणा राइजिंग राजस्थान के समय प्रदेश के मुखिया श्री भजनलाल शर्मा ने की थी। वास्तव में ये आयोजन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देश दुनिया से हजारों राजस्थानी केवल ये देखने और समझने आ रहे हैं कि आखिर यहां की सरकार और यहां के तंत्र में इस मरुधरा को विकसित करने की कितनी लगन और आग बाकी है।

राजस्थान में निवेश का नया दौर

सदियों से राजस्थान की गौरवशाली धरा की पहचान संस्कृति, शौर्य और परंपराओं की भूमि के रूप में रही है। आज वही धरती मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निवेश और विकास की स्थली के रूप में पहचान बना रही है। राजस्थान सरकार के निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है, जिससे

''हमने विजन डॉक्यूमेंट–2047 को मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने''।

प्रवासी राजस्थानी समुदाय अपनी मातृभूमि के विकास में भागीदार बनने के लिए आगे आ रहा है। प्रवासी राजस्थानियों ने देश और दुनिया को अपनी कर्मभूमि बनाकर अपने संकल्प, श्रम और बुद्धिमता से हर क्षेत्र में नाम कमाया है। आज राजस्थान ऐसे कर्मवीरों को अपने संचित ज्ञान, अनुभव और पूंजी का निवेश करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः जुड़ने का अवसर उपलब्ध करवा रहा है।

विश्व के निवेश मानचित्र पर उभरता प्रदेश

पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने राजस्थान की आर्थिक यात्रा में नया इतिहास रच दिया। समिट के दौरान लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह किसी भी राज्य के लिए असाधारण उपलब्धि है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात

यह है कि इनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो चुका है। यह सिद्ध करता है कि सरकार के इरादे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली विकास योजनाओं में बदल रहे हैं।

मोदी की गारंटी-भजनलाल का भरोसा

राइजिंग राजस्थान समिट में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम में जान फूंक दी थी। मोदी वैश्विक स्तर पर लीडरशिप के उस पायदान पर पहुंच चुके हैं, जहां से वो जिस विषय पर अपील करते हैं, उसका असर बहुत दूर तक होता है। इस बात को भजनलाल भी जानते थे और उन्होंने आग्रहपूर्वक प्रधानमंत्री को जयपुर बुला ही लिया।

श्री नरेंद्र मोदी ने समिट के उद्घाटन सत्र में जो अपना भाषण दिया, उसे सुनकर तो राजस्थान के राजनेता और नौकरशाह दोनों ही अवाक रह गए। मोदी ने धाराप्रवाह राजस्थान के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यटन और विरासत पर जो बोलना शुरू किया, उसने इतनी गहराई से लोगों को कनेक्ट किया, कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का उस समिट से जुड़ना ही उसकी सफलता बन गया। बीसियों देशों के निवेशकों ने राजस्थान में किसी भी एमओयू को साइन करने से पहले सिर्फ एक चेहरा देखा –प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी के व्यक्तित्व के तिलिस्म ने ही वाइब्रेंट गुजरात को सफल बना दिया था। ये है मोदी की गारंटी।

दूसरी ओर प्रवासी दिवस की घोषणा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देस और परदेस में बसने वाले लाखों राजस्थानियों के दिलों को जीतने की कोशिश की है। बेशक, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे धाराप्रवाह न बोल पाते हों या सूबे के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्रियों जैसे लच्छेदार भाषण भी न कर पाते हों, लेकिन बीते दो वर्षों में उन्होंने अपनी सादगी और सटीक नीति से जनमानस को प्रभावित किया है। उन्होंने अफसरों, संगठन और सत्ता से जुड़े अन्य लोगों को साथ लेकर काम करने की कोशिश की है और उससे एक भरोसा पैदा हुआ है जो सफल प्रवासी दिवस के रूप में परिलक्षित होगा। पहले वर्ष के राइजिंग समिट ने पहले के सभी निवेश शिखर सम्मेलनों को पीछे छोड़ा था, अब प्रवासियों की संख्या का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। . परिणाम कुछ भी हो, प्रदेश के मुखिया ने प्रवासियों के मन में हलचल तो पैदा कर ही दी है।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए अभूतपूर्व पहल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों की ऊर्जा और अनुभव को प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं–

राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर सक्रिय–

मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय से राजस्थान फाउंडेशन के जरिए जुड़ने की कोशिश की है। राजस्थान फाउंडेशन के देश में 14 प्रमुख शहरों के साथ ही न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिंगापुर, दुबई, रियाद, काठमांडू जैसे दुनिया के 12 बड़े शहरों में चैप्टर स्थापित किए गए हैं। मार्च 2001 में राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चैप्टरों की कार्यकारिणी का गठन और अनुमोदन किया गया है।

समस्याओं के समाधान हेतु नया पोर्टल–

सरकार ने एक डिजिटल पोर्टल (https://rajnivesh. rajasthan. gov.in/) बनाया है, जिससे प्रवासी आसानी से अपनी समस्याएं, सुझाव और निवेश संबंधी जानकारी साझा कर सकते हैं।

विशेष विभाग का गठन–

प्रवासियों के लिए एक विशेष विभाग एक ऐसा मंच है, जो प्रवासी राजस्थानियों के व्यावसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग प्रदान करेगा। यह उनकी हर छोटी–बड़ी जरूरत और योजना के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करेगा।

प्रवासी राजस्थानी सम्मान–

प्रदेश सरकार अब हर वर्ष उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित करेगी। यह न केवल गौरव का अवसर है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम भी बनेगा।

हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट–

राजस्थान में बसे प्रवासियों के परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट स्थापित कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही, एक डैशबोर्ड बनाया गया है ताकि प्रवासी अपने पैतृक गांवों एवं शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल–संचय और आधारभूत ढांचे के विकास और निवेश संबंधी कार्य चुनकर योगदान दे सकें।

हर वर्ष मनेगा प्रवासी राजस्थानी दिवस–

मुख्यमंत्री शर्मा की घोषणा के अनुसार अब हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस एक भव्य उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य और जल संचयन जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता का फायदा प्रदेश को मिल सके। इस आयोजन के लिए हैदराबाद, सूरत, कोलकाता और अन्य शहरों में विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित कर प्रवासियों को आमंत्रित किया गया है।

राजस्थान सरकार का यह प्रयास सिर्फ आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और समावेशी दृष्टि का प्रतीक है। 10 दिसंबर का दिन अब प्रवासी राजस्थानियों को उनकी जड़ों से जोड़ने का पर्व होगा। एक ऐसा अवसर, जहां विचार, अनुभव और निवेश मिलकर नए राजस्थान की नींव मजबूत करेंगे। प्रदेश सरकार ने जो वातावरण बनाया है, वह आने वाले वर्षों में राजस्थान को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

उद्यमी सरकार से सस्ती जमीन, सस्ती बिजली, व्यापार में आसानी, एकल खिड़की, बेहतर इंफ्रा हर चीज का एश्योरेंस मांगता है, लेकिन इसके बदले में जो वो एश्योरेंस करता है, उसे पूरा करना भूल जाता है। इसे उद्यमी या वो कंपनी ही नहीं भूलती, बल्कि सिस्टम में बैठे वो लोग भी भूल जाते हैं, जिनके ऊपर उसकी पालना करवाने का दायित्व भी है।

राजस्थान के भीलवाड़ा में जिंदल शॉ लिमिटेड का ऐसा ही एक उदाहरण है। कंपनी को वर्ष 2007 में माइनिंग लीज इस शर्त पर दी थी कि ग्रुप वहां स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। लेकिन अपना वादा भूल कर लोह अयस्क (Iron Ore) का निर्यात करने लगा। आज तक उद्योग पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे प्रदेश को दो नुकसान हुए, पहला–रोजगार सृजन नहीं हुआ और दूसरा– उत्पादन से जो राजस्व प्रदेश को मिल सकता था उसका भी नुकसान हुआ।

बदली-बदली सी ब्यूरोक्रेसी

राजस्थान में जितना निवेश आना चाहिए था बीते बरसों में, उतना आया नहीं। करोड़ों रुपये बिग फोर कंपनियों या अन्य कंसल्टेंसी एजेंसियों से सरकारी योजनाओं के ड्राफ्ट बनाने और आंशिक रूप में उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के नाम पर खर्च कर दिए गए। उन योजनाओं को प्रचारित भी किया गया, लेकिन उससे आकर्षित होकर निवेश धरातल पर नहीं आया।

सरकारें आती–जाती रहीं, सरकार के मुखिया बदलते रहे, दो–दो, तीन–तीन बार एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक दलों ने रिपीट भी किया, लेकिन उनका ओरिएंटेशन उद्योगों के विकास पर था ही नहीं। रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो उसने कभी अपने तौर–तरीकों को बदलनेकी कोशिश ही नहीं की। इसीलिए प्रदेश के साथ निवेश के मामले में न्याय नहीं हो सका। गाहे–बगाहे इस सबके पीछे नौकरशाही पर उंगलियां उठती रही। ये माना जाने लगा कि किसी भी उद्योग के लगने में हो रही अनावश्यक देरी या उनके नहीं लगने के पीछे ये ही जिम्मेदार रहे हैं। और ये बात दुनियाभर में और अन्य राज्यों में यहां से गए हुए प्रवासी राजस्थानी कहते भी हैं। उनके मन में दर्द भी है कि वे अपनी जन्मभूमि या अपने पुरखों की भूमि पर अपना कोई उद्योग नहीं लगा पाए, जो उनके लिए यहां सबसे बड़ा जुड़ाव का सबब बनता। जब भी नौकरशाही के रवैये को लेकर कोई बात भी उठती है, तो उनके ट्रांसफर कर दूसरे विभागों में पोस्टिंग दे दी जाती है।

लेकिन बीते दो वर्षों में नौकरशाही में आंशिक बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्हें इस बात का इल्म होने लगा है कि सरकार में शीर्ष पर बैठे लोग उनसे जिस दिन सवाल पूछना शुरू करेंगे और उनके काम की समीक्षा होना शुरू होगा, तो उस दिन उनके पास भी बहुत ज्यादा एक्सक्यूज़ नहीं होंगे। उन्हें अपनी नाकामी को स्वीकार करना होगा और अपने व्यवहार में और अधिक पेशेवर क्वालिटीज़ को शामिल करना होगा। इस बात को यहां इसलिए भी कहना जरूरी है कि विकसित भारत–2047 के मिशन को साकार करने में राजस्थान प्रदेश कितना सफल हो सकेगा, और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में किस ब्ल्यू प्रिंट को काम में लेगा, इसका दिग्दर्शन जन–मन में कराया जाना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रतिबद्ध पब्लिक सर्वेंट्स यानी जन सेवक चाहिए, बड़े हाकिम नहीं।

बीआईपी की समीक्षा जरूरी

बीआईपी (ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन), जो प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और उसे जमीन पर उतारने के लिए उत्तरदायी एजेंसी है, की स्थापना और उसमें काम कर रहे लोगों की चयन प्रक्रिया ही विवादों में रही है। अपना रसूख इस्तेमाल कर कई लोगों ने बैक डोर एंट्री यहां ली थी। यहां पर काम कर रहे कार्मिकों की कार्यशैली और उनके कार्यों (KRA- Key Responsibility Area) की समीक्षा की जानी बहुत जरूरी है। बीआईपी में और अधिक सक्षम, संवेदनशील, अनुभवी और उत्तरदायी प्रोफेशनल्स को जोड़े जाने की जरूरत है जो न केवल रिजल्ट ओरिएंटेड हों, बल्कि वे यहां पारदर्शी व्यवस्था को कायम करने में सफल हो भी सकें। हाल ही में एक युवा ब्यूरोक्रेट को कमिश्नर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, ये अच्छी बात है लेकिन बीआईपी की कल्चर को वो कितना बदल पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है।

डायमेंशन स्टोन पर सरकार कब डेडिकेटेड स्कीम बनाएगी ?

देशभर में ग्रेनाइट, सैंड स्टोन और मार्बल के कुल उत्पादन

का 65 प्रतिशत तो केवल राजस्थान के खाते में जाता है। इतना होने पर भी डायमेंशन स्टोन की डेडिकेटेड स्कीम बनाने की यहां की सरकार ने कोई जहमत नहीं उठाई। इसी तरह से प्रोसेसिंग मशीनरी का उत्पादन करने वाला भी राजस्थान ही है सबसे अग्रणी देश में। उसके लिए भी कोई अलग से योजना नहीं उपलब्ध है। करीब 700 करोड़ रॉयल्टी केवल डायमेंशन स्टोन से ही मिल जाती है। देशभर में जितने पुराने ऐतिहासिक भवन, मंदिर (राममंदिर) और सरकारी कार्यालय और निवास (राष्ट्रपति भवन) हैं, वे राजस्थानी पत्थर से ही निर्मित हैं।

राजस्थान में टाइल्स हब कब बनेगा ?

गैस की अनुपलब्धता का झूठ किसने फैलाया ?

गुजरात के मोरबी इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हम बरसों से ये सुन रहे हैं कि टाइल्स हब कहलाने वाले इस मोरबी को रॉ मटेरियल राजस्थान से ही जाता है। जब लोग पूछते हैं कि प्रदेश में टाइल्स हब बनाने के प्रयास क्यों नहीं हुए, तो जवाब आता है कि इस उद्योग में गैस भी रॉ मटेरियल ही माना जाता है और प्रदेश में प्रचुर मात्रा में गैस की उपलब्धता नहीं है। ये मिथ है और वास्तविकता नहीं है। राजस्थान में इतने वर्षों से गैस का उत्पादन हो रहा है, रागेश्वरी गैस फील्ड बाड़मेर और जैसलमेर में भी फोकस एनर्जी इस काम को कर रही है। 4 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस अभी वहां निकल रही है, उसमें से कुछ यहाँ कंज्यूम हो रही है और बाकी करीब 70 फीसद तो गुजरात ही सप्लाई हो रही है, तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है।

एग्रो फूड पॉलिसी की कमजोर पहल से गुजरात की मंडी पर राजस्थान की कैश क्रॉप आश्रित क्यों ?

जीरा, इसबगोल, सफ़ेद मूसली, गुग्गल आदि वे कैश क्रॉप हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान अव्वल है लेकिन इन्हें बेचने के लिए गुजरात की ऊंझा की मंडी में जाने की क्या मजबूरी रही है। यहीं नहीं, यहाँ से पैकेजिंग कर इन्हें दुनियाभर में निर्यात करने का काम भी गुजरात की यही मंडी करती है।

ऑयल मिलिंग ज़ोन की जरूरत

ऑयल सीड्स के उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पर है 60 प्रतिशत सरसों का तेल ही प्रयोग में लाया जाता है, इसके बावजूद कोई मिलिंग जोन नहीं है, डेडिकेटेड ऑयल इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। राज्य की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कमजोर है।

माइनिंग इंडस्ट्रियल जोन आटे में नमक के बराबर

राजस्थान में मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट्स ब्यावर और किशनगढ़ में लगी हैं, उनके लिए माइनिंग ग्राइंडिंग ज़ोन रीको ने बनाए हैं लेकिन ये नाकाफी हैं।

देश–विदेश में राजस्थानी प्रवासियों ने अपने उद्यम कौशल से अपनी पहचान बनाई। लेकिन वे अपनी मातृभूमि पर निवेश से वंचित रहे। ये यक्ष प्रश्न हर उस व्यक्ति को दंश करता है जो इस धरती से प्रेम करता है और उसे भी जो किसी कारण से दूर परदेस में गए और उसे अपनी कर्मभूमि बनाया। लेकिन पीढ़ियों से वहां रहने के बाद भी उनका जुड़ाव अपनी मातृभूमि के साथ हमेशा बना रहा। यही कारण है कि प्रवासी बंधु अपनी धरती से निवेश के माध्यम से जुड़ रहे हैं ।

अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहता है !

भारत के मैनचेस्टर कहलाने वाले अहमदाबाद में राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष और अग्रणी उद्यमी श्री महेंद्र लोढ़ा बताते हैं कि इस बार सरकार जितनी आतुर है प्रवासियों को बुलाने के लिए, उससे अधिक आतुर हैं प्रवासी यहां आने के लिए। कौन है जो अपना घर छोड़कर जाना चाहता है। अपनी जमीन से अटैचमेंट तो होता ही है। इस बारे में वे अपनी भावना भी व्यक्त नहीं कर सकते। कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है, राजस्थानियों के खून में उद्यमिता होती ही है। तो वे हर जगह जाते हैं और अपनी सोच और कर्म से अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं।

ख्यातिलब्ध पूर्व न्यायाधिपति श्री गुमानमल जी लोढ़ा के सुपुत्र श्री महेंद्र याद करते हैं वर्ष 1981 को, जब वे जोधपुर से अहमदाबाद कोई उद्योग लगाने आये थे और समय बहुत तेजी से निकल गया। आज उनकी गुजरात में अलग–अलग सेक्टर में 6 कंपनियां हैं जिसके लिए पूरे साल में भी कभी गांधीनगर नहीं जाना पड़ता। यह है गुजरात की ताकत जिसमें ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, लॉ एण्ड ऑर्डर और गवर्नेंस सभी कुछ तो है।

कंपनी का कोई भी काम रूटीन में ही हो जाता है। न रिक्वेस्ट की जरूरत और न सिफारिश की। राजस्थान में ऐसा दृश्य, ऐसी वर्क कल्चर संभव है क्या? सभी अपना घर अच्छा देखना चाहते हैं इसलिए कई बार कुछ मित्र यहां के स्कूलों, तालाबों और अन्य सामाजिक और विकास के कार्यों को अपनी जन्मभूमि पर आकर करवाने चाहते हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि उन्हें भी समस्या आ रही है, ये अच्छा अनुभव नहीं होता।

कैपिटल सेफ्टी सबको चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उद्यमी को शोषक समझ लिया जाये। सामान्य धारणा कुछ भी हो, लेकिन गुजरात में जमीन, बिजली, पानी और अन्य संसाधन बहुत सस्ते भी नहीं हैं, फिर भी लोग यहाँ निवेश करने आते हैं। क्यों?

❑❑❑

Laghu Udyog Bharati signed an MoU with BITS Pilani, covering all campuses - Pilani, Goa, Hyderabad, Mumbai, and Dubai on 21st Nov. The ceremony took place in hybrid mode. Prof. Sounak Roy, Dean Research & Innovation, BITS Pilani shared PPT on research and innovation ecosystem and LUB's national initiatives and industry/ academia activities by Smt. Jayanti Goela, National Coordinator - Industry Academia.

The event was graced by the presence and remarks of Prof. Suman Kundu, Director, BITS Pilani K.K. Birla Goa Campus; Col. S. Chakraborty (Retd.), Registrar, BITS Pilani; Shri Madhu Sudan Dadu, National President, LUB; Shri Om Prakash Gupta, National General Secretary, LUB, Smt. Pallavi Salgaocar, President LUB Goa, Shri Mudit Agarwal GS Goa, Shri Vibhor Keny, Shri Yogish Kulkarni and Shri Jayesh Raikar.

गवर्नेंस का 'गुजरात मॉडल' आखिर है क्या?

सफलता का जो मार्ग मोदी ने दिखाया, उस पर राजस्थान क्यों नहीं चल पाया?

Exclusive Interview @ Udyog Times

भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है जब किसी व्यक्ति को अचानक एक प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के तौर पर सौंपी गई हो। और इतना ही नहीं, पहली बार के अनिर्वाचित विधायक ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपनी और सरकार दोनों की परफॉर्मेंस के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। लेकिन ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर वर्ष 2001 में गुजरात से की। उससे पहले उन्होंने सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था। ये दीगर बात है कि वे गुजरात की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से न केवल भली–भांति परिचित थे, बल्कि अपने सांगठनिक कौशल और संपर्कों का दिग्दर्शन वे संघ के प्रचारक के नाते करा चुके थे। कुल मिलाकर मोदी सामान्य लोगों को राजनीति में नए जरूर लगे होंगे, लेकिन वास्तव में वे बहुत परिपक्व और गहरे व्यक्तित्व थे, जो बाद में उनके कुशल नेतृत्व और नीतियों में परिलक्षित होता है।

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश की छवि निर्माण (Image Building) में शानदार योगदान दिया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ त्वरित निर्णय से प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था और निवेश के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य (Best Destination for Investments) के रूप में गुजरात को इस तरह प्रतिष्ठित किया, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन यानी गुजरात मॉडल के नाम से जाना गया। सवाल यहां बस ये है कि जो रास्ता मोदी ने सबको दिखाया, उस पर राजस्थान क्यों नहीं चल पाया?

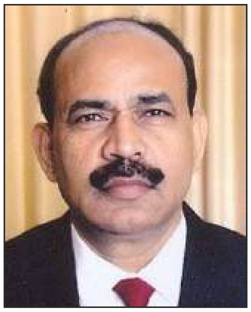

गुजरात मॉडल और निवेश में राजस्थान की कमजोर पहल के सवाल को लेकर उद्योग टाइम्स के को–एडिटर डॉ. संजय मिश्रा ने गुजरात राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री जीआर आलोरिया से विशेष बातचीत की।

वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1981 बैच के आईएएस मूलतः जयपुर के पास गोनेर से हैं जिन्होंने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, सामाजिक क्षेत्रों, स्टार्ट– अप, नवाचार और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने जीएसपीसी, जीएसएफसी, जीएनएफसी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, जीएसीएल, गुजरात गैस, जीएसपीसी एलएनजी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों की अध्यक्षता की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के पद पर रहते अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, PPP मॉडल पर स्लम रीडेवलपमेंट, महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन पर नई पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाई।

श्री आलोरिया कहते हैं कि किन्हीं भी दो राज्यों की तुलना करने से पहले उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जानना–समझना जरूरी होता है। यही गुजरात और राजस्थान में भी हमें करना है। भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, तो राजस्थान एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, वहीं गुजरात कोस्टल यानी तटीय प्रदेश है और वो भी ऐसा कि जिसकी सर्वाधिक लम्बी कोस्ट लाइन है, 1600 किलोमीटर तक जाती है।

राजस्थान से जो पलायन हुआ, वो मुख्यतः कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट की ओर हुआ। वहीं गुजरात से माइग्रेशन पहले अफ्रीकी देशों में हुआ, और फिर अफ्रीका से यूरोप तथा वहां से होते हुए गुजराती अमेरिका तक पहुंचे।

राजस्थान के लोग अमूमन संतोष प्रकृति के होते हैं, जो उनके पास होता है, अधिकांशतः उसमें ही संतोष करने वाले लोग होते हैं। दूसरी ओर गुजराती लोग स्वभाव से ही व्यावसायिक प्रकृति के होते हैं और आगे की सोच रखते हैं।

गुजरात और राजस्थान में सिंचित क्षेत्र की कुल उपलब्धता के आंकड़ों को एक बार अलग भी रख लें, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गुजरात का किसान वर्ष भर में तीन से चार फसलें लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये ट्रेंड राजस्थान में देखने में नहीं आता। इसी तरह राजस्थान का बाशिंदा जब भी मकान बनाता है, तो वो भी कई किश्तों में, जबकि गुजराती पूरी योजना से एक बार में ही ये कार्य करता है। ये जो ज़ील और उत्साह है वो गुजराती में है और इसे मानने से हमें इंकार नहीं करना चाहिए।

आज ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट) बात हो रही है सभी राज्यों में, उसमें भी गुजरात बहुत एडवांस रहा है। वहां जामनगर में ब्रास, राजकोट में इंजीनियरिंग, सौराष्ट्र में डायमंड और टेक्सटाइल्स तथा खेड़ा में एग्रीकल्चर के क्लस्टर्स डेवलप हुए।

राजस्थान में राजे–रजवाड़ों का प्रभुत्व लम्बे समय से रहा है और लोगों की मानसिकता भी उस सामंतवादी सोच से अलग नहीं रह सकी, क्योंकि बरसों तक उसे यहां के लोगों ने भोगा जो था। उसी रियासतकालीन समय में जब राजाओं और सामंतों का राज होता था, यहाँ शिक्षा का प्रसार बहुत ही कम

रहा। न शिक्षा के केंद्र सबके लिए सुलभ थे। और न ही राज्यों की नीतियों में शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति ही देखने में आती है। लोगों की पीढ़ियां तक अशिक्षित ही रहती रही। दूसरी तरफ गुजरात में इसके विपरीत इतिहास मिलता है। भावनगर बड़ौदा के श्री सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय के समय शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, जो समकालीन राज व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। यानी दुनिया किस तरफ जा रही है, प्रगतिशील सोच क्या है, उसे देखकर ही शासन में बदलाव कर लिए जाते थे। ऐसे लोगों को ही तो विजनरी या दूरदर्शी कहा गया है।

1990 के फेज में गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट पर हजीरा में पेट्रोकेमिकल्स में रिलायंस और एस्सार ग्रुप, सूरत में डायमंड, जरी और टेक्सटाइल्स का काम बढ़ गया।

सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट (1 बिलियन USD प्रोजेक्ट) के

जॉइंट MD (फाइनेंस) रहते श्री आलोरिया ने सहमति से 16000 हेक्टेयर जमीन खरीदने में योगदान किया साथ ही सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और कच्छ में नहर नेटवर्क का विस्तार किया। जब नर्मदा परियोजना का काम शुरू हुआ, कैनाल के बैंक पर पंप लगाकर खेती में पानी लेना शुरू किया गया। इसी तरह बरसात के बाद पशुओं और खेती के लिए भी जल संग्रहित किया जाने लगा। नर्मदा डेम से ट्रंक लाइन से लिए जा रहे पीने के पानी पर गुजरात की पचास प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है।

अकाल की त्रासदी दोनों राज्यों ने ही झेली थी लेकिन दक्षिण गुजरात की जियोफिजिकल कंडीशंस अलग रहीं है, तो उसे छोड़कर शेष गुजरात को ले सकते हैं। पानी की समस्या से ग्रसित होकर गुजरात से भी पलायन हुआ। ये लोग धीरे–धीरे जब मुंबई में सेटल होने लगे, तो महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में नए उद्योग स्थापित हुए, उनकी एंसिलियरीज भी साथ में आने लगी। इसका सबसे अधिक असर महाराष्ट्र से सटे गुजरात के कई इलाकों पर हुआ जिससे बलसाड़, वापी, अंकलेश्वर की ओर आते हुए महाराष्ट्र से मेहसाणा तक गोल्डन कॉरिडोर डेवलप हो रहा था। दूसरे राज्यों से लेबर भी आने लगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनने लगा और कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां तेज होने लगी।

गुजरात में मोदी युग की शुरुआत–

गुजरात व्यापार में आसानी लाने (Ease of Doing Business) की रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर रहा। इसके लिए व्यापक सुधारों पर कार्य करने वालों में से प्रमुख रहे श्री आलोरिया बताते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो व्यवस्था को दिशा दी, वो गेमचेंजर रही। वे बताते हैं कि राजनीति में नरेंद्र भाई का नौसिखियापन उनके और खासतौर पर प्रदेश के लिए फायदे का सौदा रहा। ये उनके लिए अच्छी बात ही थी कि उनके दिमाग में संगठन में बाहर–भीतर काम कर रहे पदाधिकारियों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं थे, और न ही किसी से घोषित तौर पर राजनीतिक द्वेष या प्रतिद्वंद्विता ही थी। उन्होंने लम्बे समय तक गुजरात में संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर कार्य किया, इसलिए संगठन की गहरी समझ तो जरूर रही उनको।

ट्रांसफर पर लगाम एवं प्रशासन में स्थायित्व–

गुजरात मॉडल के बारे में चर्चा करते हुए श्री आलोरिया बताते हैं कि मोदी सरकार में गुजरात के प्रशासनिक ढांचे में आमतौर पर कोई फेरबदल नहीं किया जाता था यानी ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर बहुत आसानी से नहीं होते थे। मोदी ने मुख्यमंत्री पद की की कमान संभालते ही इस पर अघोषित रोक ही जैसे लगा दी थी। क्योंकि वे जानते थे कि इससे प्रशासन में अहम ओहदों पर काम कर रहे अधिकारियों में गलत सन्देश जा सकता है, साथ ही वे जिन दायित्वों पर काम कर रहे होते हैं वहां भी सौ फ़ीसदी प्रदर्शन नहीं कर पाते। और उनका मनोबल भी इससे गिर सकता है। मोदी जानते थे कि आया राम, गया राम की बजाय अगर प्रशासन में स्थायित्व बना रहता है, तो स्टेबल गवर्नमेंट की छवि का सकारात्मक असर निवेश के मामलों में भी होता ही है।

नौकरशाही में भी इस बात का अच्छा सन्देश गया कि उन्हें एक विभाग में निरंतर कार्य करने का अवसर और सरकार को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और अनावश्यक ट्रांसफर की तलवार भी सर पर नहीं लटकती रहेगी। इस तरह जब

ब्यूरोक्रेट्स कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और गुड फेथ में काम करते हैं।

श्री आलोरिया ने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि गुजरात सरकार में वे अर्बन डेवलपमेंट विभाग में 15 वर्ष तक विभिन्न पदों पर रहे। ऐसे उदाहरण देश भर में बहुत विरले ही मिलते हैं जब आप सीनियर पोजीशन पर एक ही विभाग में इतने लम्बे समय तक कार्य कर सकें। ये इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित और पोषित करता है कि मोदी सरकार में नौकरशाह को बिना किसी दखल के काम करने के लिए पूरा समय और समर्थन दोनों मिलता था। ऐसी स्थिति में सरकारी मशीनरी में रोजमर्रा के काम बहुत ही सहजता से सम्पन्न होते हैं, फाइलें टेबल पर रखी नहीं रहती। ब्यूरोक्रेट्स अधिक रेस्पॉन्सिव होते हैं। ये निर्णय गुजरात की नौकरशाही में एक लैंडमार्क के तौर पर देखा जाता है।

ये तो रही टॉप ब्यूरोक्रेसी की बात। इसके साथ ही अलग–अलग विभागों में काम करने वाले अधीनस्थ सेवाओं और अन्य विभागों के कर्मियों के भी तबादलों को लेकर स्पष्ट नीति रही है। जबकि अन्य राज्यों में विधायकों की डिजायर से ट्रांसफर होते रहे हैं और नियत समय पर ट्रांसफर खुलने की लोग प्रतीक्षा करते हैं। ये ट्रांसफर फेस्टिवल जैसा ही होता है। कई राज्यों में ये संस्थागत धंधे में बदल जाता है।

ट्रांसफर केवल तीन स्थितियों में ही हो सकते थे–

1. **लोक सेवक की गंभीर शिकायत होने पर**
2. **भ्रष्टाचार या अनियमितता में संलिप्त होने पर**
3. **सरकार को किसी विशेष टास्क में किसी लोक सेवक की आवश्यकता होने पर**

इस प्रकार मोदी ने गुजरात में नौकरशाही को लेकर होने वाले राजनीतिक दखल को लगभग ख़त्म ही कर दिया था।

सरकारी भर्तियों में पादर्शिता–

गुजरात में शासन की ओर से की जानी वाली भर्तियों (रिक्रूटमेंट) में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के तौर पर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन करने और ई–गवर्नेंस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले श्री आलोरिया ने बताया कि एक बार पुलिस की भर्ती वाले स्थल पर एक आईपीएस अधिकारी के अनाधिकृत रूप से वहां अन्य व्यक्तियों के साथ आने की घटना रिपोर्ट हुई, तो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को बरक़रार रखने हेतु तुरंत उस आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। ये था जीरो टॉलरेंस।

दूसरी ओर सरकारों में सरकारी नौकरियों में कई बरसों से धांधलियों के चलते लोगों का सरकारी एजेंसी पर यकीन कम हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में सरकारों ने जरूर थोड़ी तत्परता दिखाई है परीक्षाओं की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए।

जनता की पहुंच में सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों –

गुजरात में आम जनता की पहुंच (Access) में सरकार और नौकरशाही दोनों ही रहते हैं। कलेक्टर और क्षेत्रीय अधिकारी अगर जनता की समस्याओं पर तुरंत ध्यान नहीं देते हैं, तो मामला सचिव और मंत्रियों तक शीघ्र ही पहुँच जाता है। इसके विपरीत राजस्थान लम्बे समय तक फ्यूडल स्टेट (सामंतवादी राज्य) होने की वजह से ब्यूरोक्रेसी में अभी भी कहीं न कहीं उसका असर दिखता है और यही वजह है कि प्रशासन के साथ जनता का स्वाभाविक कनेक्ट नहीं बन पाता और त्वरित निर्णय भी नहीं हो पाते।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया एक्शन प्लान–

मोदी ने गुजरात के आधारभूत ढांचे के कायाकल्प के लिए मिशन मोड पर काम किया। उन्होंने नर्मदा योजना के क्रियान्वयन पर अफसरों को लक्ष्य दिया। यहां ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काम हुआ। कच्छ के रण क्षेत्र में पर्यटन विकास को शुरू किया। इंडस्ट्री सेक्टर, रोड नेटवर्किंग और बंदरगाहों के विकास पर ध्यान दिया गया। इसमें मूंदरा, हजीरा, पीपावाव, घोघा और कांडला पोर्ट्स को विकसित करने का कार्य किया।

नर्मदा के पानी ने गुजरात के किसानों के खेतों को जब सींचना शुरू किया, तो उस पूरे क्षेत्र में किसानों को समृद्ध बनने में बहुत समय नहीं लगा। पारम्परिक फसलों की बजाय कैश क्रॉप्स उगाई जाने लगी। इसमें इसबगोल और जीरा जैसी फसलें भी शामिल थीं।

इसी तरह लॉजिस्टिक्स पर भी काम शुरू किया गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एनसीलियरीज बड़ी संख्या में आने लगी। फिर सरकार ने ट्यूरिज़्म को भी फोकस किया। बड़े स्तर पर नवरात्रि महोत्सव और वाइट रन फेस्टिवल शुरू किये गए।

निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात की पहल

इसके बाद वाइब्रेंट गुजरात की 2003 में अहमदाबाद में शुरुआत की गई। पहले–पहल नेशनल लेवल की बड़ी

कम्पनीज पर फोकस किया गया और फिर जल्दी ही मल्टीनेशनल कम्पनीज और अन्य देशों की सरकारों के साथ प्रवासी गुजरातियों को भी एप्रोच किया गया। स्टेट के पोटेंशियल को विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया। उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी और इंसेंटिव अन्य राज्यों की तुलना में अधिक नहीं होने पर भी गुजरात में निवेश के लिए यहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंसी को अधिक प्रचारित किया गया।

आईएमडी नर्मदा योजना में जब कैनालों के लिए किसानों से जमीन अवाप्ति का काम चल रहा था, उस समय श्रीमती आनंदी बेन पटेल रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करती थी। किसानों को पूरे विषय की समझाइश के साथ नक़्शे के अलाइनमेंट को भी बातचीत कर चेंज कर दिया जाता था। जिन रास्तों से जमीन अधिग्रहित की गई, वो आने वाले समय में दस–बीस गुना तक बढ़ गई थी। इससे किसानों में और अधिक विश्वास पैदा हुआ सिस्टम के लिए।

स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन (SIR), सोलर, पावर, लॉजिस्टिक्स पार्क सभी को लेकर होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम किया गया पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया गया। पीपीपी मॉडल पर अल्ट्रा मॉडर्न बस टर्मिनस बनाये गए। सरकारी बसों को प्राइवेट बसों की मानिंद ट्रांसफॉर्म कर दिया गया जिससे बरसों से घाटे में चल रहा ये विभाग प्रॉफिट में आ गया। लैंड रिफॉर्म्स का काम शुरू किया गया। जमीनों के रि–सर्वे सैटेलाइट ड्रोन की मदद से ग्राउंड टूथिंग कर मिलान किया गया।

पॉलिसी में क्लैरिटी, किसी को डिस्क्रीशन पावर नहीं–

गुजरात मॉडल की सबसे खास बातों में से एक रही है उसकी पॉलिसी में स्पष्टता। सरकारी योजनाओं के ड्राफ्ट इस तरह से बनाये गए, कि उनकी 'बिटवीन दी लाइन' किसी भी तरह की स्वविवेक की शक्ति ब्यूरोक्रेट्स को न दी जाये। ताकि किसी भी प्रोजेक्ट्स की क्लीयरेंस में कोई अफसर किसी को फायदा पहुँचाने की मंशा से उसे तोड़–मरोड़ न सकें। इंटर–डिपार्टमेंट इश्यूज के निपटारे के लिए कोआर्डिनेशन कमेटी काम करती थीं।

उद्योगों के लिए जमीन आवंटन को लेकर भी नीति स्पष्ट थी। इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल में ही इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता था कि ये जमीन जीआईडीसी के प्लॉट्स से चाही गई है या फ्री ज़ोन या स्पेशल इकनोमिक ज़ोन से जुड़ी है। अगर वर्जिन लैंड है, तो उसके लिए अलग से रिक्वेस्ट आती थी। अगर सीधे किसानों से खरीदनी होती थी, तो उसका अलग सिस्टम था।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए वहां Index tB-Industrial Extension Bureau काम करता है जहां उद्यमी अपनी फाइल के मोमेंट को देख सकता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग से लोगों का यकीन पैदा हुआ सिस्टम में। अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। उद्यमियों को भरोसा होता था कि हैंडहोल्डिंग मिलेगी। कोई हाथ पकड़ने वाला है।

देखिए, सारे ब्यूरोक्रेट्स तो यूपीएससी से ही आते हैं सलेक्ट होकर। वे ही देशभर के सिस्टम को चला रहे हैं। उनमें तो कोई अंतर होता ही नहीं है। हम अगर राजस्थान की बात करें, तो यहां भी सिस्टम को समझने वाले ब्यूरोक्रेट्स कम थोड़े ही हैं, अच्छी समझ वाले भी हैं, और वे काम करना भी जानते हैं। फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में उनकी वर्किंग में बहुत अंतर किस लिए आ जाता है? ये सवाल निश्चित रूप से बड़ा है।

लम्बी कागजी प्रक्रिया (Procedure) को आसान बनाया–

मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करूं, तो आप हैरत में पड़ जायेंगे, कि करीब 150 तरह की रसीदें हुआ करती थीं पहले। उसे हम सिंगल पेपर पर ले आये। इसी तरह से बिजली के लिए जो अप्लीकेशन हुआ करती थी, उसमें भी अनावश्यक बिंदुओं को ख़त्म कर कंस्यूमर्स को ईज किया गया। मोदी सरकार ने देश में सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया। ये बड़ी राहत थी। लोग पहले इसी काम के लिए चक्कर काटा करते थे। कुल मिलाकर प्रोसीजर को कट किया गया।

त्वरित निर्णयों के लिए नियमित कैबिनेट बैठकों का आयोजन–

गुजरात मॉडल में ये बिन्दु भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि सरकार नियमित तौर पर अपनी कैबिनेट के साथ बैठके करें। जिन

राज्यों में ये अनियमित रहती हैं, वहां लोक जीवन में अपेक्षाकृत अधिक असंतोष रहता है। क्योंकि बैठकों का सीधा सम्बन्ध लोक कल्याण से जुड़ा होता है और उसकी अनदेखी से सरकार को नुकसान होता ही है। इसलिए गुजरात में प्रत्येक मंगलवार को मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री सुलभ होते हैं पब्लिक से मिलने के लिए। बिना अपॉइंटमेंट के भी आम जन इनसे मिल सकती है। प्रत्येक बुधवार कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें मंत्रीगण विविध योजनाओं के फीडबैक के साथ शासन से जुड़े मसलों पर अपनी राय रखते हैं और उन पर वहां मंथन होने से तीव्र गति से कार्यवाही हो पाती है। इसके साथ ही सेक्रेटरीज की मीटिंग सीएस लेता है। ये सिलसिला बरसों से चल रहा है, इसलिए जनहित से जुड़े विषयों पर बहुत अधिक पेंडेन्सीज नहीं रहती। कुल मिलाकर शासन में खुलापन दिखना चाहिए और पारदर्शिता हर स्तर पर सुनिश्चित हो, ये जरूरी है।

योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन

गुजरात मॉडल के महत्वपूर्ण तत्वों में समयबद्धता (Time Bound Execution) बहुत प्रभावी है क्योंकि गुजरात ने बीते 25 वर्षों में जो बड़े विकास कार्य किए हैं, उनमें से अधिकांश मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू और संपन्न किये गये। श्री आलोरिया बताते हैं योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की देरी संभव नहीं थी। रेडटेपिज़्म यानी लाल फीताशाही की तो कोई जगह ही नहीं थी। अधिकारीयों को सरकार के पोर्टल पर ही फाइल पर अपनी टिप्पणी और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती थी। साथ ही सक्षम स्तर पर मॉनिटरिंग और कोआर्डिनेशन निरंतर रहता था। बड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाती थी, इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई इसमें बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी, ये बात सम्बद्ध विभाग से जुड़े सभी लोगों को मालूम रहती थी। इसलिए मोदी जी के रहते वहां लगभग सभी योजनाएं रिकॉर्ड टाइम में पूरी हुई हैं। श्री आलोरिया ने जानकारी दी कि वे स्वयं ऐसे बड़े टास्क में शामिल रहे हैं जिसमें सूरत में 600 हेक्टेयर में डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी (ड्रीम सिटी) और पीपीपी मॉडल पर सूरत और गांधीनगर में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट और 100 नई टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी आदि शामिल हैं।

❑❑❑

Chairman of National Traders Welfare Board Shri Sunil Singhi discussed the schemes being run by the Central Government to increase ease of doing business at Jodhpur on 30th Nov. On this occasion, LUB's Former National President Shri Ghanshyam Ojha, Shri Anil Agarwal, Shri Sudhindra Duggar, Shri Mahavir Chopra, Shri Deepak Mathur, Shri Pankaj Bhandari and Asstt. Director DIC Smt. Pooja Surana were present.

On the occasion of the 70th Foundation Day of Madhya Pradesh, LUB's State President Shri Rajesh Mishra and GS Shri Arun Soni represented the MSME Sector at the Abhyudaya Madhya Pradesh program organized by the Government of Madhya Pradesh in the capital city of Bhopal. They also discussed the Prospects and Challenges reg. MSMEs with CM Dr. Mohan Yadav on 5th Nov.

A new batch of stitching (tailoring) training for women was started at the Saksham Bharat Skill Development Center on 4th Nov. This centre is run by LUB's Alwar Unit in collaboration with Alwar Chamber of Commerce and Industry and PNB RSETI. On this occasion, Shri Rajesh Gupta, President CCI and Shri Shashank Jhalani, President of LUB, Alwar were present.

अगर इनलैंड पोर्ट का खाका वर्ष 1996 में ही बन गया था, तो फिर किसने रोक दिया राजस्थान का औद्योगिक विकास ?

ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर ये पोर्ट दो दशक पहले बन जाता, तो आज राजस्थान पड़ोसी गुजरात से कहीं अधिक आगे होता। लेकिन अफ़सोस, ये हो न सका।

Exclusive Story @ Udyog Times
by Dr. Sanjay Mishra

राजस्थान में इनलैंड पोर्ट की संकल्पना का खाका वर्ष 1996 में ही बनकर तैयार हो गया था। तत्कालीन पेट्रोलियम निदेशक श्री जीपी माथुर ने पहली बार मरुधरा पर बंदरगाह बनाने का स्वप्न देखा। और उसे डेप्युटी सेक्रेटरी माइंस श्री निरंजन आर्य से साझा किया। श्री आर्य ने भी अचरज भरी नज़रों से श्री माथुर के प्लान पर गौर किया।

उसी दौरान संयोग से राजस्थान से मिलती–जुलती भौगोलिक स्थितियों वाले नीदरलैंड में भी इस तरह की परियोजना मूर्त रूप ले चुकी थी, तो उसी का अध्ययन करने के लिए श्री माथुर और श्री आर्य दोनों नीदरलैंड पहुँच गए थे। लेकिन वहां की परियोजना का जब उन्होंने अवलोकन किया, तो उसका आकार राजस्थान की परियोजना के समक्ष बहुत छोटा निकला, जिसमें बड़े जहाजों का नेविगेशन संभव नहीं था।

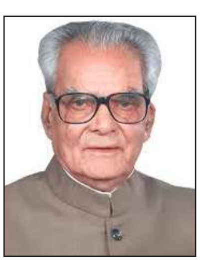

नीदरलैंड से वापस जयपुर लौटने के बाद श्री माथुर ने वर्ष 1997 में 250 पेज का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। सिस्टम में उनकी नेटवर्किंग अच्छी थी और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत से मिलकर अपने इनलैंड पोर्ट के प्रस्ताव पर बात की। श्री शेखावत ने भी बहुत रुचि लेकर पूरे विषय को सुना।

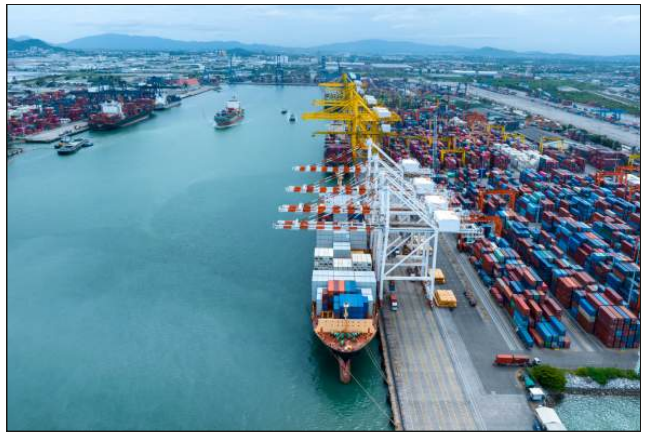

प्रदेश में दलगत राजनीति, प्रबल राजनीतिक नेतृत्व और इच्छा शक्ति के अभाव में इस इनलैंड पोर्ट के प्रोजेक्ट में हुए विलम्ब के कारण अनुमानतः 8 लाख करोड़ रु के राजस्व का नुकसान हो चुका है।

प्रस्ताव के कुछ समय बाद ही जून, 1998 में गुजरात में भयंकर समुद्री तूफ़ान आया था। 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से आये उस तूफ़ान ने ऐसी तबाही मचाई कि 2 लाख घर उससे प्रभावित हुए।

करीब 700 मिलियन डॉलर की संपत्ति (भारतीय मुद्रा में रु. 63123795000.00) का नुकसान भी हुआ।

इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद श्री गिरधर प्रसाद माथुर और श्री भैरोसिंह शेखावत हेलीकॉप्टर में बैठकर इस समुद्री तांडव को देखने गए थे जिसका मकसद पोर्ट की परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में ये भी देखना था कि दरअसल राजस्थान में कितना भीतर तक ये पानी आ सका है। क्योंकि भैरोसिंह जी के मन में भी इनलैंड पोर्ट का बीज तो बो ही दिया था श्री माथुर ने।

उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले श्री गिरधर प्रसाद माथुर ने भारत सरकार की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड में पहली नौकरी ज्वॉइन की भू–भौतिकविद (Geo-Physicist) के तौर पर। कुछ समय बाद वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) के जरिए माइंस एंड जियोलॉजी विभाग में काम शुरू किया और फिर यहीं के होकर रह गए। सिस्टम में अपने बेहतर संबंधों से उन्होंने पेट्रोलियम विभाग में डायरेक्टर की पोस्ट सृजित करवाई थी जिस पर 1997–2000 तक उन्होंने कार्य किया और फिर वहीं से वे रिटायर हो गए।

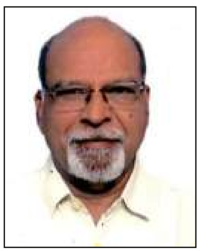

इस प्रस्ताव को बनाने में श्री माथुर के बाद अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो वो थे देश के जाने–माने भू–गर्भ शास्त्री श्री प्रदीप अग्रवाल, जो उस समय मुश्किल से 35 वर्ष के युवा भू–वैज्ञानिक थे। आरपीएससी के रुट से ही सलेक्शन होकर आये श्री अग्रवाल को भू–विज्ञान के अलावा भूगोल का भी बहुत अच्छा ज्ञान रहा था। उस वक्त सेटेलाइट और गूगल जैसे टूल्स भी चलन में नहीं थे, इसके बावजूद उस पूरी परिकल्पना को कागज़ पर उन्होंने सफलतापूर्वक अंकित कर दिया।

इनलैंड पोर्ट, जिसे वे वेट पोर्ट कहते हैं, की उनसे जब चर्चा की, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कि वो प्रस्ताव उनके पास ही रखा है अभी तक संभालकर। लेकिन राजस्थान के हक में इतनी शानदार योजना को साकार नहीं कर सकी यहां की सरकारें। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राजसिको की एक महिला कार्मिक ने तैयार किया। बहुत कम लोग जानते थे पीपीटी बनाना उस समय।

श्री अग्रवाल ने बताया कि हजारों वर्षों पूर्व अजमेर के पहाड़ों से जल की दो धाराएं निकलती थी, एक पुष्कर जी के पवित्र सरोवर में ठहर जाती, तो दूसरी लूणी नदी के रूप में अपना लम्बा सफर तय करते हुए कच्छ के रण और उसके बाद समंदर में समा जाती थी। कालान्तर में जलवायु परिवर्तन के कारण केवल अंतर ये आया है कि लूणी नदी सागर तक पहुँचने से पहले ही कच्छ के रण में ही खो जाती है। लूणी का सतत प्रवाह भले ही ख़त्म हो गया, लेकिन उसके चैनल यानी धारा के प्रवाह से बने रास्ते उसी तरह से मौजूद हैं। इसलिए जब कभी अरब सागर में ज्वार उठता है, तो इसी नदी के रास्तों से होकर उसका पानी 100 किलोमीटर आगे आ जाता है और इसी चैनल्स की खुदाई करके इसे कार्गो शिप के आने–जाने के लिए 60 से 100 मीटर की चौड़ाई में खुदाई करने का सुझाव प्रस्ताव में दिया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट की लम्बाई थी 270 किलोमीटर जिसे 10 मीटर गहराई में खोदा जाना था।

Plan of Proposed Canal For Sea Port At Bhawatra (Barmer)

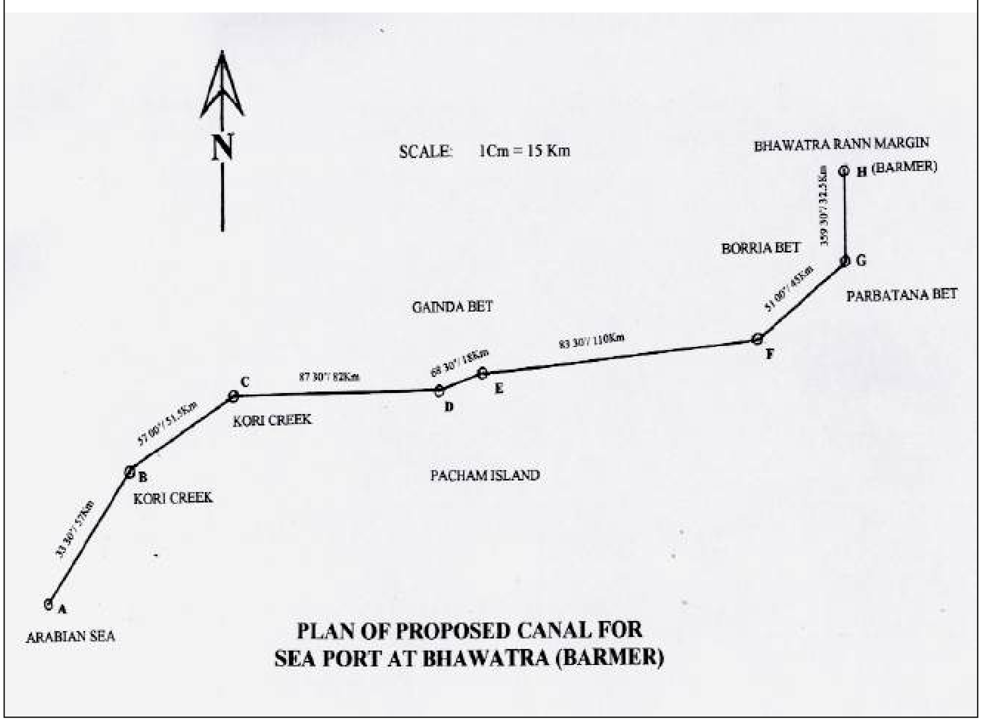

खैर, मुख्यमंत्री श्री शेखावत ने तत्कालीन केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी क्योंकि जहाजरानी मंत्रालय और बंदरगाहों का विकास केंद्र के अधीन ही आता है। तो उसके कुछ समय बाद ही शिपिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया की एक टीम ने राजस्थान आकर इस प्रस्तावित इनलैंड पोर्ट की प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में प्रस्ताव को निरस्त कर (turn down) दिया। इस तरह राजस्थान के विकास को बरसों पीछे कर दिया केंद्र की कांग्रेस सरकार ने। श्री प्रदीप अग्रवाल बताते हैं कि श्री जीपी माथुर साहब भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने भी प्रस्ताव पर शिपिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के रुख से हार नहीं मानी थी। क्योंकि वे जानते थे कि ये टास्क पूरा हो सकता है और ये प्रदेश के औद्योगिक विकास में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।

वे सरकार की नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। लेकिन अपने संपर्कों से लगातार वे इस प्रोजेक्ट को फिर से सुर्ख़ियों में लाना चाहते थे और उन्होंने एन चुनावों से पहले श्रीमती वसुंधरा राजे से भेंट की और इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया। वसुंधरा जी ने भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस भाजपा के चुनावी घोषणा–पत्र में शामिल करवा दिया। उसके बाद भाजपा तो जीत कर सत्ता में आ गई, लेकिन ये मुद्दा फिर से परवान नहीं चढ़ सका।

आज से 25 बरस पहले इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत थी 12000 करोड़, जिसका पे–बैक पीरियड (Pay Back Period) यानी कुल खर्च किये गए धन की पुनः वसूली (Recovery) के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था और आज अगर ये कॉस्ट तीन–चार गुना बढ़ भी जाती है, तब भी इसका पे बैक पीरियड करीब एक साल ही होगा। इस तरह करीब 24 वर्षों के हुए नुकसान को अगर औसतन 30 हजार करोड़ से भी कैलकुलेट करें, तो करीब 8 लाख करोड़ रु. का नुक़सान अभी तक हो चुका है।

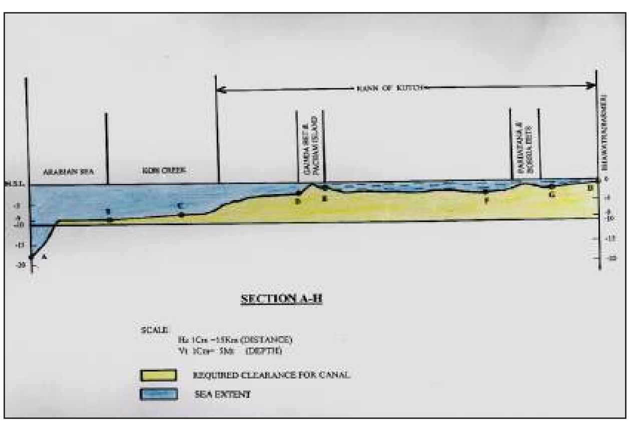

सीपोर्ट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की खास बातें और अनुमानित फाइनेंशियल असर

- कच्छ के रण के उत्तरी सिरे पर एक सही इन–लैंड हार्बर बनाने के लिए जगह पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए अरब सागर से कोरी–क्रीक (यानी लखपत से भवात्रा तक) तक फैले निचले इलाके में लगभग 350 km लंबे चैनल की ड्रेजिंग की जाएगी।
- इन–लैंड पोर्ट को शुरू में एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट कार्गो के हिसाब से कम से कम 50 MTPA लोड संभालने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।
- शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 350 km लंबे चैनल और बर्थ और मूरिंग जैसे पोर्ट स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए मौजूदा रेट स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोजेक्ट के शुरुआती स्टेज की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये है।
- प्रस्तावित इन–लैंड पोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और नॉर्थ इंडिया के बढ़ते ट्रेड ग्रोथ से फायदा उठा सकता है।
- प्रस्तावित चैनल इंटरनेशनल बॉर्डर के लगभग पैरलल है, जो इस बॉर्डर पर देश के क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा करने में देश की मदद करता है। इस नेविगेशनल चैनल को नेशनल वॉटर–वे घोषित किया जा सकता है, जिसे राजस्थान सरकार को ऑपरेट और मेंटेन करना पड़ सकता है।

इन-लैंड पोर्ट से देश को होने वाले लाभ

1. यह नहर रण के किनारे भारत की सुरक्षा को मज़बूत करेगी।
2. इससे राजस्थान में जहाज़ों तक पहुँच मिलेगी और उत्तर भारत के कंज्यूमर सेंटर्स की दूरी कम होगी, खासकर कच्चे पेट्रोलियम, LPG और LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए।
   a) पेट्रोलियम इंपोर्ट कुल इंपोर्ट का 21% है, जो 0.1 लाख करोड़ रुपये (1995–96) है। भौगोलिक रूप से भारत का वेस्ट कोस्ट इसके लिए सबसे सही है क्योंकि इसके आस–पास (मिडिल ईस्ट) में बड़े

रिज़र्व और एक्सपोर्ट करने लायक सरप्लस है। भारतीय बाज़ार, खासकर उत्तर भारत के बाज़ार में भी खपत की बड़ी संभावना है। भारत में बिजली की कमी भी आम है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम रॉ मटेरियल जैसे नेचुरल गैस, नेफ्था, डीज़ल और कम सल्फर वाले हेवी फर्नेस ऑयल की ज़रूरत होती है। प्राइमरी एनर्जी में पेट्रोलियम की खपत काफी ज़्यादा रहने की संभावना है।

b) टन के हिसाब से माँग तेज़ी से बढ़ेगी। साल 2000 से 2010 के बीच नैचुरल गैस की डिमांड दोगुनी होने की उम्मीद है। 2010–2011 तक कुल डिमांड में इम्पोर्ट का हिस्सा 54% या 54 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस इम्पोर्ट जितना ज़्यादा होगा।

c) LPG – डिमांड, सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चरः अभी, भारत में 90% LPG का इस्तेमाल घरेलू सेक्टर में होता है, खासकर खाना पकाने के लिए। नॉर्थ इंडिया 32.7% और वेस्ट इंडिया 31.9% इस्तेमाल करता है।

3. MoP & NG, GOI द्वारा बनाए गए एक ऑयल इंडस्ट्री ग्रुप के सर्वे के मुताबिक, स्च्ळ की अभी की डिमांड 3.5 मिलियन टन (17% इम्पोर्ट) है। यह 2006–07 तक बढ़कर 10.66 मिलियन टन (53% इम्पोर्ट) हो जाएगी।

4. मुंबई, कांडला, विजाग और मैंगलोर में लगभग 2 मिलियन टन LPG इम्पोर्ट किया जाता है। MoP और NG ने LPG के इंपोर्ट के लिए नए पोर्ट पहचानने के लिए एक कमिटी बनाई थी। इस कमिटी ने गुजरात में 5 नए पोर्ट, उड़ीसा में 2 नए पोर्ट और महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र और तमिलनाडु में 1–1 पोर्ट की पहचान की है। 12 नए पोर्ट पर सुविधाओं के अलावा, प्राइवेट सेक्टर 5 पोर्ट बना रहा है, जिससे कैपेसिटी 1.6 मिलियन टन बढ़ जाएगी। हालांकि, ये सभी सुविधाएं अभी भी मांगों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होंगी।

5. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कच्चे तेल की सालाना मांग अभी के 79 मिलियन टन से बढ़कर 2001 में 114 मिलियन टन, 2006–07 में 148 मिलियन टन और साल 2011–12 तक 189 मिलियन टन होने की उम्मीद है। नॉर्थ–इंडिया के कंज्यूमिंग सेंटर्स के लिए ज़्यादातर मात्रा इंपोर्ट करनी होगी।

6. LPG की 3.5 मिलियन टन मांग (1995–96) का लगभग 17% इंपोर्ट किया जाता है। साल 2006–07 तक इम्पोर्ट का हिस्सा बढ़कर 10.6 मिलियन टन का 53% होने की उम्मीद है। LPG आम तौर पर 5000 टन कैपेसिटी वाले टैंकरों में आती–जाती है।

7. एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट की रुकावटेंः
   प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि फंड की कमी की वजह से 7वीं और 8वीं प्लान के दौरान कोई और पोर्ट फैसिलिटी शुरू नहीं की गई है। पोर्ट पर पहले से ही लगभग 2 हफ़्ते का इंतज़ार करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भीड़ कम करने के लिए बड़े और छोटे, दोनों तरह के पोर्ट के डेवलपमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सुझाव दिया है।

राजस्थान को होने वाले संभावित फायदे

1996–97 जो इन–लैंड पोर्ट की परिकल्पना परिकल्पित की गई थी, उसमें जो फायदे राजस्थान को संभावित बताये गए थे उनका विवरण यहाँ दिया जा रहा है–

1. **जैसलमेर ज़िले में हाई ग्रेड लाइमस्टोन के बड़े भंडार हैं** – लो सिलिका लाइमस्टोन और सीमेंट बनाने के लिए। इस इलाके में 30,000 मिलियन टन से ज़्यादा सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन होने का अनुमान है। अगले कुछ सालों में 1.5 मिलियन TPA कैपेसिटी वाले सात सीमेंट प्लांट लगने की संभावना है; जिससे सीमेंट प्रोडक्शन में चार गुना बढ़ोतरी की गुंजाइश है। GOI ने 1996–97 के दौरान 5 मिलियन टन सीमेंट एक्सपोर्ट का टारगेट संभावित रखा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024–25 में राज्य सरकार द्वारा लाइम स्टोन ब्लॉक्स की सफल नीलामी की गई तथा वंडर सीमेंट एवं जेके सीमेंट दोनों 15–15 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट लगाने का कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं तथा वर्ष 2026–27 में उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है, यदि इन–लैंड पोर्ट बन जाता है, तो यहां से सीमेंट का निर्यात न केवल खाड़ी के देशों को, वरन यूरोप और अफ्रीका को भी किया जा सकेगा।
2. पश्चिमी राजस्थान में हर साल लगभग 1.5 मिलियन टन जिप्सम भेजा जाता है। राज्य में देश के कुल जिप्सम रिज़र्व का 90% से ज़्यादा है। प्रस्तावित पोर्ट के ज़रिए सस्ते ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता से जिप्सम और लो सिलिका–लाइमस्टोन की ज़्यादा आवाजाही होगी।
3. सी–पोर्ट के पास इम्पोर्टेड मेटल कंसन्ट्रेट पर आधारित

कॉपर और लेड–ज़िंक स्मेल्टर लगाने की भी गुंजाइश है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा गुजरात के कांडला पोर्ट के पास 5 मिलियन टन कॉपर कंसन्ट्रेट हेतु स्मेल्टर लगाने की परियोजना प्रारम्भ की गई है।

4. यह पोर्ट स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की निकासी, पश्चिमी राजस्थान के कास्ट डिपॉजिट से सीमेंट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा और दूसरे मिनरल और अनाज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा।
5. सीपोर्ट इम्पोर्टेड क्रूड पर आधारित रिफाइनरी लगाने के लिए एक आइडियल जगह है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी में लगभग 6 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात किया जायेगा। इस इन–लैंड पोर्ट से आयात करने से क्रूड ऑयल की लागत काफी कम हो जाएगी।
6. प्रस्तावित नहर का इस्तेमाल राजस्थान नहर से सिंचाई वाली ज़मीन से अनाज लाने–ले जाने के लिए फायदेमंद तरीके से किया जा सकता है।
7. इस तरह, जबकि हर साल लगभग 15 से 20 मिलियन टन का कार्गो उपलब्ध होगा, प्रस्तावित पोर्ट को शुरू में लगभग 2 मिलियन TPA का माल संभालने के लिए बनाया जा सकता है।

अब बरसों से दबी उस फाइल से गर्द साफ़ करके नए चश्मे से उसे देखा गया होगा, तो फिज़िबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव बन गई होगी। जो भी हुआ, अच्छा है लेकिन ये उदाहरण इस बात को समझने के लिए तो पर्याप्त है कि राजनीति के दलदल में या दलों की राजनीति में प्रदेश के हितों को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है।

❑❑❑

LUB's Bareilly Unit (UP) conducted Family Industrial Visit (Udyog Darshan) on 8th Nov.

LUB's Women Wing of Udaipur Unit conducted an Inaugural Session of Swayamsiddha Exhibition in the presence of MLA Shri Tarachand Jain, MLA Shri Fulchand Meena, LUB's State President Shri Yogendra Sharma & Add. Commissioner Smt. Pragya Kewalramani IAS on 1-3 Nov.

LUB's Bihar State Delegation met Industry Minister Shri (Dr.) Dilip Jaiswal and discussed the state of MSMEs.

LUB's Beawer Women Wing released a Poster for Swayamsiddha Exhibition & Trade Fair to be held on 3-4-5 January, 2026

क्रूड ऑयल उत्पादन एवं रिफाइनरी में लाभ का हिस्सा लेने में राजस्थान क्यों पिछड़ा ?

हमारी जमीन, हमारा तेल और मुनाफा सारा केंद्र को !

Exclusive Story @ Udyog Times
by Dr. Sanjay Mishra

29 अगस्त, 2009 वो तारीख है, जब राजस्थान की मरुधरा की कोख से केयर्न एनर्जी द्वारा क्रूड ऑयल उत्पादन शुरू किया गया। और उस हिसाब से किसी भी सूरत में 2015 तक रिफाइनरी चालू हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे भी शुरू होने में और दस बरस लग गए। शुरू होने की तारीख 4 बार आ चुकी, लेकिन अभी भी शुभारम्भ की अनिश्चितता है।

इससे बहुत पहले बठिंडा में गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी जो स्थापित की गई, वो दरअसल राजस्थान के हिस्से में दी जानी थी। लेकिन उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी, यानी डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान के साथ खेल कर दिया।

वर्ष 2009 को राजस्थान विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किये गए पेट्रोलियम विभाग के प्रतिवेदन में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उस समय केंद्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे श्री मणिशंकर अय्यर ने राजस्थान का हक छीनकर पंजाब में उस रिफाइनरी को डायवर्ट कर दिया। भटिंडा में ये रिफाइनरी मार्च, 2012 में शुरू हो चुकी थी और उससे पहले वहां अगस्त, 2011 में क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का ट्रायल रन शुरू हुआ था।

स्टेट को तेल उत्पादन के लाभ में हिस्सेदारी नहीं दी गई

तेल का गुना–भाग समझने के लिए माइंस एन्ड जियोलॉजी विभाग से सेवानिवृत्त अधीक्षण भू–वैज्ञानिक (Super-intending Geologist) के पद से सेवानिवृत्त हुए श्री राजकुमार शर्मा से इस विषय पर चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की मुहीम को पश्चिम के देशों के साथ नरसिम्हा राव सरकार ने भी अपना लिया था और इसी के परिणामस्वरूप तेल शोधन और उत्पादन में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए गए। इससे पहले भारत में इस कार्य में केवल भारत सरकार की कंपनियां ऑयल एन्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड ही तेल और गैस के अन्वेषण हेतु अधिकृत थी।

1991 में हुए उदारीकरण के पश्चात एस्सार, फीनिक्स, शेल इंटरनेशनल आदि निजी कंपनियां तत्समय में प्रचलित नियमों के अनुसार ONGC एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ उत्पादन सहभागिता करार में शामिल हुई। उस समय तेल एवं गैस की खोज हेतु लागू पॉलिसी के अनुसार

ओएनजीसी एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस दिया जाता था और निजी कंपनियों को लाइसेंसी कंपनी एवं भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय उत्पादन सहभागिता करार करना होता था जिन्हें ऑपरेटर कंपनी कहा जाता था। इस करार में विशेष बात ये थी कि अन्वेषण कार्य का समस्त निवेश ऑपरेटर कंपनी को ही वहन करना होता था। आज जो राजस्थान राज्य में तेल का उत्पादन हो रहा है, वो इसी तरह की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है जिसमें ओएनजीसी को बाड़मेर–सांचोर बेसिन में लगभग 10500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र स्वीकृत किया गया।

इस स्वीकृत क्षेत्र में ओएनजीसी ने ब्रिटेन की शेल कंपनी के साथ अनुबंध किया। शेल कंपनी ने इस क्षेत्र में दो तेल कूप गुढ़ामलानी में खोदे –गुढा ए और गुढा बी और पहली बार इस बेसिन में तेल की उपलब्धता को प्रमाणित किया। परन्तु तेल की अधिक उपलब्धता नजर नहीं आने के कारण शेल कंपनी ने अपना हिस्सा भारत सरकार की अनुमति से केयर्न एनर्जी को हस्तांतरित कर दिया।

इसके पश्चात वर्ष 2001–02 में केयर्न एनर्जी द्वारा ओएनजीसी के साथ अनुबंध कर अन्वेषण का कार्य पुनः प्रारम्भ किया वर्ष 2004 में मंगला क्षेत्र से एक विशाल तेल भण्डार की खोज की सफलता प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि शेल कंपनी उस समय भी और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन करने वाली कंपनी है। जबकि केयर्न एनर्जी वर्ष 2001–02 में दुनिया की 100 वे नंबर की तेल खोज एवं उत्पादन कंपनी थी। केयर्न एनर्जी के सफल अन्वेषण के पश्चात् एग्रीमेंट के मुताबिक ओएनजीसी को पूछा गया कि उसे वेंचर में कंटिन्यू करना है या नहीं, और अगर करना है तो उसे ऑपरेटर को किये गए खर्च का 30 प्रतिशत हिस्सा देना था।

क्रूड ऑयल उत्पादन में प्रॉफिट शेयरिंग का फार्मूला जो तत्समय में नियम था उसके अनुसार उसमें 40 प्रतिशत प्रॉफिट ऑयल का केंद्र सरकार, 30 प्रतिशत ओएनजीसी और 30 प्रतिशत ऑपरेटर कंपनी को देना तय किया गया। तथा राज्य सरकार को 20 प्रतिशत देय रॉयल्टी का भुगतान ओएनजीसी के 30 प्रतिशत प्रॉफिट ऑयल में से देना तय था। लेकिन ये प्रतिवर्ष कम होते–होते अब 12.5 प्रतिशत पर आ गई।

इस तरीके से 40 प्रतिशत भारत सरकार और 18 प्रतिशत

ओएनजीसी जो कि केंद्र सरकार का ही उपक्रम है, इस तरह से कुल मिलाकर केंद्र सरकार 58 प्रतिशत प्रॉफिट ले रही है और राज्य सरकार ठन–ठन गोपाल है। ये कहाँ क्या न्याय है कि जमीन राजस्थान की, तेल राजस्थान का, और मुनाफा केंद्र को?

वर्ष 1999 में तेल एवं गैस की खोज हेतु नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (New Exploration Licensing Policy] NELP) को लाया गया। इसमें 100 फ़ीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की मंजूरी दी गई। इसके तहत ओएनजीसी एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस जारी करने की बाध्यता समाप्त हो गई तथा भारत के साथ अन्य विदेशी कंपनियां तेल अन्वेषण हेतु ब्लॉक लेने के लिए एक लेवल पर आ गई। इसके बाद वेनेजुएला की PDVSA और इटली की ENI समेत कई अन्य देशों की कंपनियां यहां आई।

अब जब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान और केंद्र दोनों जगहों पर, तो प्रदेश को भी अपना 20 प्रतिशत प्रॉफिट इस रिफाइनरी में सुनिश्चित करना होगा। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि भजनलाल सरकार कितने प्रभावी ढंग से इस विषय को केंद्र के समक्ष रख कर राजस्थान को उसका वाजिब हक़ दिला पायेगी!

रिफाइनरी की परिधि में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स में 2.5 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होने की सम्भावना है। रिफाइनरी का शुरू होना वास्तव में पश्चिमी राजस्थान में निवेश और रोजगार सृजन का नया सवेरा होने जैसा है। रिफाइनरी के साथ एनसिलियरीज भी डेवलप होगी।

❑❑❑

निवेश के लिए नयी सोच, नवाचार और नयी रणनीतियों को अपनाना होगा

अंतर्दृष्टि

मनीष पारीक

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं स्वतंत्र निदेशक ONGC

manishpareekjpr23@gmail.com

Web: manishpareek.com

करीब चार बरस पहले हवाई यात्रा में टाटा कंपनी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी मिल गए। बातचीत में उन्होंने बताया था कि जब बंगाल के सिंगूर में कंपनी के सामने संघर्ष और संकट की स्थिति खड़ी हो गई, और ये तय हो गया था कि नैनो कार की फैक्ट्री को कहीं दूसरे राज्य में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तीन राज्यों में कंपनी की ओर से बाकायदा आवेदन भी भेजा गया।

जब अन्य राज्यों के अधिकारियों से बात चल रही थी, तभी गुजरात से मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हे स्वयं फोन करके 'वेलकम टू गुजरात' कहा और सभी बुनियादी सुविधायें तत्काल उपलब्ध कराते हुए फैक्ट्री शुरू करवा दी। यह अपने आप में एक ऐसा अनूठा किस्सा है जो प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय, संवेदनशील और सकारात्मक लीडरशिप और इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम को दर्शाता है।

लेकिन वहीं आज के दौर में अमेज़ॉन और फेसबुक के सबसे बड़े उद्योग कहलाये जाते हैं, उनकी पारंपरिक फैक्ट्री ही नहीं है। इस बदलते औद्योगिक परिवेश में मुझे लगता है कि निवेश एक बहुआयामी पहलू के रूप में उभर के आया है। ऐसे में प्रवासी राजस्थानी निवेश बढ़ाने के लिए ना सिर्फ मौलिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, साथ ही तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को बढाने की भी ज़रूरत है। इनोवेशन एवं रिसर्च डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने से निवेशकों का भरोसा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ हो सकेगा।

राजस्थान सरकार के 'एनआरआर' (प्रवासी राजस्थानी) नीति और 'राइजिंग राजस्थान' समिट जैसे प्रयास निवेश बढाने के रास्ते में कारगर है।

किंतु बदलते औद्योगिक परिवेश में निवेशको को आकर्षित करने के तरीकों को भी बदलने की आवश्यकता है। परंपरागत क्षेत्रों के बजाय,भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर ध्यान जैसे ग्रीन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों और हरित प्रथाओं को प्राथमिकता देना काफी फायदेमंद साबित होगा। हमें राजस्थानी युवकों को स्टार्ट अप खड़े करने में भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसे में निवेशक को राजस्थान में इन्वेस्ट करने में आकर्षित करेगा। फोकस अब 'सस्ता उत्पादन' से हटकर 'स्मार्ट, स्थिर और टिकाऊ उत्पादन' पर करना होगा।

वर्तमान दौर में नव उद्यमियों को स्टार्टअप, एमएसएमई उद्योग लगाने हेतु परिवेश की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए, राजस्थान केवल सौर ऊर्जा के भरोसे नहीं रह सकता। नये क्षेत्र जैसे पेट्रोलियम बायप्रोडक्ट की भी राजस्थान में विपुल संभावनाएं है। ऐसी सम्भावनाओं व क्षमताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में निवेशकों का रुझान बढ़ाने के लिए गतिशील और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान बदलते औद्योगिक परिवेश में निवेश हब के रूप में उभर कर आए।

□□□

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से
प्रदेश के विकास में समर्पित लघु उद्योगों के विकास की प्रदर्शनी
सशक्त भारत के बढ़ते कदम .....
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प
उत्सव 2026
PASCHIMI RAJASTHAN UDHYOG HASTSHILP UTSAV
JODHPUR
उत्सव 2026
२५ दिसम्बर २०२५ से ४ जनवरी २०२६
लघु उद्योग भारती
माननीय श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री-भारत सरकार
दिनांक : 25 दिसंबर, गुरुवार 2025 से 4 जनवरी, रविवार 2026
स्थान : रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर
माननीय श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री- राजस्थान सरकार
स्टॉल आंवटन फॉर्म वितरण 28 नवम्बर 2025 से,
लॉटरी में भाग लेने हेतु फ़ॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसम्बर 2025 शाम 5:30 बजे,
कॉर्नर नीलामी 1 दिसम्बर 2025 तथा स्टॉल आवंटन लॉटरी 2 दिसम्बर 2025 से
स्थान : जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, फोन : 0291-2431937
vyas advt
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री
एवं सांसद लोकसभा, जोधपुर
श्री राजेन्द्र गहलोत
सांसद
राज्यसभा
आयोजक
जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र
एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर
श्री के.के. विश्नोई
राज्यमंत्री
(उद्योग एवं वाणिज्य)
श्री राज्यवर्द्धन सिंह
केबिनेट मंत्री
(उद्योग एवं वाणिज्य)
नोडल एजेन्सी :
लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रान्त
Mob. : 8233454522
सम्पूर्ण भारत की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग उत्पादों का अनूठा प्रदर्शन,
सेमिनार, प्रतियोगिताऐं, मनोरंजन के साधन, सांस्कृतिक संध्याएँ व खाने-पीने की स्टालें
श्री जोगाराम पटेल
संसदीयकार्य एवं कानून मंत्री
श्री मदन दिलावर
शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री
श्री अतुल भंसाली
विधायक, जोधपुर शहर
श्री देवेन्द्र जोशी
विधायक, सूरसागर

राजस्थान को टेक ड्रिवन एवं नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की जरूरत

> **चीन को हम कुछ भी कहें, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वहां ब्लैक फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है जहाँ शाम को फैक्ट्री से सभी वर्कर्स के चले जाने के बाद रात भर अँधेरे में रोबोट्स उसी परफेक्शन से काम करते हैं। इससे बिजली की बचत भी होती है और प्रोडक्ट की लागत में कमी भी आती है।**

हम राजस्थानी

रवि शर्मा

प्रेसिडेंट, राजस्थान फाउंडेशन

मेलबोर्न चैप्टर

भीलवाड़ा के पास 3 हजार की पापुलेशन के छोटे से तिलोली गावं में एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। शुरू से ही मेरा मन था कि वायरलेस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पर कुछ काम करूं। पीसीएम से सीनियर सेकेंडरी करने के बाद कर्नाटक से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की। यहीं पर सरकार के एक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी से सम्बद्ध था। मेरे काम और जुनून को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करने का ऑफर मिला। राजस्थान के सांस्कृतिक परिवेश में मेरी परवरिश हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने के प्रस्ताव को घर में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। हमारे कल्चरल नॉर्म्स हमें इस तरह की आजादी सहज नहीं देते।

एमबीए के अंतिम सेमेस्टर में टोयोटा कंपनी में मेरा चयन हो गया था जहां प्रोक्योरमेंट मैनेजर के तौर पर सालाना 2.5 बिलियन डॉलर की खरीद करता था। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और अन्य देशों से कंपनी के लिए एसेसरीज की खरीद होती थी। मैंने टोयोटा में 12 वर्ष काम किया। लेकिन कुछ विशेष कारणों से कंपनी ने वो प्लांट बंद कर दिया था। वैज्ञानिक चेतना के साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति का मैं शुरू से ही था, तो जॉब चले जाने के बाद नए जॉब की बजाय मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने का निर्णय किया। मैंने इनोवेशन और टेक ड्रिवन वेंचर शुरू किया मैक्सवेल एंड हाइट्स नाम से वर्ष 2011 में। इसके न्यूज़ीलैण्ड और यूएस में दो ऑफिस भी शुरू किये। हमने जेट्स, कैरावन, बोट्स और जेटस्की के पार्ट्स बनाने शुरू किए और बाजार से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।

करीब 13 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अब यूनिट्स को थाईलैंड और चीन में शिफ्ट करने की योजना है। क्योंकि वो सारा बेल्ट वर्ल्ड फैक्ट्री बन रहा है। कारण है थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे देश अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कई सब्सिडी देते हैं। साथ ही कोस्टिंग में लॉजिस्टिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है।

उदाहरण के तौर पर हम जब शंघाई से मेलबर्न तक कंटेनर मंगाते हैं, तो उसका खर्च करीब 800 डॉलर्स आता है, और वही कंटेनर भारत में सबसे नजदीक पोर्ट चेन्नई से मंगाते हैं, तो खर्च करीब तीन गुना यानी 2500 डॉलर्स तक चला जाता है।

मातृभूमि को पुन: लौटाने का संकल्प है ये प्रवासी दिवस

आज भारत और राजस्थान में नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की जरूरत है। प्रवासी दिवस पर ऑस्ट्रेलिया से हम करीब 40 राजस्थानी आ रहे हैं, जो जयपुर में रिसर्च सेंटर और आउटसोर्सिंग हब की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ बेस्ट टैलेंट्स एआई और इनोवेशन से इंजीनियरिंग एक्सीलेंस पर कार्य कर सके। इसके साथ फार्मा सेक्टर में भी कुछ रूचि ले रहे हैं। भारत में हमारे पुणे ऑफिस में डिजाइन पर फोकस किया जाता है और एक टीम जयपुर में भी है। शीघ्र ही हम पेटेंट्स लांच करेंगे।

राजस्थानी कुटुंब ऑफ़ विक्टोरिया नाम से यहाँ राजस्थानियों की एसोसिएशन सक्रिय है जिसमें प्रेसिडेंट रहते हुए हमने भव्यता के साथ गणगौर फेस्टिवल का आयोजन यहाँ के सबसे महंगे रेस कोर्स कोलफील्ड में आयोजित किया। खास बात ये रही कि उसकी ब्रांड एम्बेसेडर प्रीमियर एलेन क्रिश्चियन थीं और प्रस्तुति देने के लिए राजस्थान से मुस्लिम कलाकार आये थे और उसको सपोर्ट करने वाली थी यहाँ की यहूदी कम्युनिटी। ये उस समय आयोजित किया गया, जब इजरायल के साथ इस्लामिक देशों का संघर्ष चल रहा था। ऐसा कार्यक्रम करने की सोच केवल राजस्थानी के पास ही हो सकती है। हाल ही में राजस्थानी एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल एलायंस राजस्थान कम्युनिटी का गठन किया है जिसके ऑफिस मेलबर्न और न्यूयॉर्क में बनाये हैं। राजस्थानियों ने पूरी दुनिया में जो अपनी जगह बनायीं है उसके पीछे उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता है।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

❑❑❑

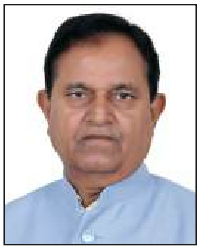

डिग्री नहीं, कौशल की कीमत है आज

हम राजस्थानी
अमराराम जांगिड़
प्रेसिडेंट, राजस्थान फाउंडेशन, दुबई चैप्टर

जोधपुर के पास भीकमकोर गाँव में हमारा साधारण परिवार रहता था। जोधपुर में रेलवे वर्कशॉप में पिता काम करते थे, तो गाँव में शुरुआती पढाई करके मैं जोधपुर ही आ गया था। यहाँ से दसवीं तक की शिक्षा पूरी की। इच्छा तो आगे भी पढ़ने की थी, लेकिन घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, डू और डाई की स्थिति थी। हम लोग खानदानी कारपेंटर हैं और मुझे मालूम था कि अब काम करना है और इसी सोच के साथ 1978 में जोधपुर से दुबई आया था बतौर कारपेंटर। यहाँ मुंबई बेस्ड कंपनी में नौकरी की जिसने शारजाह में 12 वर्षों तक हॉस्पिटल के लिए काम किया। यहां काम करने के बाद मैंने खुद की कंपनी शुरू की राजस्थान फर्नीचर इंक। उसके बाद फिर मुड़कर नहीं देखा।

हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारी सुथार कम्युनिटी को 250–300 एकड़ जमीन आवंटित कर दें, तो वहां फर्नीचर का ऐसा क्वालिटी प्रोडक्शन हो, कि दुनियाभर से खरीदार वहां से फर्नीचर/इंटीरियर खरीद सकें। इसी तर्ज पर चीन ने भी कुछ मेगा शोरूम/क्लस्टर्स तैयार किये हैं।

दुबई और राजस्थान दोनों जगहों में प्रशासन की कार्यशैली में बहुत अंतर दिखता है। हमारे यहां फाइल को ट्रैक करना मुश्किल है, जबकि यूएई में टाइम बाउंड रेस्पोंस मिलता है.. एक सप्ताह में फाइल पर लीगल रिप्लाई आ जाता है।

राइज़िंग राजस्थान के समय यहां से 60 लोगों ने भागीदारी की थी। उस समय करीब 600 करोड़ रु. के एमओयू साइन भी किये गए। उन पर कार्य चल रहा है। मेरा भी ओसियां के पास एक होटल बन रहा है 50 रूम का। प्रवासी दिवस पर मेरे साथ हमारे बहुत से सफल राजस्थानी भाई–बंधु आ रहे हैं जिनमें श्री मोहन गुरनानी, श्री अशोक ओजवानी और श्री टीकू सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं जो एक हजार करोड़ से अधिक निवेश करना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में। दुबई में आरबीपीजी (राजस्थान बिजनेस प्रोफेशनल्स ग्रुप) एक ऐसा संगठन है जिसमें राजस्थानी प्रोफेशनल्स ही सदस्य बन सकते हैं।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

❑❑❑

पुरखों की धरती पर आकर रोमांचित हो जाता हूँ

हम राजस्थानी

मोती दुग्गड़

अग्रणी उद्यमी एवं राजनीतिज्ञ

प्रेसिडेंट, राजस्थान फाउंडेशन, नेपाल चैप्टर

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में हमारी कई पीढ़ियां रहती आई थीं। मेरे परदादा श्री स्व। सोहनलाल जी दुग्गड़ की गिनती यहां के नामी–गिरामी दानी सेठों में हुआ करती थी। वैसे भी ये पूरा क्षेत्र तो सेठों के नाम से ही जाना जाता था। हमारे फतेहपुर के साथ लगते कस्बे का नाम ही रामगढ़ सेठाण रख दिया गया था। वो जमाना ही कुछ ओर था। घरानों के नाम चला करते थे और लोगों में भी परोपकार की भावना भी थी, तो धर्म–कर्म किया करते।

ये उस समय की बात है, जब इस मरू प्रदेश में कोई खास काम–धंधा नहीं था। और किसी के पास पहले से कुछ था भी, तो उसमें आगे बढ़ने के कोई विशेष अवसर नहीं थे। इसीलिए मेरे दादाजी अपने साथ पिताजी को लेकर व्यापार करने के लिए पहले कोलकाता आये और फिर वहां से विराटनगर। यहाँ उन्होंने बाकायदा सर्वे कर 1960 में जूट मिल शुरू की। जूट की खेती में बहुत अच्छी–खासी पैदावार होती थी वहां पर। लेकिन बाद में बदले हालातों के चलते उसे बंद करना पड़ा और फिर मुझ पर व्यापार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई।

सेंचुरी ग्रुप के नाम से हम पैकेज्ड फूड, दालें, चावल, और रसोई में काम आने वाले लगभग सभी मसाले करीब 30 देशों में निर्यात करने लगे। इसके साथ हमने होटल्स, रिसॉर्ट्स, लेमिनेट्स, पाइप्स जैसे उद्यम भी शुरू किये। मेरा जन्म यहां राजस्थान में नहीं हुआ, पर इतना जरूर हुआ कि दो वर्ष मैं जयपुर में पढ़ सका। लेकिन जब भी मैं अपने पुरखों की इस पुण्य धरा पर आता हूँ, हमारे घर ..... हवेली में, तो यहां की मिट्टी की खुशबू मुझे भीतर से रोमांचित कर देती है।

श्री दुग्गड़ ऐसे विरले प्रवासी हैं जिन्होंने नेपाल में अपने कर्म, कौशल और ज्ञान से व्यावसायिक क्षेत्र में ही सफलता नहीं अर्जित की, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी शीर्ष पर रहे। सम्प्रति तीन बार संसद सदस्य एवं उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री भी रहे। ये राजस्थान के साथ सम्पूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है।

नेपाल और भारत दोनों हिन्दू देशों में नैसर्गिक मित्रता है। बिना किसी वीजा और रोक–टोक के दशकों से भारत और नेपाल के लोगों की आवाजाही के साथ व्यापार भी सुगमता से होता रहा। भाषा और करेंसी को अगर अलग कर दें, तो दोनों तरफ के नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, परम्पराओं और रीति–रिवाजों में बहुत गहरी समानता नजर आती है। इसीलिए यहाँ से बड़ी संख्या में प्रवासी नेपाल गए और फिर वही के होकर रह गए।

करीब पांच लाख राजस्थानी वहां काठमांडू में रहते हैं और ये राजस्थानियों की विशेषता भी रही है कि वे जहां गए, उसे डेवलप कर दिया। प्रवासी यहां सामाजिक सरोकारों से जुड़े बहुत से कार्यों को करते हैं। अभी नए संविधान में ऐसा प्रावधान भी आ रहा है कि भारतीय यहां बहुत आसानी से निवेश भी कर सकें। नेपाल ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है, उद्योगों के साथ राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी भरपूर सफलता मिली। प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहने का सौभाग्य मिला।

राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने दुनियाभर में फैले यहाँ के प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की अभिनव पहल की। काठमांडू से कई मित्र प्रवासी दिवस पर मेरे साथ आ रहे हैं। हमारे ग्रुप की टीम भी साथ में आ रही है जो माइंस, केमिकल्स और हेल्थ सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा करेगी।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

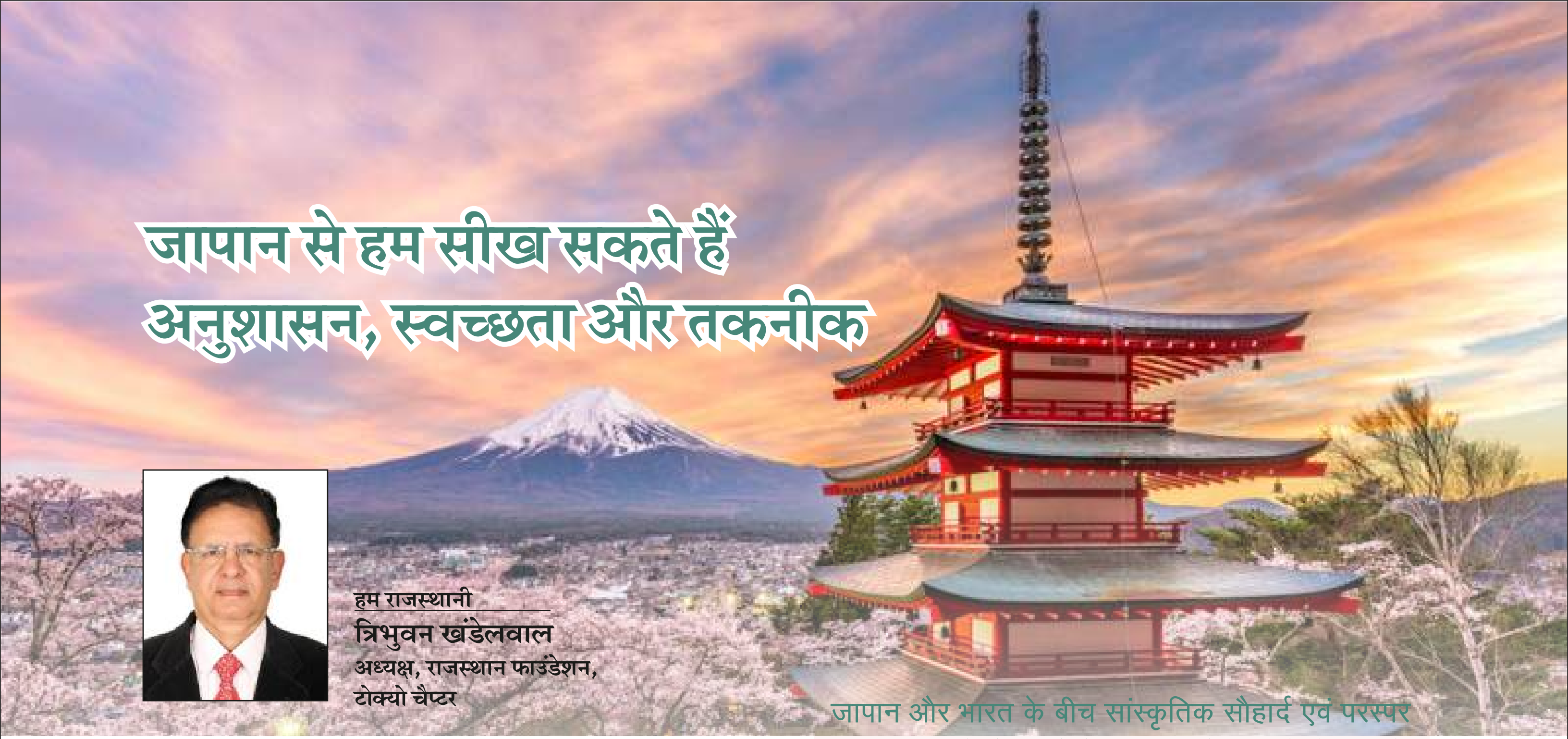

जापान से हम सीख सकते हैं अनुशासन, स्वच्छता और तकनीक

हम राजस्थानी
त्रिभुवन खंडेलवाल
अध्यक्ष, राजस्थान फाउंडेशन, टोक्यो चैप्टर

> जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक सौहार्द एवं परस्पर सम्मान का जो सेतु वर्षों के अनुभव और संबंधों से बना है, वो अत्यंत मूल्यवान है। जापानी समाज भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य, कला और संस्कृति को सम्मान देता है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और अधिक सुदृढ़ होते चले गए हैं। जापानी समाज का आत्मविश्वास, मित्रता और अनुशासन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में विख्यात 'नवाब साहब की हवेली' में रहता हूँ। मेरा बचपन यहीं बीता। 1965 से 1972 तक मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्टस् English Literature की डिग्री हासिल की।

जयपुर में मैंने कलर स्टोन उद्योग का कार्य सीखा और इसी कार्य को बढ़ाने को लेकर मैं टोक्यो आ गया। टोक्यो आने के पीछे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जापान की इकॉनमी का बेहतर होना और मेड इन जापान तो बचपन से सुनते ही आये थे। यहाँ रियल जेम्स के नाम से कंपनी बनाई जो कलर स्टोन का व्यवसाय करती है।

जापान की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी स्वच्छता है। शहरों में कूड़ेदान बहुत कम दिखाई देते है, फिर भी सड़कें निर्मल रहती हैं। लोग अपने कचरे को अपने साथ रखते हैं और घर जाकर उचित निपटान करते हैं। यह व्यवहार केवल व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि सामाजिक अनुशासन का एक सशक्त उदाहरण है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है।

पर्यटन के क्षेत्र में भी जापान का यह अनुशासन और गुणवत्ता–केन्द्रिय सोच अनुकरणीय है। देश की एक–तिहाई जनसंख्या–करीब 4 करोड़ पर्यटक–हर वर्ष यहां जापान घूमने आते हैं। राजस्थान जैसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता से भरपूर प्रदेश में पर्यटन को विश्व स्तर पर प्रमोट करने हेतु यह मॉडल अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जापान में बेहतर रोजगार अवसर बड़े शहरों में केंद्रित हैं, और इसके लिए लंबी दूरी तक करने में बुलेट ट्रेन जैसी तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह तकनीक यहां के कामकाजी लोगों के लिए लाइफ – लाइन है जो उनके समय और धन दोनों की बचत कर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाती है।

जब भी मैं टोक्यो से राजस्थान अपने घर लौटता हूँ, तो अक्सर अपने जापानी परिचितों को साथ लेकर आता हूँ ताकि वे राजस्थान की संस्कृति को अनुभव कर सकें और निवेश के अवसरां को भी समझ सकें। मेरा मानना है कि किसी भी निवेश के लिए दो तत्व अनिवार्य हैं – स्थिर सरकार और स्थिर नीतियाँ।

जापान का समाज अनुशासित, तकनीकी रूप से उत्रत और परिश्रमी है। घरों में हर आयु समूह के सदस्य कार्य में योगदान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, कृषि नवाचार तथा उत्रत तकनीक– इन सभी क्षेत्रों में जापान से सीखकर राजस्थान और भारत बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

दुनिया के नक़्शे पर महज एक डॉट, आज बड़ा बिजनेस सेंटर सिंगापुर

सिंगापुर

दाऊदयाल गुप्ता

प्रेसीडेंट, राजस्थान फाउंडेशन,

सिंगापुर चैप्टर

'सिंगापुर सिटी नेशन है, दुनिया के नक़्शे पर महज एक डॉट से ज्यादा नहीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बड़ा है। यहां की कम्युनिटी छोटी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा है।'

बात वर्ष 1979 की है, जब मैं पहली बार मद्रास से क्रूज़ में बैठकर सिंगापुर आया था घूमने, तो पहले प्यार की तरह सिंगापुर भी पहली नजर में ही मन में उतर गया था। आज से 45 वर्षों पहले का वो सिंगापुर भी उस समय का टेक्सटाइल्स का बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। यहां वियतनाम, कोरिया और जापान से कपडा इम्पोर्ट कर उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। मैंने सिंगापुर से लौटकर घर पर पिताजी से चर्चा की, जो भरतपुर में स्टील ट्रेडिंग के बिजनेस में थे उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने 1981 में यूके में रहने वाले हमारे रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप में यहां टेक्सटाइल सेंटर शुरू किया।

इसके बाद बर्मा में हम यार्न इम्पोर्ट कर टॉवेल्स बनाने और उसे यूएस को एक्सपोर्ट करने लगे। उसके साथ एग्रीकल्चर कमोडिटी में बीन्स और पल्सेस भी एक्सपोर्ट करते थे।बर्मा में लेबर बहुत सस्ती थी और उस समय यूएस के कोई सैंक्शंस भी नहीं थे, फ्री ऑफ़ कोटा मिला हुआ था। कुछ समय बाद में वहां भी सैंक्शंस लगे, तो फिर मैंने टेक्सटाइल से अलग एग्रो– कमोडिटी की यूनिट्स वेस्टर्न अफ्रीका– घाना, मेडागास्कर, तंजानिया, टोगो, गाम्बिया, सेनेगल में लगाई जहाँ से वियतनाम, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में पल्सेस, बीन्स, नट्स, ब्लैक पेपर, लोंग इत्यादि निर्यात करते हैं।

सिंगापुर में राजस्थानियों के करीब एक हजार परिवार रहते हैं। मारवाड़ी मित्र मंडल की स्थापना 20 वर्षों पहले हमने सौ परिवारों के साथ मिलकर की थी। हमारा खाना–पीना, हमारी संस्कृति सब कुछ ही तो अलग था यहां पर, तो आसानी से एसोसिएशन बनाने की स्वीकृति भी नहीं मिली, लेकिन हमने उन्हें कन्वींस कर दिया। अपनी माटी से कितना भी दूर हम लोग रहें, लेकिन अपनी परंपरा और रीति–रिवाजों को साथ रखते हैं। होली, दिवाली, करवाचौथ, गणगौर और तीज त्यौहार गुजराती, सिंधी, मराठी और अन्य भारतीय समुदाय के साथ उल्लासपूर्वक मनाते हैं। यहाँ के डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर जो अभी प्रेजिडेंट हैं श्री थर्मन शनमुगरत्नम भी गेस्ट ऑफ़ ऑनर के तौर पर कार्यक्रम में आये थे।

सिंगापुर प्रोफेशनल्स और बिजनेस क्लास लोगों की जगह है। यहाँ पर पद, पैसा, शोहरत सब कुछ तो मिला। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन की अपैक्स बॉडी में वाइस प्रेजिडेंट के रूप में काम करने का मौका मिला। इससे पहले यहां की सरकार

के अधीन बने संस्थान सिंगापुर इंडिया चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स को 1996 से 2000 चार वर्षों तक लीड करने का अवसर मिला। ये 100 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित संस्था है जिसे किसी ज़माने में पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी विजिट किया था। आज भी इस संस्था में मैं एमेरिटस चेयरमैन के रूप में जुड़ा हुआ हूं। इसी तरह दो बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय डेलीगेशन में भारत की यात्रा पर आने का सुअवसर मिला। अपने ही देश में खास मेहमान की तरह आये थे, बड़ा अनमोल पल था वो।

मेरा मानना है कि राजस्थान में इंवेस्टमेंट्स के स्कोप की कोई कमी नहीं। हां, प्रदेश में पोर्ट की कमी है, ये उनको सीधे प्रभावित कर सकती है, जो एक्सपोर्ट करते हों। लेकिन यहां ट्यूरिज़्म, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में शानदार रिटर्न मिल सकते हैं, बस कलेक्टिव एफर्ट की दरकार है। राजस्थानी कम्युनिटी को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स तो पहले से ही सब जगह बने हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने इन चैप्टर्स को सक्रिय कर दिया है। प्रवासी दिवस पर जयपुर में मेरे साथ कई और भी राजस्थानी मित्र आ रहे हैं। साथ ही डीग में घर भी जाना होगा वहां पिताजी के नाम से भामाशाह योजना में एक स्कूल भी चल रहा है और फिर जब भी आता हूँ तो मथुरा, वृन्दावन की एक परिक्रमा तो बनती ही है।

In conversation with Dr. Sanjay Mishra

□□□

याद आती है वो मरुधरा की माटी

हम राजस्थानी

संजय सारस्वत
अग्रणी फार्मा कारोबारी
आइवरी कोस्ट

मेरा जन्म सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में हुआ। हमारी कुलदेवी का मंदिर फतेहपुर में है। 1918 में मेरे परदादा स्व. श्री माधोप्रसाद जी नमक का व्यापार करने कलकत्ता गए। 1940 के दशक में मेरे दादाजी स्वर्गीय महावीर प्रसादजी सारस्वत ने बिरला में नौकरी की फिर उसे छोड़ कर Water proof और Fire proof mailbags का काम शुरू किया, सरकारी टेंडर का काम था।

मेरे पिताजी स्वर्गीय महेश कुमार जी सारस्वत ने St. Xaviers, Calcutta से Chemistry में B.Tech किया और फिर diversify करके उन्होंने केमिकल्स का काम शुरू किया। फैक्ट्री लिलुआ में थी हावड़ा के पास। bakelite moulding powder बनाते थे जो स्विचेस और कुकर के हैंडल्स बनाने के काम आता है। लेकिन वहां नुकसान होने के बाद अकोला में फिनोल और रेजिंग बनाने की फैक्ट्री लगाई।

मैंने Calcutta से B.Sc. किया। दस साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद आठ साल मैनेजर का काम किया PFIZER नाम की pharma कंपनी में। लेकिन लगातार एक जैसा काम करते ठहराव–सा आ गया था। तो फिर अफ्रीकी देश कैमरून में एक फार्मा कंपनी में कंट्री हेड की पोजीशन पर आ गया जहां स्ट्रेटजी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सभी कुछ देखा। कैमरून में फ्रेंच सीखी जो किसी ज़माने में फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा था। फ्रेंच लोगों ने भी कोई कम अत्याचार नहीं किए, इनका पूरा कल्चर ही बदल दिया। बैंगलोर के सुराणा घराने की माइक्रोलैब्स, स्ट्राइड्स, आरको लैब्स और कैडिला के लिए सेनेगल में जुड़ा। अब तक फार्मा की नब्ज समझ में आ चुकी थी।

मैं सोचता था कि 50 वर्ष के बाद नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी में तनाव मिलना शुरू हो गया था। तो फिर प्रोडक्ट प्रमोशनल एजेंसी शुरू की आईवरी कोस्ट में। लगातार बाहर रहते हैं, तो देश को ज्यादा मिस करते हैं। सेनेगल छोटा–सा देश सहारा रेगिस्तान के नीचे के हिस्से में है, जहां की बालू मिट्टी और आब–औ–हवा राजस्थान की याद दिलाती थी। राजस्थान में फार्मा सेक्टर में निवेश करने का मन है। विदेश में हमें कितनी भी सफलता मिल जाये, उस ख़ुशी को साझा करने का आनंद तो वहीं अपनी मातृभूमि पर ही आता है।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

□□□

सरकार जिस दिन आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर देगी प्रवासियों का निवेश भी सहज आने लगेगा

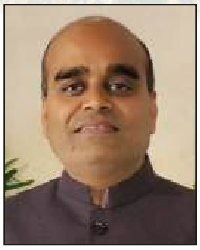

हम राजस्थानी
पंकज डागा
बैंकॉक, थाईलैंड

मेरा जन्म बीकानेर में हुआ था। संयोग से परिवार जयपुर शिफ्ट हुआ और वहां से एम.कॉम। की पढाई की। जयपुर की एक फर्म में नौकरी शुरू की और उसी सिलसिले में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी आने का अवसर मिला। यहां भी नौकरी की और फिर खुद का सेमी प्रेशियस स्टोन्स का काम शुरू किया। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी उद्यमी बहुत आसानी से विदेश नहीं जाता बिजनेस करने के लिए। जब उसे यहां देस में परेशानी होती है, तो वो परदेस का रुख करता है।

जो टैक्सपेयर्स हैं, उनका सम्मान करें

हमारे यहां जो उद्यमी नंबर एक में टैक्स देकर अपना काम कर रहे हैं, उनसे भी 50 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार मैं रोलेक्स की घड़ी पहनकर भारत आया, तो एयरपोर्ट पर ही वो घड़ी मेरे लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई। यहां अफसर हर आदमी को चोर समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

आज उद्यमी ही नहीं, जो भी नागरिक थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में है, उनके घरों की महिलाएं बहुत सामान्य रूप से नाक में डायमंड लौंग, कानों में बाली, गले में चेन, और हाथों में चार सोने की चूड़ियां पहनती ही हैं। इसमें कौनसी नई बात हैं। लेकिन जो नियम कानून बनाते हैं, उन्हें हमारे लोक जीवन, संस्कृति और इतिहास का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। सरकार को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि जो बड़े उद्यमी यहां से बाहर चले जाते हैं, वे आखिर लौटकर आते क्यों नहीं। बड़े उद्यमियों का बाहर जाना अच्छा संकेत नहीं। इससे रोजगार सृजन रुक जाता है, जरूरतमंद लोगों को जॉब नहीं मिलते, साथ ही सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू का बड़ा स्रोत भी हाथ से निकल जाता है।

इसलिए सरकारी मशीनरी में काम करने वाले लोगों को जवाबदेह बनाना होगा। सरकार बताए, कि गलत लोगों की शिकायत किस प्लेटफॉर्म पर आसानी से की जा सकती है। आज दुनिया चीनका रुख क्यों करती है, वहां पर आखिर ऐसा क्या है, जो अपने देश और प्रदेश में नहीं?

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

❑❑❑

Laghu Udyog Bharati had the honour of participating in 7th Pre-Budget Consultation held in New Delhi on 20th Nov. Meeting was chaired by Union Minister for Finance & Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, along with the Union MoS for Finance, Shri PP Chaudhary, focusing on the Banking, Financial Services and Insurance sector for the upcoming Union Budget 2026-27. LUB was represented by General Secretary, Haryana Prant CA Manoj Rungta.

राजस्थानी जैसा जीवठ वाला और मेहनती उद्यमी कहीं नहीं

अंग्रेज 5-6 घंटे में थक कर काम छोड़ देता है, लेकिन हमारा राजस्थानी 18 घंटे काम करके भी दूसरे दिन उसी उत्साह से काम में जुट जाता है।

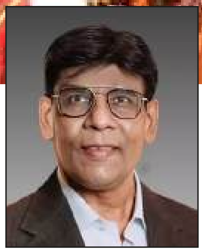

हम राजस्थानी

गणपत कोठारी

प्रमुख उद्यमी एवं समाजसेवी

अध्यक्ष, राजस्थान फाउंडेशन, मुंबई चैप्टर

मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है जिसमें विरार से कोलाबा करीब 30 लाख प्रवासी लोग रहते हैं। अलग–अलग व्यवसाय, उद्योगों, सर्विस सेक्टर में काफी हैं, लेकिन जितने हैं वे सफल उद्यमी हैं।

मेरा जन्म बाड़मेर के जसोल में हुआ था। पिता फालना में प्राइवेट नौकरी करते थे। घर के पीछे ही संघ स्थान पर शाखा लगती थी और वहीं से स्वयंसेवक बने, इस तरह संघ के संपर्क में आये।

आज सिक्किम के जो राज्यपाल हैं श्री ओमप्रकाश माथुर जी, प्रचारक थे और शंकरजी उस समय हमारे जिला कार्यवाह हुआ करते थे। मोतीलाल ओसवाल जैन हॉस्टल में रहते थे एवम् नियमित स्वयंसेवक थे।

पहली बार नौकरी की तलाश में मैं मुंबई आया था 1984 में। कपड़ा बाजार में 6 बरस नौकरी की और काम को समझा। 1989 में जब थोड़ी गुडविल बन गई, तो कपड़ा खरीदकर ट्रेडिंग करने लगा। इसी तरह काम करते–करते 1993 में पाली में पहली प्रोसेस यूनिट शुरू की। और उसके बाद तीन और यूनिट्स का संचालन भी यहां होने लगा। तमिलनाडु में भी काम शुरू किया। तीन लाख मीटर रोज कपड़ा बनाते हैं।

स्पेन में निवेश किया हमने। जब 2005 में स्पेन गया बिजनेस के सिलसिले में, तो कई लोगों से मिलना हुआ। उनमें अंग्रेज भी थे वे 5–6 घंटे से अधिक काम नहीं कर पाते थे। जबकि सुबह से शाम तक काम करके भी हमारे लोगों की वर्क एफिशियन्सी में कोई कमी नहीं आती।

देखिये, उद्यमी क्या करे, सरकार चाहे, तो जयपुर, पाली और जोधपुर ये मिलकर ही यहां नया चाइना खड़ा कर दें। लेकिन इसके लिए पूरे तंत्र को एक दिशा में काम करने की जरूरत होगी। हमारे देखते–देखते दुबई केवल 33 वर्षों में वहां के शासकों की विल पावर से रेगिस्तान से चमन बन गया, तो राजस्थान क्यों नहीं बन सकता?

दूसरी ओर बिहार के रोहतास में डालमिया नगर का उदाहरण भी है जो 38 हजार एकड़ भूमि में फैला हुआ था जहाँ कितने ही कल–कारखाने चलते थे सीमेंट्स, शुगर, पेपर, कैमिकल्स सहित बहुत से उत्पाद यहां बनते थे और हजारों लोगों को रोजी–रोटी भी मिलती थी वहां, लेकिन सरकारी दखलंदाजी और उपेक्षा से उसकी जो दुर्दशा हुई, उसका जीता–जागता उदाहरण है ये औद्योगिक नगरी जो आज जंगल बन गई है।

सरकारी शिथिलता का आलम देखिये कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के समय पाली और जोधपुर के बीच करीब 3 हजार एकड़ औद्योगिक जमीन चिन्हित कर आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

राजस्थान में निवेश को आकार देने के लिए पड़ौसी राज्यों के सिस्टम को समझना होगा। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जन प्रतिनिधि और उद्यमी तीनों का समन्वित प्रतिनिधिमंडल गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर देखे कि उद्योग कैसे वहां निर्बाध रूप से पनप रहे हैं। आज प्रदेश में इंफ्रा पहले से बेहतर है सोलर और खासतौर पर रिफाइनरी से जुड़े उद्योग पनपेंगे।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

पिता ने रेडियो रिपेयर करते हमें उद्यमिता का पाठ सिखा दिया

हम राजस्थानी
सीए राजेश कोठारी
जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान फाउंडेशन, चेन्नई चैप्टर

सोजत के पास गुढ़ा रामसिंह गाँव में हमारा परिवार रहता था। सौ बरस पुरानी बात है, बिलकुल फिल्म की तरह से लगती है ये। 1938 में मेरे दादाजी श्री हीराचंद जी ने कोलकाता जाकर वहां कुछ काम करने की मन में सोची। उन्होंने दादी को भी साथ में लिया और सफर शुरू कर दिया। पहुंचना कोलकाता था, लेकिन दादाजी पहुँच गए चेन्नई। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने परिचय में कुछ पुराने लोगों के बारे में पूछताछ की और आखिरकार चेन्नई में रह कर नए सिरे से जीवन शुरू करने का निश्चय किया।

मेरे पिता की उम्र थी 7 वर्ष उस समय। किन्हीं कारणों से उनकी औपचारिक पढाई–लिखाई ज़्यादा नहीं हो सकी। लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में रुचि थी तो उसीमें कुछ ना कुछ करने लगे। रेडियो उन दिनों हमारे लोक जीवन में छाया हुआ था। सभी घरों में रेडियो तो फैमिली मेंबर की तरह से था ही। उसे बेचने बनाने का काम करतें रहें। फिर 1963 में चिट फाइनेंस का बिज़नेस शुरू किया मगर उसने लोकल पार्टनर की गड़बड़ी से बड़ा नुक़सान उठाना पड़ा।धीरे–धीरे वे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे इस बार थिएटर (सिनेमा हॉल) के प्रोजेक्टर को लगाने और सुधारना चालू किया और उसमें भी उनको सफलता मिल गई। फिर क्या था, पिताजी रातों–रात इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर ही बन चुके थे। इसी काम के सिलसिले में वे मुंबई, अमरावती और ऊपर नॉर्थ इंडिया तक के कई राज्यों में लगातार इसी काम को लेकर आते–जाते रहे। फिर उसके बाद टीवी, वीसीआर और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बाजार में आ गए, और पिताजी उन्हें भी एक्सपर्ट की तरह बखूबी सुधारने लगे। अपने इसी काम को करते हुए पिताजी ने हमें पढ़ाया। उनके मन में इस बात की कसक जरूर थी कि वे नहीं पढ़ सके, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट बना। यहाँ के मुख्यमंत्री का फाइनेंशल एडवाइज़र भी बना।

तमिलनाडु में करीब 10 लाख प्रवासी राजस्थानी रहते हैं जो तिरुचि, कोयम्बटूर, वेल्लोर और कांचीपुरम जैसे स्थानों पर रहते हैं। गोल्ड लैंडिंग ज्वेलरी स्टोर्स और मैन्युफैक्चरिंग में रत हैं, स्टील निर्माण में अग्रवाल, टेक्सटाइल्स में माहेश्वरी और रानी फालना से आने वाले प्रवासी राजस्थानी यूरोप से इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट का काम करने लगे। सभी प्रवासी बिजनेस कम्युनिटी के रूप में स्थापित हो गए। आज इनमें से कई तो ऐसे हैं, जो हजार करोड़ रु. के टर्नओवर से ऊपर निकल चुके।

लाडनूं की जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कोषाध्यक्ष का दायित्व देख रहे श्री कोठारी कहते हैं कि राजस्थान में निवेश कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बस इसके लिए सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। निवेशकों को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि सब प्रवासियों का अपनी जमीन से लगाव तो है ही, सभी चाहते हैं कि देस में उनका भी कुछ न कुछ काम धंधा हो, ताकि उनका आना–जाना यहाँ होता रहे। हमने यहां पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जिसमें 250 श्रमिक काम करते हैं और लगभग सारा प्रोडक्शन रिलायंस की ग्रुप कंपनी को चला जाता है।

चेन्नई में राजस्थानी एसोसिएशन यहां प्रवासियों की बड़ी संस्था है जो उन्हें आपस में जोड़े रखती है। बीते दिनों जब हैदराबाद में प्रवासी प्री–समिट आयोजित की गई, तो हम यहाँ से काफी संख्या में गए। प्रवासी दिवस पर जयपुर हमारे साथ जैन रिसॉर्ट्स वाले, श्री मयंक पारीक, श्री प्रमोद बालोटिया, श्री आदित्य टीबरेवाल और श्री राजेश चन्दन सहित अग्रणी उद्यमीगण पहुँच रहे हैं।

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

नॉर्थ-ईस्ट के चाय-बागानों की धरती से आया एक प्रेरक संदेश

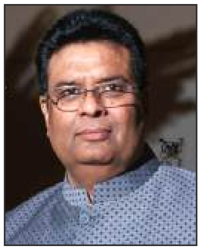

हम राजस्थानी

रतनलाल शर्मा

प्रख्यात उद्यमी एवं प्रेसिडेंट,
राजस्थान फोरम
गुवाहाटी चैप्टर

'जड़ें मजबूत रहें, तो पीढ़ियाँ मजबूत बनती हैं'

दाउदसर की मिट्टी - संस्कार और पहचान

हमारा परिवार पीढ़ियों से चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे के पास दाउदसर गाँव में रहता था। पंडितों का घर था, मेरे दादाजी पंडिताई में आसपास बहुत प्रसिद्ध और सौ बरस पुराने रघुनाथ मंदिर के पुजारी थे। करीब 8 वर्ष की उम्र में दादाजी ने मुझे भी पुरोहित्य का पाठ पढ़ाना शुरू किया। पहली बार नामकरण संस्कार करवाया और दक्षिणा में 1 रुपया मिला – वही मेरी पहली कमाई थी।

कक्षा से आगे - जीवन की पढ़ाई

मेरी स्कूलिंग सुजानगढ़ में दसवीं तक हुई। मैंने तभी समझ लिया कि केवल क्लासरूम की पढ़ाई से आगे बढ़ने की बजाय मुझे काम सीखना चाहिए और ज़िंदगी के असल मैदान में उतरना चाहिए। और मैं भी पिताजी के पास असम आ गया।

संघर्ष, आत्मविश्वास और पिताजी का आशीर्वाद

1984 में मैं गुवाहाटी आया। कॉलेज के 2 वर्ष पढ़ाई की, लेकिन तभी महसूस हुआ कि किताबें ज्ञान दे सकती हैं, पर ज़िंदगी काम से सिखाती है। इसलिए पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह काम में उतर गया।

पिताजी स्क्रैप का व्यवसाय करते थे और असली सीख मुझे उन्हीं के साथ काम करते हुए मिली। बाज़ार का व्यवहार, दुनिया का स्वभाव – सब देखा, पर एक बात दिल में हमेशा साफ रही– "पूरी दुनिया एक पलड़े में रख दो और मेरे पिताजी को दूसरे पलड़े में – तो मेरे लिए पिताजी ही सबसे भारी होंगे।"

मेरे मन में कुछ अलग और बड़ा करने की आग थी। एक दिन पिताजी से कहा– "मुझे कुछ नहीं चाहिए३ न पैसा, न मदद३ बस आपका आशीर्वाद चाहिए।" और फिर 15 फरवरी, 1995 को 0 रुपये से– बिल्कुल शून्य से – बिना किसी की मदद के व्यवसाय शुरू किया।

> **'प्रवासी अपने बच्चों को वर्ष में दो बार राजस्थान भेजें, तो वे भी अपनी जड़ों से जुड़ेंगे।'**

न पूंजी, न पहचान, न सहारा - सिर्फ मेहनत

ईमानदारी और पिताजी के आशीर्वाद के बल पर सफर शुरू हुआ। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो यही लगता है –जिसके पास कुछ नहीं था, वह सब कुछ बना सकता है – बस उसके पास पिता की दुआ और खुद पर भरोसा होना चाहिए।

1996 - उद्योग यात्रा की शुरुआत

लगातार संघर्ष और विश्वास की ताकत से 1996 में गुवाहाटी में रोलिंग मिल की स्थापना की। यहीं से उद्योगों के विस्तार का नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद मेघालय में स्टील यूनिट, अरुणाचल प्रदेश में कोल माइंस, फेरो सिलिकॉन के 7 बड़े प्लांट – जिन्हें आज देश के शीर्ष प्रोडक्शन प्लांट के रूप

में जाना जाता है आज हमारे ग्रुप के उद्योग नॉर्थ–ईस्ट के पाँच प्रमुख राज्यों में सक्रिय हैं – असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और इन राज्यों में प्रमुख कार्य हैं – Steel Industry, Coal Mines, Ferro Silicon Plants, Coke Plant, Hotel & Resort Industry

इन उद्योगों ने हज़ारों लोगों को रोजगार दिया, स्थानीय युवाओं को कौशल विकास दिया, और नॉर्थ–ईस्ट की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया। इसलिए यह सफर केवल व्यापार का नहीं, विकास और जिम्मेदारी का सफर है।

मेफेयर – होटल इंडस्ट्री में सफलता का स्वर्णिम अध्याय

गुवाहाटी में मेफेयर स्प्रिंग वैली रिज़ॉर्ट की स्थापना की। ईश्वर की कृपा से यह प्रॉपर्टी इतनी सुंदर बनी कि देशभर में चर्चित वेडिंग डेस्टिनेशन बन गई। आज लोग जयपुर, कोलकाता, बनारस छोड़कर गुवाहाटी में शादियाँ करने आते हैं, जो एक समय असंभव–सा लगता था।

गुवाहाटी का राजस्थानी समाज – गर्व और जिम्मेदारी

गुवाहाटी में लगभग 2.5 लाख राजस्थानी प्रवासी रहते हैं। 90% ट्रेडिंग में, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन जो भी हैं, सम्मान और पहचान के साथ हैं। हमने यहां उद्योग लगाए, रोजगार दिया, राजस्व दिया और विकास में योगदान किया– पर दिल में राजस्थान के लिए कुछ करने की भावना हमेशा रही।

प्रवासी दिवस – नई उम्मीद और नए अवसर

राजस्थान में भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रवासी समाज में उत्साह और विश्वास और अधिक बढ़ा है। हम भी इस बार प्रवासी दिवस पर जयपुर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हमारा ग्रुप राजस्थान में होटल इंडस्ट्री में निवेश कर रहा है।

अवसर मिल रहा है – तो सरकार भी उद्यमियों को सहूलियत और समय दे। घर में बच्चा जन्म ले, तो 18 साल तक हम उससे कमाई की उम्मीद नहीं रखते – पहले सहारा देते हैं। यही नीति नए उद्योगों पर भी लागू होनी चाहिए।

अंतिम संदेश – अगली पीढ़ियों के नाम

हम प्रवासी यहाँ सफल हुए –पर अगली पीढ़ियों का अपनी जड़ों से जुड़ना और भी जरूरी है। यदि हर प्रवासी अपने बच्चों को वर्ष में दो बार राजस्थान भेज दे, तो वे अपनी संस्कृति, भाषा और परंपरा कभी नहीं भूलेंगे। **यही विरासत, यही पहचान, और यही ताकत है।**

in conversation with Dr. Sanjay Mishra

The evaluation of intern students from Zakir Husain Delhi College, DU was conducted on 21st Nov. through presentations showcasing their learnings and internship experience. The evaluation was carried out by Smt. Aarti Sehgal, General Secretary, LUB Delhi and Dr. Arshpreet Kaur, Nodal Officer - Research & Industry Collaborations.

LUB's New Executive of Madurai Unit (TN) was formed in the presence of State President Dr. VSV Verchezhian and General Secretary Shri R. Kalyansundaram.
The new team reiterated its commitment to expanding the organization and working towards the betterment of the MSME sector.

The LUB's Economic Group meeting was held in the presence of Uttar Pradesh Industrial Development Minister Shri Nand Gopal Gupta, MSME Minister Shri Rakesh Sachan and National President Shri Madhusudan Dadu on 27th Nov. On this occasion, National Jt. General Secretary Shri Rakesh Garg, State President Shri Ravindra Singh and State GS Shri Amit Agarwal presented a copy of Udyog Times to Shri Nandi.

ECONOMIC GROWTH IN RAJASTHAN:
Relative Position, Issues & the Way Forward

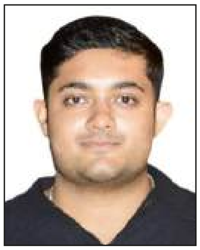

Dr. Varinder Jain
Assistant Professor,
Institute of Development Studies, Jaipur
vjain2007@gmail.com

Dhritiraj Sarma
Senior Researcher,
Institute of Development Studies, Jaipur
sarmadhriiraj000@gmail.com

Introduction

Rajasthan, geographically being the largest state in India, plays a pivotal role in India's economic landscape. Spanning across arid deserts, fertile plains, and rugged hills, the state is rich in natural resources. Additionally, its vibrant cultural heritage, is marked by colourful festivals, traditional arts, and historic forts and palaces. This rich diversity not only attracts national and international tourists but also contributes to a growing market for local artisans and entrepreneurs. However, the inherent strengths of Rajasthan are often diluted by considerable structural challenges, as the state faces persistent water scarcity that affects agricultural productivity and limits industrial growth. Additionally, Rajasthan's distinctive geographical features, such as the vast Thar Desert, pose unique obstacles to infrastructure development and accessibility, particularly in rural areas. Moreover, the state grapples with uneven human development indicators, including literacy rates, healthcare access, and employment opportunities. These disparities highlight the urgent need for comprehensive policy interventions aimed at promoting inclusive growth and sustainable development.

In fact, post-1990 economic reforms unquestionably marked a crucial turning point in India's development trajectory. Rajasthan, like many other states, experienced an uneven impact of these reforms (Ahluwalia, 2000). In the early years following liberalisation, urban centres and resource-rich areas benefited relatively quickly, while other districts, particularly those in arid zones or with weaker infrastructure, were left behind.

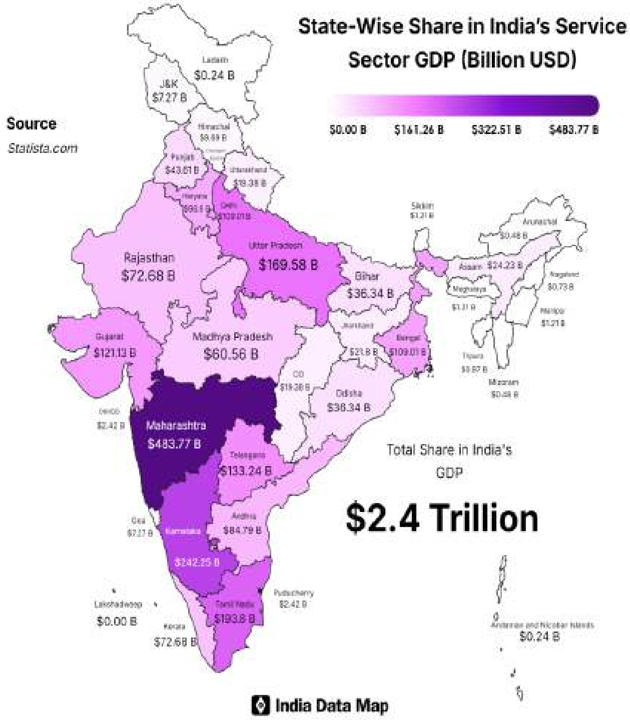

One notable aspect of Rajasthan's recent economic trajectory is the gradual shift from agriculture to industry and services. Although agriculture remains a vital source of rural livelihoods and is particularly important in a state where approximately 73.4% of the population lives in rural areas. However, its share of the Gross State Domestic Product (GSDP) has been declining rapidly. This change is partly due to ongoing water constraints and agro-climatic vulnerabilities, but it also reflects the natural growth of services sector as income rises. In sharp contrast to agriculture, the services sector, especially banking and financial

services, tourism, retail, logistics, and other services, has emerged as the most dynamic contributor to economic output. Additionally, the expansion of renewable energy, particularly solar power generation, has introduced a new dimension to state's economic profile during the past decade.

Rajasthan's industrial sector displays a distinctive blend of both strengths and weaknesses. Across the state, several specialised industrial clusters have taken shape over time. For instance, Bhilwara has grown into a major textile hub, Pali and Rajsamand are recognised for their marble and stone-processing activities, while the Hadoti belt hosts some of the country's prominent cement and mineral-based operations. Kota also records a notable presence in leather and footwear manufacturing. Because many of these industries rely heavily on labour, they have played an important role in generating employment and supporting local economic development. Yet, despite this progress, Rajasthan's industrial profile still lacks the breadth and depth as seen in more advanced industrial states such as Gujarat. Rajasthan's manufacturing base remains comparatively narrow, with limited integration into high-technology production systems or export-driven value chains, which continues to constrain its potential for large-scale industrial transformation (Jain, 2024).

Contemporary Economic Landscape

Rajasthan's contemporary economic landscape reflects a combination of structural shifts, demographic changes and policy-driven developments that have taken place over the past decade (Sharma et al., 2022). The state's Gross State Domestic Product (GSDP) has steadily expanded, with an average annual growth rate of 5.7% from 2011 to 2024. However, it is important to note that growth trajectories have varied significantly across different sectors and districts. Rajasthan's share of the country's nominal GDP has increased only slightly, rising from 5% in 1990-91 to 5.2% by 2021-22. As of 2021-22, the state's nominal per capita income is 10% which is below the national average. In 2023-24, Rajasthan's per capita income stands at ₹90,831, up from ₹57,192 in 2011-12, reflecting an average annual growth rate of 3.71%.

The structural composition of the state economy also continues to evolve. Agriculture, while still a major source of livelihood, now contributes approximately 29.4% of GSDP. Agricultural output is closely linked to monsoon patterns, distribution of irrigation, and groundwater availability. Despite some gains in crop diversification and horticulture, agricultural growth remains volatile, with yield improvements being uneven across districts. While some districts have recorded significant productivity gains, arid and semi-arid regions continue to face persistent climatic and resource-related challenges.

Industry contributes around 27.4% of GSDP as of 2022-23, shaped by a mix of traditional and emerging sectors. Rajasthan hosts some of India's most prominent mineral-based and resource-driven industries, including cement, non-metallic minerals, and stone processing, supported by abundant limestone and marble deposits. The rise of renewable energy, particularly solar power generation, has diversified the industrial landscape, with installed capacity increasing from 1,167 MW in June 2015 to 23,972 MW as of November 2025. However, large-scale, export-intensive manufacturing is still developing gradually, influenced by factors such as logistics connectivity, cluster maturity, and access to skilled labour. In comparison, the agriculture sector's share of Gross Value Added (GSVA) remains above the state average, while the industry's share has been declining and has remained below the state average since 2017.

The services sector has emerged as the principal growth engine in Rajasthan, which contributes 43.2% of GSDP in 2022-23, which is lower than the average share of 51% across all states. In Rajasthan, tourism is one of the most dynamic components, driven by heritage sites, cultural assets, and state-led promotional efforts. Between 2013 and 2019, Rajasthan held an average share of 2.6% of total domestic tourist visits and 6.2% of total foreign tourist visits, generating substantial employment in hospitality, transport, and retail sectors. Banking and financial services, IT-enabled services, and logistics have also expanded, and this can be due to growing urbanisation and rising consumption patterns. Among all major sectors, the banking and insurance sector has demonstrated the highest growth rate in GSVA, averaging at 9.4%, over the last decade (Figure-1).

Figure 1: Decadal Share (%) and Growth Rate (%) across Sectors in Rajasthan 2012-2022

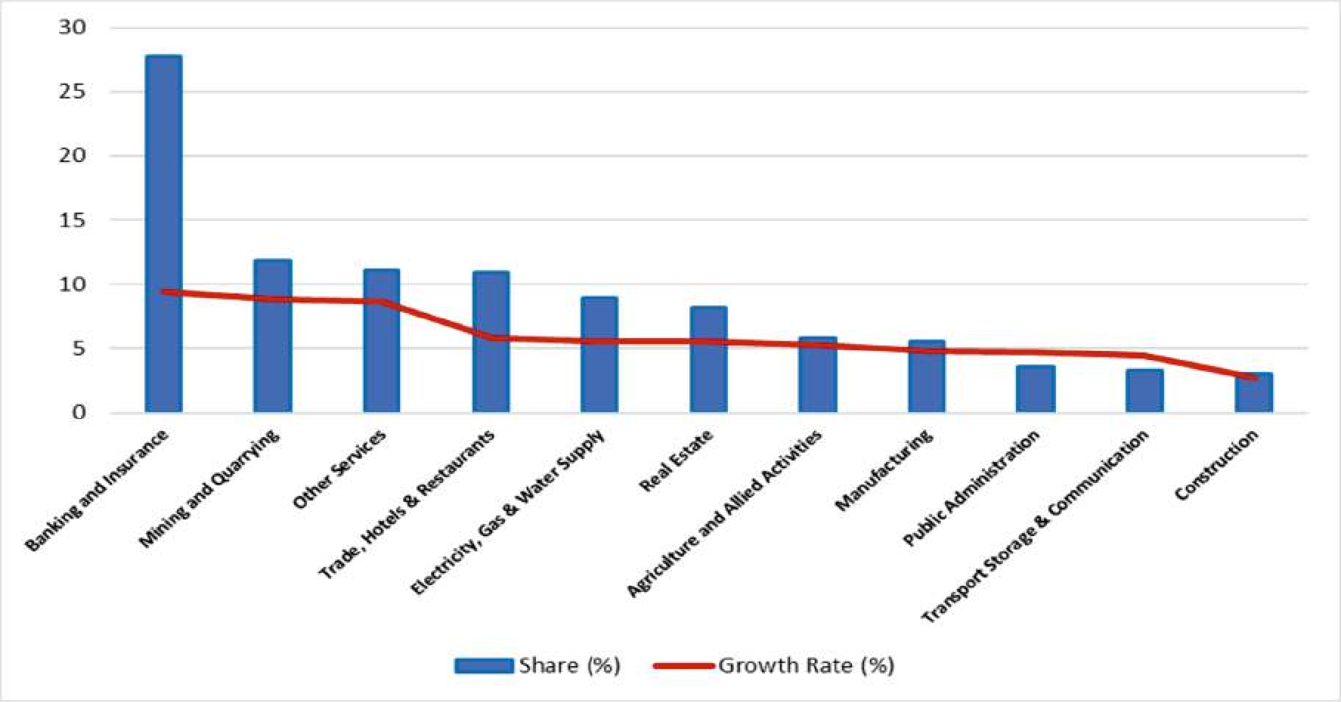

Source: MoSPI, as of August 2023

Labour market indicators also present a complex scenario. According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS), Rajasthan's unemployment rate was estimated at 4.4% for 2022-23, compared to the national average of 3.2% (Figure 2). Female labour force participation in the state is relatively high at 47.9%, in contrast to the national average of 37%. Notably, female labour force participation is predominantly higher in rural areas of Rajasthan, and majority of the female workforce comprises self-employed workers. Furthermore, the state's youth population presents a demographic dividend, which could enhance potential for labour-intensive manufacturing, services, and skill-based industries. However, this potential can only be fully realised through targeted skilling and effective employment policies.

Figure 2: Unemployment in Rajasthan and India (Per Thousand)

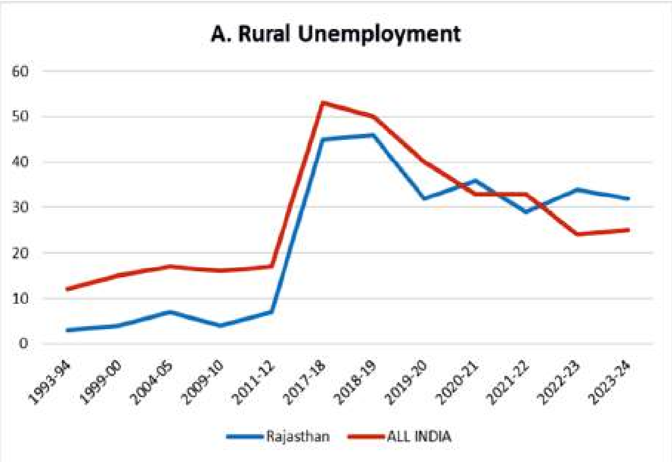

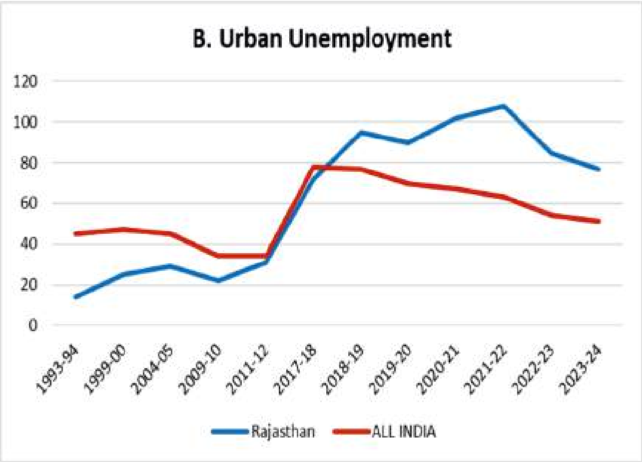

Source: NSSO Employment & Unemployment Survey Reports; NITI Aayog; and Periodic Labour Force Survey (PLFS), NSO it needs to be.

Overall, Rajasthan's contemporary economy shows steady progress, supported by sectoral diversification, infrastructure improvements, and the emergence of new industries. However, the state's future growth will depend on addressing water stress, enhancing manufacturing competitiveness, deepening skill development, and promoting inclusive development across all districts.

Rajasthan's Economic Growth: A Comparative Picture

Rajasthan's aggregate economic performance is best understood relative to its comparable neighbouring states like Gujarat and Madhya Pradesh (Figure 3).

Figure 3: Map showing Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat (from left to right)

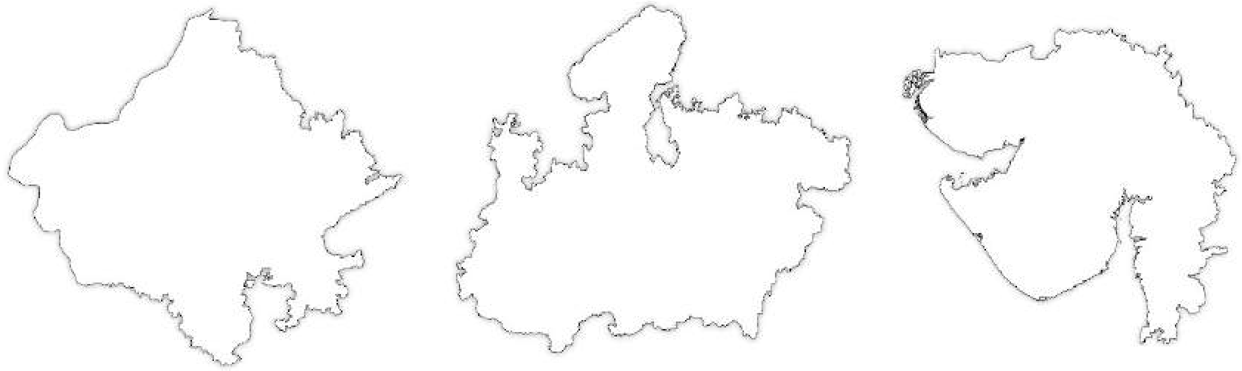

Over 2011 -2023, Rajasthan has typically recorded higher compound annual growth in GSDP with 4.87% as compared to -5.22% of Madhya Pradesh and -3.22% of Gujarat. This indicates that, over the years, Rajasthan's growth trajectory has been more stable and less prone to fluctuations. This is further evident with the annual growth rate of Gross State Domestic Product of these states. From Figure 4, we may observe that Madhya Pradesh initially experienced high peaks during 2016-17, but very steep downturns during Covid-19 times. Gujarat also suggest overall high volatility as the trend in the recent years is seen to be sloping downward. However, Rajasthan exhibit a relatively steady band of 5-8% in most years, with notable recent performances in 2021-22, 2022-23, and 2023-24.

Figure 4: Annual GSDP Growth Rate (%) of selected States

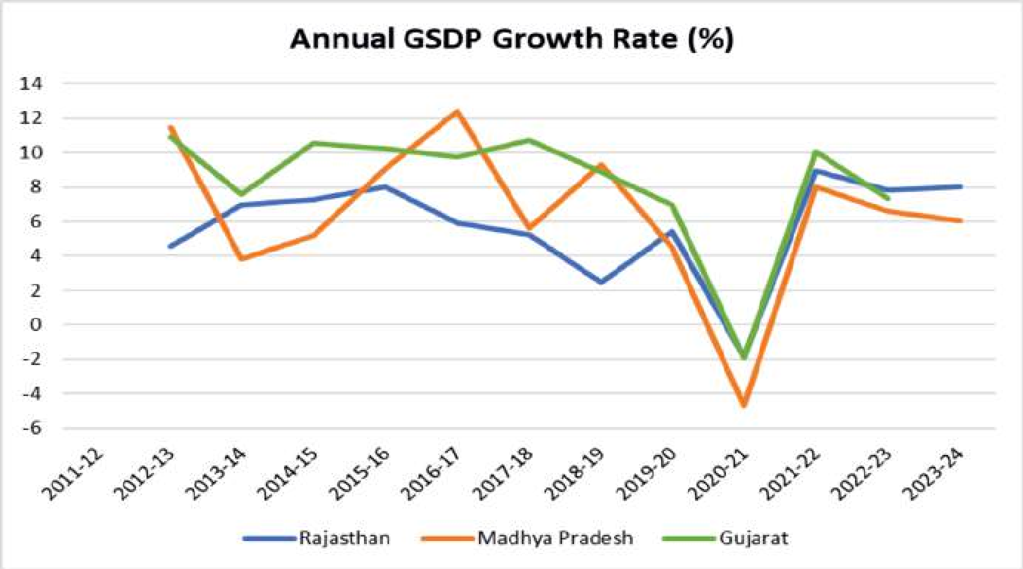

Source: NSO, MoSPI, Govt. of India it need to be

Analysing the Gross Value Added (GVA) by sector provides an understanding of the structural differences between states (Figue 5). Gujarat's GVA profile indicates a significant share of industrial activities followed by services. In contrast, Rajasthan's GVA is more dependent on service sector, followed by industry. Meanwhile, Madhya Pradesh has a relatively larger share of agriculture and agro-processing compared to both Rajasthan and Gujarat. However, both industry and services almost equally contribute to Madhya Pradesh's GSVA. To conclude, over the years, the GVA series reveals Gujarat's deeper industrial base, Madhya Pradesh's rising agro-processing contribution, and Rajasthan's persistent services dominance, albeit with growing industrial clusters.

Figure 5: GSVA Composition (%) among selected States

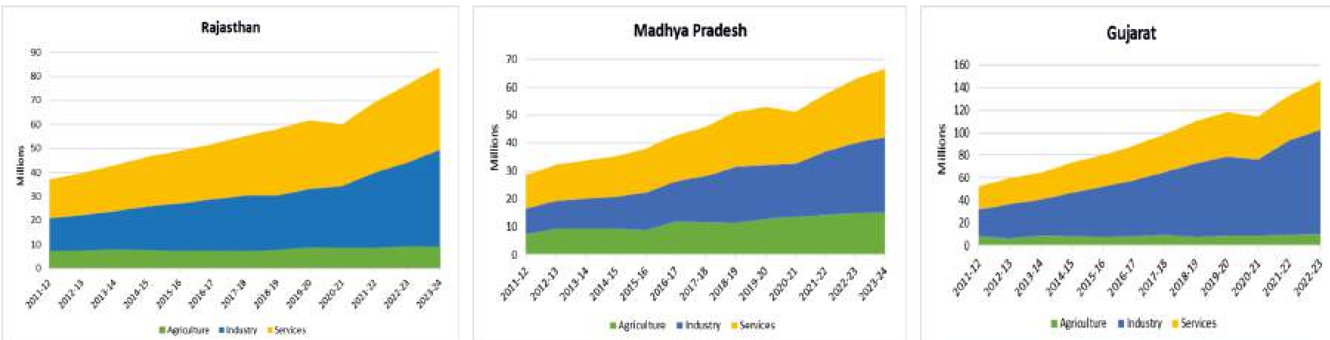

Source: MoSPI, Govt. of India it needs to be

Agriculture

The agriculture sector is structurally important in both Rajasthan and Madhya Pradesh, playing a significant role in employment and the political economy, though the two states exhibit different productivity dynamics. In Rajasthan, the gross cropped area and productivity are heavily influenced by irrigation access and groundwater limitations. In contrast, Madhya Pradesh benefits from larger areas of fertile land and greater irrigation expansion in certain districts.

While Gujarat's agriculture contributes less proportionally to the state's Gross Value Added (GVA), but its commercialised and irrigated segments demonstrate higher yields and stronger value-chain linkages. From 2011 to 2023, Gujarat and Madhya Pradesh experienced more volatility in agricultural growth compared to Rajasthan, as illustrated in Figure 6 below.

Figure 6: Magnitude & Growth of Agriculture GSVA across Selected States

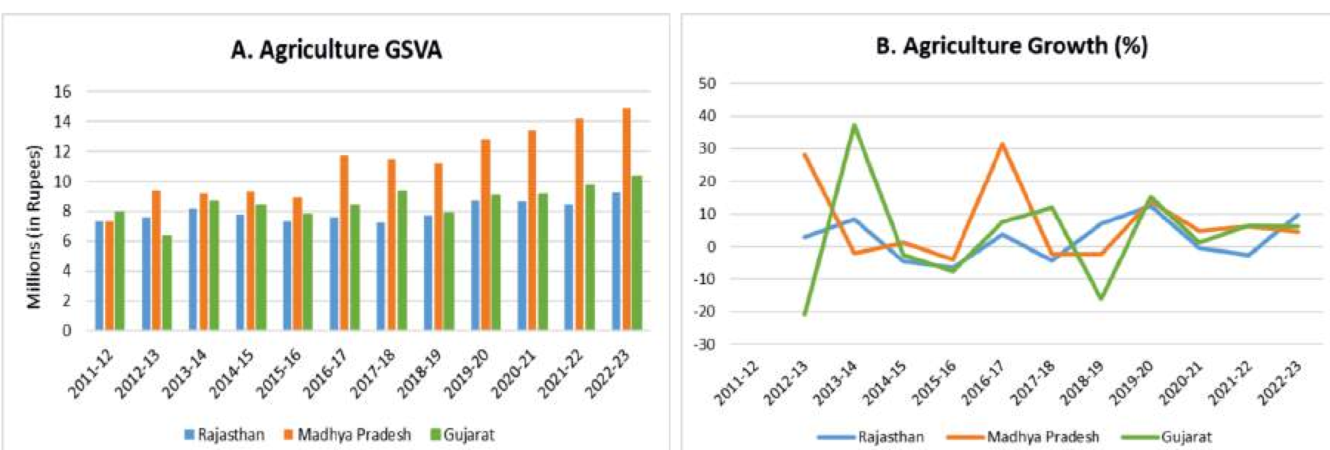

Source: NSO, MoSPI, Govt. of India

Industry

The industrial sector, which includes manufacturing, mining, quarrying, and construction, shows distinct structural differences across the three states (Figure 7). In Gujarat, the industrial base benefits from a strong presence in petrochemicals, engineering, and construction-related activities, supporting steady industrial growth from 2011 to 2023.

In Rajasthan, the industrial sector is shaped by substantial mineral resources, particularly in the mining and quarrying of limestone, marble, gypsum, and other non-metallic minerals. The state also has well-established clusters in textiles, stone processing, and cement production, alongside a growing construction sector driven by infrastructure development.

Madhya Pradesh has experienced significant growth in industrial output in recent years, particularly in food processing, textiles and apparel, automobiles, petrochemicals, and pharmaceuticals, which are gradually strengthening its industrial landscape.

Figure 7: Magnitude & Growth of Industry GSVA across Selected States

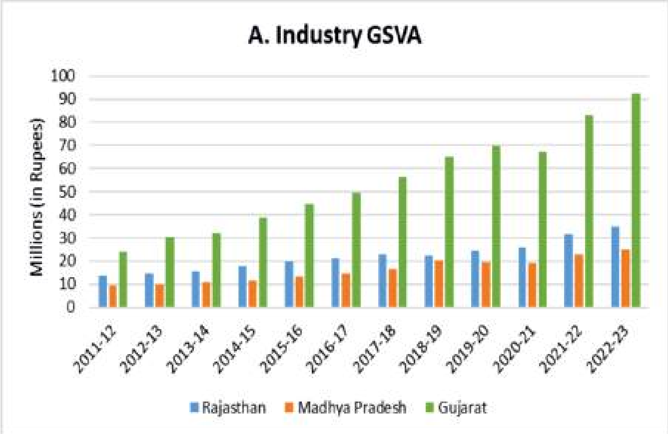

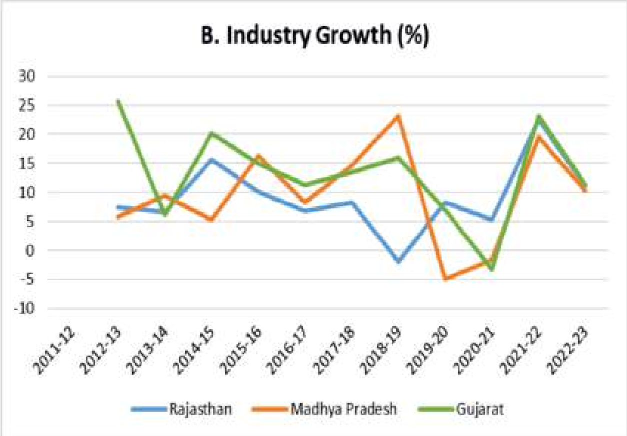

Source: NSO, MoSPI, Govt. of India it needs to be

When compared over an extended period, Gujarat's industrial growth stands out as the most consistent, although it experienced a decline during the COVID-19 pandemic. In contrast, Rajasthan and Madhya Pradesh show moderate yet stable industrial expansion. This trend is linked to their respective natural resource bases and the development of mining and quarrying activities, particularly in Rajasthan. Additionally, the presence of a strong industrial sector, characterised by large-scale industries and factories, is clearly evident in Gujarat, as illustrated in Figure 8 below.

Figure 8: Number of Factories in the Selected States

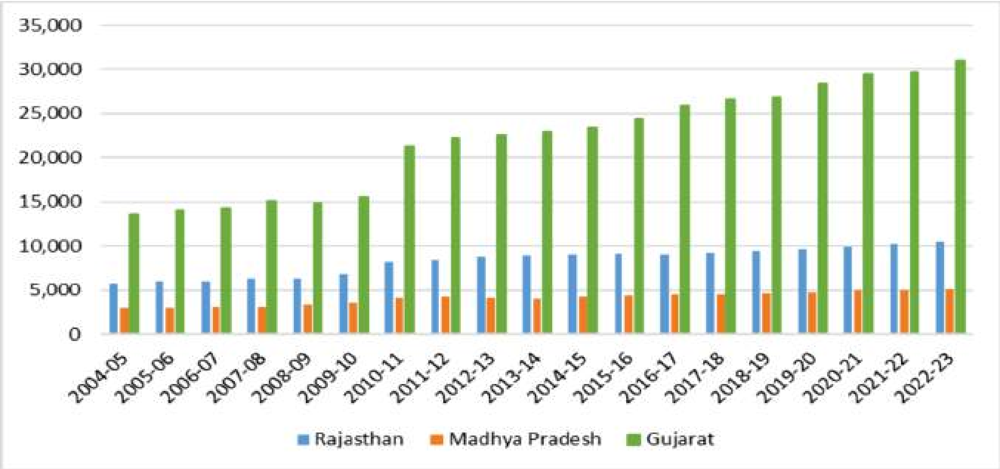

Source: ASI, MoSPI, Govt. of India

Services

The services sector is a key component of Rajasthan's economic structure, with continuous growth in banking and finance, tourism, trade, transport, logistics, and public services contributing to an increase in Gross State Value Added (GSVA) since 2011. Trends from 2011 to 2023 clearly illustrate Rajasthan's consistent upward trajectory in services output, bolstered by banking and finance, and tourism-driven urban centres and growing market activities. In contrast, Gujarat's services sector has a different composition. Its services GSVA is closely tied to industrial and trade activities, with ports, logistics networks, and financial services supporting a significant manufacturing base. Consequently, Gujarat not only reports higher absolute services GSVA but also experiences more pronounced growth during years of robust industrial performance. Madhya Pradesh, on the other hand, shows modest but steady growth in services GSVA, primarily fuelled by trade, hotels and restaurants, public administration, education and health services, and other local services. Although its growth rates are generally lower than those of Gujarat, it aligns more closely with Rajasthan during the recent economic recovery following the COVID-19 pandemic.

Figure 9: Magnitude & Growth of Service GSVA across Selected States

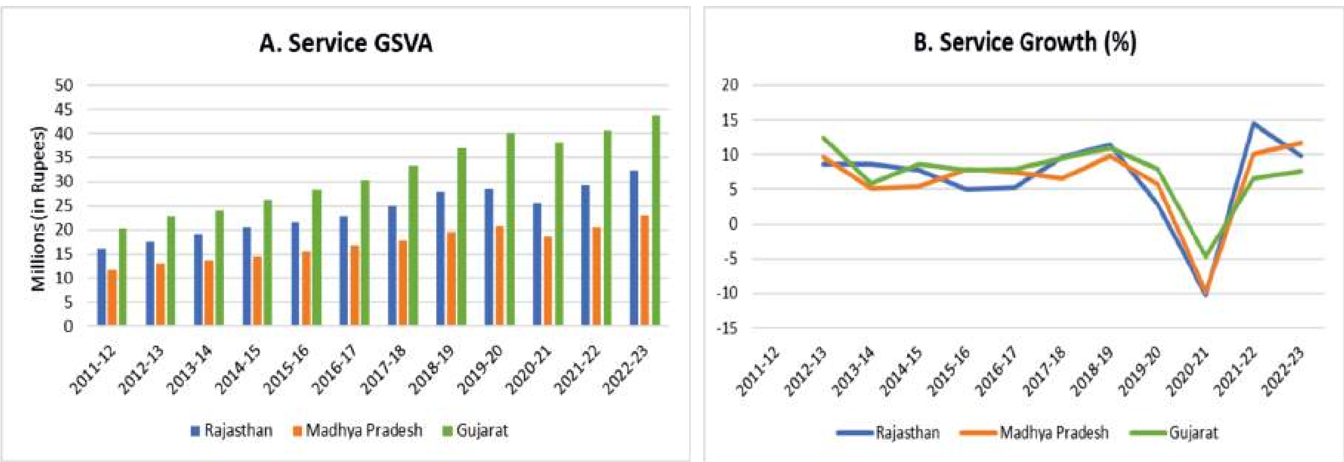

Source: NSO, MoSPI, Govt. of India

When viewed through services' growth rates across 2011-2023, Gujarat typically records continuous stable acceleration due to industry-linked services; however experienced slight decline in 2022-23. Rajasthan, on the other hand, shows moderate but steady growth supported by tourism and urban service activity, and Madhya Pradesh reflects gradual strengthening in public and social services. This is shown in Figure 9 above.

Industry in Rajasthan: Performance, Potential and Policy Priorities

The industrial sector plays an important role in any developing economy. Rajasthan, being endowed with substantial natural resources, benefits from extensive mineral reserves, a diversified textile base, globally recognised stone-processing industries, and a strong cement production network that anchors much of its industrial activity (Vyas et al., 2007). Districts such as Bhilwara, Pali, Chittorgarh, Kota, Rajsamand, Alwar, and Jaipur constitute state's major industrial nodes. Mining and quarrying continue to contribute significantly to state GVA due to abundant deposits of limestone, marble, gypsum, and other non-metallic minerals. Manufacturing relies on both traditional sectors (textiles, handicrafts, stone) and modern industries such as cement, chemicals, engineering goods, and renewable energy components. However, despite these advantages, the industrial sector's share in Rajasthan's GSVA has not expanded at the pace expected for a large state, and growth has often been uneven across sub-sectors. Construction has not shown much growth and manufacturing has mostly remained modest, particularly in technology-intensive and export-oriented segments. Additionally, the pace of industrial growth over the past decade has been steady

but relatively moderate compared to the rapid industrialisation seen in some neighbouring states. As India aims for a developed Bharat by 2047, Rajasthan is positioned to play a vital role as an emerging economic hub. To achieve this, revitalizing the industrial sector is essential for long-term growth, job creation, and enhancing regional competitiveness.

Key Constraints Hindering Industrial Acceleration

The relative slowdown in Rajasthan's industrial trajectory can be traced to several inter-related constraints:

a. Logistics and Connectivity Limitations

Unlike coastal states such as Gujarat, Rajasthan's inland location increases transport costs for bulky and mineral-based goods. Although major highways and freight corridors have improved connectivity, however, last-mile logistics, multimodal integration, and freight-handling capacity require further strengthening.

b. Dependence on Resource-Based Industries

A large share of industrial output comes from minerals and mineral-based processing. While these sectors generate significant value, resource dependence limits diversification into high-value manufacturing and reduces resilience against commodity price cycles.

c. Limited Depth in Technology-Driven Manufacturing

Rajasthan has not yet developed a critical mass of industries in electronics, engineering, machinery, or advanced materials. Technology adoption among MSMEs also remains uneven, affecting productivity and competitiveness.

d. Skilling Gaps and Labour-Market Mismatch

The availability of technically trained manpower remains an enduring concern in Rajasthan. While ITIs and polytechnics exist across districts, yet operational skills, digital competencies, and advanced manufacturing capabilities among the youths needs to be enhanced.

e. Water Stress and Environmental Constraints

Water scarcity affects both industrial siting and operational costs. Sectors such as textiles, leather, and chemical processing require dependable water supply and robust effluent management systems, both of which can constrain expansion.

f. Compliance and Regulatory Bottlenecks

Despite reforms in single-window clearance and digitisation of approvals, procedural overlap, multiple inspections, and delays in environmental and land-related clearances continue to affect investor confidence.

g. Weak MSME Structure Dominated by Micro Enterprises

Rajasthan's MSME landscape is heavily skewed toward micro enterprises, while the number of small enterprises is relatively limited and medium enterprises are almost negligible. This structural imbalance restricts state's ability to build integrated value chains, achieve economies of scale, and foster technology-intensive manufacturing. The absence of a strong pipeline of small and medium enterprises, which typically drive innovation, supply-chain deepening, and export competitiveness, slows the transition from informal, low-productivity activities to higher-value industrial operations.

Why Industry Should Lead Rajasthan's Growth up to 2047?

As India advances toward the vision of Vikasit Bharat 2047, the industrial sector is expected to become a central driver of national transformation by expanding manufacturing capacities, generating high-quality employment, enhancing export competitiveness, and strengthening domestic resilience in strategic sectors. Rajasthan is poised to play an important role in this national agenda due to several inherent advantages. First, with a young population and rising labour force participation, particularly in fast-urbanising districts, the state needs a robust industrial base capable of generating labour-intensive and mid-skilled employment opportunities. Second, Rajasthan enjoys a unique locational advantage within India's industrial corridor architecture, being strategically positioned along the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). This corridor can offer a foundation for high-value logistics, warehousing, and manufacturing hubs that can integrate Rajasthan more closely into national and global value chains. Third, Rajasthan's emergence as India's leading solar power producer provides a competitive edge by enabling low-cost, renewable electricity supply, strengthening Rajasthan's potential as a hub for green manufacturing, battery storage solutions, solar-equipment production, and other

energy-intensive industries. Finally, Rajasthan has considerable scope to diversify its industrial base into high-value sectors such as engineering goods, automobile components, electronics, pharmaceuticals, and advanced textiles. These sectors are aligned with national Production Linked Incentive (PLI) schemes and India's export ambitions. Together, these factors highlight why a dynamic and diversified industrial sector is critical for Rajasthan's long-term economic transformation and for achieving the broader goals of Viksit Bharat 2047 and Rising Rajasthan.

The Way Forward

To accelerate industrial growth, Rajasthan should pursue a coordinated strategy that strengthens infrastructure, deepens industrial diversification, and enhances human capital. Priority should be given to developing integrated industrial corridors, improving last-mile logistics, and expanding reliable water and energy systems. Supporting MSMEs through technology upgradation, credit facilitation, and cluster-based interventions is essential for building competitive value chains. Skill development should be aligned with industry needs through stronger apprenticeship ecosystems and upgraded technical training. Effective environmental governance, streamlined clearances, and digital, time-bound regulatory processes will further improve the business climate. Together, these measures can position Rajasthan as a major industrial driver towards 2047.

Reference

Ahluwalia, M.S. (2000). Economic performance of states in post-reforms period. *Economic and Political weekly*, 1637-1648.

Jain, V. (2024). Rajasthan's Microenterprise amid COVID-19 Crisis: Operational Performance and the Question of Resilience. *Economic and Political weekly,* LIX(17): 64-72.

Sharma, H. & Burark, S., & Kalamkar, S. (2022). Economic Growth and Structural Changes in Rajasthan Economy (1955-56 to 2019-20). *Journal of Agricultural Development and Policy*. 32. 1-16.

Vyas, V.S., Acharya, S., Singh, S., & Sagar, V. (2007). *Rajasthan: The Quest for Sustainable Development*. Institute of Development Studies, Jaipur. Academic Foundation, New Delhi.

❑❑❑

Investment in Value Addition of Minerals in Rajasthan & Employment Generation Prospects

Insights

Madhu Sudan Paliwal
Rtd. Superintending Mining Engineer,
DMG, Rajasthan.
Presently Advisor in RSMML, Udaipur
paliwalms@gmail.com

CA Yogesh Gautam
Former National Treasurer
Laghu Udyog Bharati, Jaipur
ca_ygautam@yahoo.com

Introduction

Rajasthan is often described as a geological archive of India- a state where desert landscapes quietly shelter vast mineral wealth. From extensive limestone belts and the nation's largest rock-phosphate deposit to world-class marble, gypsum, copper, and lead-zinc ores, the state's mineral diversity has shaped national mineral supply chains for decades. With over 82 identified minerals and more than 56 under active extraction, Rajasthan is not only a mining powerhouse but also a strategic supplier of industrial minerals across the country.

Despite this advantage, much of the processing and value addition of key minerals-such as copper concentrate, iron pellets, silica sand, quartz, feldspar, China clay, and soapstone-still takes place outside Rajasthan. This limits job creation, slows local industrialization, and reduces economic multipliers for rural communities. This article examines Rajasthan's mineral base, investment opportunities in value-addition industries, employment prospects, and the challenges and solutions associated with environmentally responsible mineral processing.

1- Mineral Resources of Rajasthan: An Overview

Rajasthan's mineral landscape is broad and commercially significant, offering a wide spectrum of resources that support value-addition industries. The state has extensive limestone deposits, which form the backbone of its cement and lime manufacturing ecosystem. It also

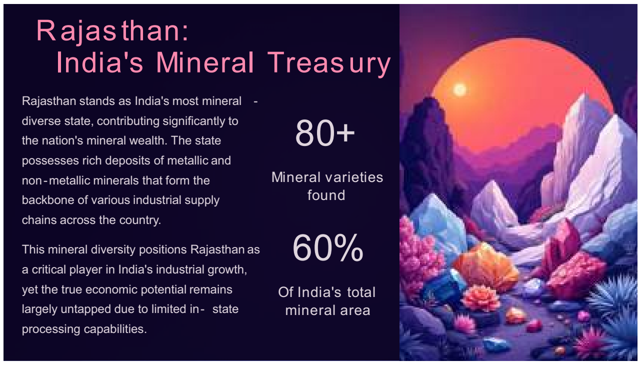

hosts **India's largest commercial rock phosphate deposit at Jhamarkotra,** a resource of national importance for fertilizer production. Rajasthan is a major producer of **gypsum,** widely used in cement, plasters, and agriculture, and it leads the country in the production and export of **marble and dimension** stone, which fuel a vast stone-processing and export-oriented industry. The state is India's only significant source of lead-zinc ores, with integrated smelting operations at Chanderiya, Dariba, and Debari operated by Hindustan Zinc. In addition, Rajasthan possesses a rich suite of other industrial minerals-including **copper, silver, silica sand, feldspar, quartz, China clay, bentonite, and soapstone**-which serve as essential inputs for ceramics, electronics, glass, cosmetics, metallurgy, and advanced manufacturing. Together, this diversity of mineral resources provides a robust foundation for the development of cement plants, fertilizer complexes, stone-processing clusters,

metal smelters, and a wide range of modern mineral-based industries within the state.

2- Industrial Uses of Key Minerals and their Utilization Outside Rajasthan

To understand the value-addition gap in Rajasthan, it is necessary to examine how key minerals are used and where their downstream processing currently takes place.

a) Copper concentrate, produced from copper ore extracted mainly in the Khetri-Jhunjhunu region, continues to leave the state for smelting activities in Jharkhand and for manufacturing in cable, electronics, and alloy industries located in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Jamshedpur, Howrah, Pune, and the Delhi–NCR automotive components belt. Copper derived from this concentrate is essential for electrical wiring and cables, electronic circuits, motors, transformers, brass and bronze alloys, as well as industrial piping systems.

b) Iron ore, mined in the Bhilwara district and converted into iron pellets, also undergoes value addition outside Rajasthan. These pellets are transported to steel plants in Odisha, Chhattisgarh, and Jharkhand, as well as sponge iron units in Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu, and to engineering clusters in Mumbai, Pune, and Hyderabad. The pellets serve as critical inputs for steel manufacturing, blast furnace charge, sponge iron production, and a wide range of construction, automotive, and heavy machinery applications.

c) Silver (Slurry for Refining): - Silver is produced as a by-product during lead–zinc smelting at HZL's complexes in Chanderiya, Dariba, and Debari. The silver slurry generated here is transported outside Rajasthan to specialized refining units in Gujarat and Maharashtra due to the absence of an in-state refinery. Refined silver is then supplied to national jewellery hubs and advanced manufacturing clusters. It is used in Jewellery and ornaments, industrial silver alloys, electrical contacts and conductors, solar photovoltaic cells, catalysis, and photographic applications.

d) Potash and Salt (Brine-Based Minerals): - Rajasthan hosts promising potash-bearing deposits and extensive salt-lake brines across the Nagaur-Ganganagar basin, Didwana, and Sambhar lake region. Since there is no fertilizer-grade potash processing within the state, brine and crude potash material are dispatched to chemical and fertilizer plants in Gujarat and Andhra Pradesh. It is used in Production of Muriate of Potash (MOP) fertilizers, chemical intermediates, water-softening salts, specialty salts for glass and pharmaceutical industries, and industrial reagents.

e) Dolomite (Waste Utilization for Wall Putty & Construction Materials): - Dolomite occurs widely in Bhilwara, Chittorgarh, Udaipur, Sikar, and Alwar, generating substantial mine waste during extraction. This waste is transported to wall-putty and construction-material industries in Gujarat, Uttar Pradesh, and Maharashtra, where it is processed into putty-grade powder. It is used in Wall putty, paints and primers, construction additives, refractories, steel flux applications, ceramics, and low-cost fillers—supporting waste recycling and circular-economy benefits.

f) Overburden / Stone Waste (M-Sand Production): - Stone quarrying across Jodhpur, Ajmer, Bhilwara, Udaipur, Rajsamand, and Jaipur produces large quantities of overburden, slurry, and crusher dust. Due to limited M-Sand clusters in Rajasthan, this waste often moves to Delhi–NCR, Haryana, and western Uttar Pradesh for conversion into manufactured sand. It is used for concrete and masonry work, ready-mix plants, road and infrastructure projects, and as a sustainable substitute for river sand, reducing ecological pressure on riverbeds.

g) Silica Sand, yet much of its processing occurs beyond state borders. Industries in Firozabad (Uttar Pradesh), Gujarat, and Maharashtra use this silica for glass manufacturing, including bottles, flat glass, and fiberglass, while ceramic and electronics units in Tamil Nadu and Karnataka, and filtration plants in Punjab, Haryana, and Delhi rely heavily on it. Silica sand is indispensable for glass, foundry casting, ceramics, water filtration, and electronics-grade silicon.

h) Quartz mined in Rajasthan are similarly processed elsewhere. Ceramic and tile industries in Morbi (Gujarat), engineered stone units in Bengaluru, fiberglass and refractory plants in Tamil Nadu, and electronics manufacturers in Maharashtra constitute the main external consumers. Quartz supports industries producing engineered stone slabs, glass,

ceramics, refractories, electronic components, and high-purity silica powders.

i) feldspar, produced across several districts of Rajasthan, processing and value addition primarily occur in centres such as Morbi in Gujarat-which accounts for over 70 percent of India's tile production-along with Khurja in Uttar Pradesh, and sanitary ware and glaze units in Tamil Nadu, Maharashtra, and other states. Feldspar is a major raw material for ceramic tiles, sanitary ware, glazes, glass production, and electrode manufacturing.

j) China clay (kaolin), concentrated in the western districts of Rajasthan, also undergoes processing outside the state. Paper coating industries in West Bengal, paint and rubber units in Gujarat, porcelain and tableware manufacturers in Tamil Nadu, and cosmetics and pharmaceutical industries in Delhi-NCR and Mumbai rely on Rajasthan's kaolin. Its applications span paper coating, ceramics, porcelain, rubber, paints, cosmetics, and pharmaceutical formulations.

k) Soapstone (talc), largely produced in the southern part of the state, is shipped to processing centers such as Mumbai-Thane for cosmetics, Gujarat for filler industries, Uttar Pradesh for paper mills, Karnataka and Tamil Nadu for ceramic and tile units, and the Delhi–NCR region for pharmaceutical formulations. Talc remains a vital ingredient in cosmetics, rubber and plastic products, paints and paper manufacturing, pharmaceuticals, and ceramics.

3- Additional Mineral Resources with High Potential for In-State Processing: -

a. **Bentonite,** used in drilling muds, foundry binders, and cat litter, offering opportunities for granulation, purification, and export-oriented processing.
b. **Garnet and wollastonite** from districts such as Sirohi and Jodhpur are vital inputs for abrasives, ceramics, and polymer fillers, and can support cluster-based beneficiation units.
c. **Fluorite** deposits in Jaisalmer create prospects for hydrofluoric acid, refrigerant gas, and specialty chemical industries. Rajasthan is also endowed with
d. **Barytes, mica, pyrophyllite,** and ball clay, all of which have established markets in paints, ceramics, rubber, paper, and refractories-sectors that increasingly demand localized processing to reduce import dependence. Additionally, the state's deposits of
e. **sandstone, granite, slate, and quartzite** enable expansion of engineered stone, dimension stone, and tile manufacturing clusters. Together, these diverse minerals provide a broad canvas for attracting beneficiation plants, chemical-processing units, advanced ceramics industries, and value-chain MSMEs, thereby multiplying direct and indirect employment opportunities across mining districts.

Conclusion of this pattern: Rajasthan provides the raw materials, but downstream value-manufacturing, jobs, exports-is captured by other states.

4- Why Value Addition Happens Outside Rajasthan

Despite superior mineral availability, several structural factors limit Rajasthan's own processing capacity. Historical clustering of processing industries in

Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, and eastern India. Proximity of other states to ports and large industrial markets. Higher energy costs in certain Rajasthan districts. Infrastructure gaps in older mining belts. Lack of fully developed processing clusters (stone parks, ceramic zones, smelting clusters)

As a result, raw minerals leave the state while the real economic value-jobs, manufacturing output, and exports-is created elsewhere

5. Government Policies Enabling Value Addition

i. **Rajasthan Mineral Policy 2024:** - Focus on resource augmentation, zero-waste mining, and cluster development. Pre-embedded clearances for mineral block auctions. Explicit targets for employment and mineral-sector GSDP contribution

ii. **Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS 2024):** - Key incentives include: Capital subsidies, Electricity duty exemptions, Stamp duty relaxations, Land allotment facilitation, Special packages for backward districts and employment-generating projects.

iii. **Additional policy tools improving investor confidence:** Cluster CETPs for stone and chemical units, Subsidies for beneficiation plants, Skill development funding for local workforce.

Photo 5 PPT

Investment Opportunities in Rajasthan's Value-Addition Industries

i. **Cement and Lime Manufacturing: -** Rajasthan's limestone belts create ideal conditions for clinker units, grinding units, and lime kilns. Opportunities include waste-heat recovery systems, green fuels, and high-efficiency kilns.

ii. **Phosphate and Fertilizer Processing: -** Proximity to Jhamarkotra enables beneficiation plants, phosphoric acid units, SSP/DAP intermediates, and captive fertilizer complexes. Public–private partnerships can upgrade RSMML's capacity and attract new investors.

iii. **Stone Processing and Engineered Stone:** - Opportunities include automated slab polishing, engineered quartz production, export-oriented units, and cluster-based facilities with CETPs.

iv. **Metal Smelting and Downstream Metallurgy: -** Rajasthan's lead-zinc ores support expansion of smelters, galvanizing units, alloy manufacturing, zinc oxide plants, and secondary metal recycling. Ancillary units (wire drawing, battery materials, specialty alloys) offer high-skilled jobs.

7 Employment Prospects: Direct, Indirect, and Rural Development

i. **Direct Employment: -** Value-addition units require: Technicians, Engineers, Plant operators, Quality control staff, Logistics, maintenance, and safety teams. Large cement, fertilizer, and smelting plants can create hundreds to thousands of direct jobs.

ii. **Indirect Employment: -** Value addition activates extensive supply chains: Transport and logistics, Spare parts, equipment suppliers, Construction, power services, packaging, Service economy (housing, retail, healthcare)

iii. **Rural Development Impacts:** - When processing occurs near mines, benefits accrue locally: Higher local wages, MSMEs in transport, machinery repair, fabrication, Infrastructure upgrades (roads, power lines, water systems), Vocational training and long-term employability for rural youth.

Rajasthan's 2024 Mineral Policy aims to create **50 lakh jobs by 2029–30** and **over 1 crore by 2046-47**, reflecting the multiplier effects of decentralised value addition.\

8 Environmental and Social Challenges

Key concerns include air pollution from kilns, furnaces, and stone-cutting units, along with water stress and untreated effluents from chemical, fertilizer, and stone-processing industries. Solid wastes such as slurry, slag, and tailings create disposal pressures and often degrade nearby land. Mining expansion may also trigger land-use conflicts, displacement issues, and tensions over grazing or agricultural spaces. Occupational health risks—from dust exposure, noise, and unsafe handling of chemicals-remain significant. Additionally, inadequate monitoring, informal labour practices, and limited community participation often intensify these environmental and social pressures, especially in rural belts dependent on mining for livelihoods.

9 Practical Solutions and Mitigation Measures

i. **Circular and Zero-Waste Approaches:** - Beneficiation technologies: - Reuse of stone slurry, phosphor gypsum, slag

ii. **Shared Environmental Infrastructure:** - CETPs in stone and chemical clusters, Common logistics and waste management systems

- **iii. Strong Regulatory Framework:** - Pre-embedded clearances with mine-closure bonds, Biodiversity offsets, Groundwater recharge obligations.
- **iv. Cleaner Technologies:** - Waste-heat recovery, Low-emission smelting, Renewable energy integration.
- **v. Community Safeguards:** - Fair compensation and livelihood restoration, Local hiring commitments, CSR-linked investments in schools, clinics, water systems.
- **vii. Skill Development and Worker Safety:** - Certified training programs, PPE, dust control, medical surveillance.
- **viii. Transparency and Monitoring: -** Real-time emission and effluent monitoring, Public dashboards and grievance systems.

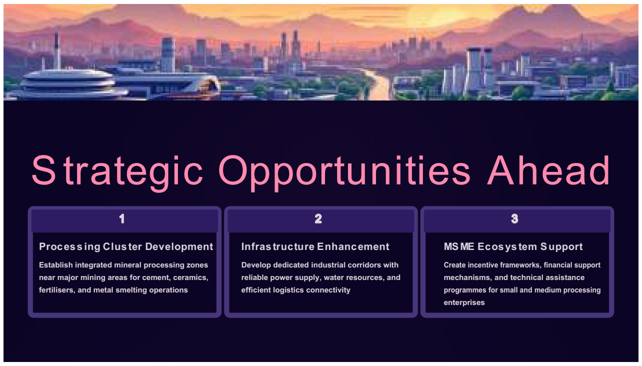

10 Strategy for Enhancing Value Addition in Rajasthan

A focused and systematic strategy is essential for expanding value addition within Rajasthan's mineral sector. The first priority is to develop **processing-near-mine clusters** for industries such as cement, ceramics, engineered stone, fertilizers, and metal smelting. Locating beneficiation and manufacturing units near mineral belts reduces logistics costs, minimises wastage, and generates direct employment in mining districts. A **sector-wise cluster approach** also allows the state to assess the specific needs of each industry—ensuring tailored support in terms of raw material linkages, water supply, energy access, and environmental facilities.

Affordable and reliable **power, natural gas supply, and Common Effluent Treatment Plants (CETPs)** must be strengthened so that value-addition industries can operate efficiently and sustainably. Parallel investment in **logistics hubs, industrial roads, rail sidings, and export infrastructure** will further improve the competitiveness of mineral-based manufacturing.

Rajasthan should expand **R&D centres, mineral testing laboratories, and innovation partnerships** to promote advanced beneficiation, waste utilisation, engineered materials, and low-emission processing technologies. Locating such facilities within clusters can accelerate technological adoption, improve mineral recovery, and support cleaner production.

For MSMEs, the state needs to provide **technology support, incubation facilities, credit guarantees, capital subsidies, and low-interest loans**. These measures will help smaller enterprises acquire modern machinery, meet environmental norms, and integrate into value-addition chains.

Finally, investment incentives should be linked to **environmental compliance, zero-waste mining, circular-economy practices, and local employment generation**. By aligning industrial expansion with sustainability and community welfare, Rajasthan can transform itself from a raw-material supplier into a leading centre of mineral processing, manufacturing, and inclusive economic growth.

Conclusion

Rajasthan's mineral wealth holds the potential to reshape its industrial landscape-provided the state steadily pivots from raw-material extraction toward deeper, technology-enabled value addition. A cluster-based approach for minerals such as copper, iron ore, silica, feldspar, talc, and kaolin, supported by modern infrastructure, power and gas access, CETPs, and R&D facilities, can anchor processing-near-mine ecosystems and reduce the current outflow of concentrates and intermediates. With policies like the Mineral Policy 2024 and RIPS 2024 encouraging investment, green compliance, and MSME participation, Rajasthan is well positioned to attract smelters, advanced ceramics, engineered stone, specialty chemicals, and other downstream industries. If coupled with strong environmental stewardship, effective waste management, and community-inclusive development, these initiatives can generate large-scale employment, diversify district economies, and establish Rajasthan as a leading centre for sustainable and high-value mineral processing in India.

भारतीय सिनेमा और डेस्टिनेशन वेडिंग की नई राजधानी

'राजस्थान'

चर्चा में

अनुराग रायजादा

वरिष्ठ पत्रकार

जयपुर

anuraagraizada@gmail.com

राजस्थान आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य सौंदर्य और अद्वितीय लोक–परंपराएँ न केवल पर्यटन जगत में, बल्कि फिल्म उद्योग और डेस्टिनेशन वेडिंग की दुनिया में भी नई पहचान गढ़ रही हैं। किलों, महलों, हवेलियों और विशाल रेगिस्तानी परिदृश्यों से सजा यह राज्य दशकों से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की पसंदीदा लोकेशन रहा है। इसी विरासत और नैसर्गिक वैभव ने राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में भी देश की पहली पसंद बना दिया है।

राजस्थान का प्रभाव सिनेमा के गोल्डन ईरा से लेकर आज के आधुनिक दौर तक एक समान रहा है। चित्तौड़गढ़ किले में फिल्माए गए गाइड के प्रसिद्ध गीत 'आज फिर जीने की तमन्ना है' से लेकर आमेर के शीश महल में फिल्म 'मुगल–ए–आजम' के दृश्यों तक इन लोकेशंस की गूंज हर

पीढ़ी के दर्शकों के मन में बसती रही है। आमेर, मेहरानगढ़, उदयपुर का सिटी पैलेस, जैसलमेर का सोनार किला, बीकानेर का जूनागढ़ और शेखावटी की हवेलियाँ आज भी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनी हुई हैं।

राजस्थान की खासियत सिर्फ इसका स्थापत्य वैभव नहीं, बल्कि यहाँ का लोक–जीवन, रंग, रसानुभूति और मेहमाननवाजी है, जो हर प्रोजेक्ट को और अधिक जीवंत बना देती है। यही वजह है कि बीते एक वर्ष में राजस्थान में वेब सीरीज, फीचर फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज़, विज्ञापन फिल्मों और टीवी शो की रिकॉर्ड संख्या शूट हुई।

राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग में भी पहली पसंद बना हुआ है। आज देश की लगभग 70% हैरिटेज प्रॉपर्टीज राजस्थान में स्थित हैं, यह तथ्य ही राज्य की

समृद्धता और विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर वर्षों से डेस्टिनेशन वेडिंग की राजधानी रहे हैं, लेकिन अब बीकानेर, डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर, करौली, पाली, राजसमंद जैसे जिले भी तेजी से विश्वस्तरीय वेडिंग लोकेशन के रूप में उभर रहे हैं।

राजस्थान के 120 से अधिक किले–महलों में होने वाली शादियाँ न केवल भव्य होती हैं, बल्कि समारोह को जीवन भर

का अनुभव बना देती हैं। जब ये ऐतिहासिक धरोहरें विवाह के रंग से दमकती हैं, तो वे वास्तव में परीकथाओं के महलों जैसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। राजस्थान का विज़न है कि यहाँ का हर जिला पर्यटन और विवाह समारोहों की नई मंज़िल बने। इसी दिशा में "WED IN INDIA EXPO, 2024" जैसे आयोजन महत्वपूर्ण साबित हुए, जिन्होंने वैश्विक वेडिंग इंडस्ट्री का ध्यान राजस्थान की ओर खींचा।

राजस्थान में बीते एक वर्ष में शूट हुए प्रमुख प्रोजेक्ट

वेब सीरीज–

फ्रीडम ऑफ मिडनाइट (जयपुर), दिल्ली क्राइम सीजन–3 (झुंझुनू–सीकर), मॉड' (जयपुर), नीट (कोटा), को–एड (जोधपुर), लॉस मोंटानेर (जयपुर), फ्रीडम एट मिडनाइट (जोधपुर)

डॉक्यूमेंट्री–

सेकाई सन – द वर्ल्ड हेरिटेज (जयपुर), क्रूज़िंग विद सुसान कालमैन (जयपुर), साइक्लिंग फॉर लव (जोधपुर)

विज्ञापन फिल्में–

ह्युंडई भारत, हार्ले डेविडसन, ऑरेलिया क्लोथ्स, एमजी साइबरस्टर, कास्ट्रोल, टीवीएस शूट (जयपुर व जोधपुर)

टीवी शो–

क्राइम पेट्रोल, पेकिंग एक्सप्रेस (जयपुर–अजमेर–जोधपुर), प्यार टेस्टिंग (जयपुर), दिल को तुमसे प्यार हुआ (जोधपुर)

टीवी सीरियल–

त्रिवेणी (जयपुर), दुर्गा (जोधपुर)

फीचर फिल्में (मुख्य)–

खेल खेल में (उदयपुर), हिट–द थर्ड केस (जयपुर–झुंझुनू), जॉली एलएलबी 3 (अजमेर), सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (जयपुर–उदयपुर), लंदन ठुमकदा (जयपुर), मुरदाबाद (जयपुर), रू–ब–रू (जोधपुर), सफेद (कोटा), 120 बहादुर (झुंझुनू), एनबीके–109 (जयपुर), रेड–2 (नागौर–जोधपुर), तेरे बिना (अजमेर), डीजे मारवाड़ (जोधपुर), कोरोलेक ऑफ माय लव (जोधपुर), कुली (जयपुर ग्रामीण)

म्यूजिक वीडियो–

वे रांझणा (जोधपुर), राम जी (जयपुर), मिलन (जयपुर), प्यार की हद (जोधपुर)

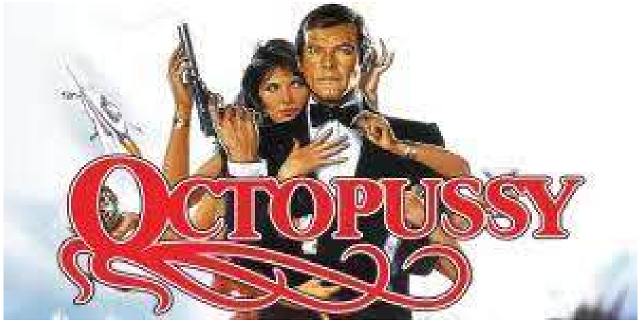

दुनिया की पाँच प्रतिष्ठित फ़िल्में जो राजस्थान में शूट हुईं–

गांधी, अक्टोपसी (जेम्स बॉन्ड), द फोर पवेलियन्स, हीट एंड डस्ट, हॉली स्मोक।

बॉलीवुड की 30 बड़ी फिल्में जिनका राजस्थान से गहरा नाता–

बाजीराव मस्तानी, धनक, जोधा अकबर, बजरंगी भाईजान, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बोल बच्चन, राम–लीला, हाईवे, खूबसूरत, पीके, डोर, पहेली, प्रेम रतन धन पायो, रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, ये जवानी है दीवानी, भूल भुलैया, बड़े मियां छोटे मियां, वीर, नमस्ते लंदन, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ–साथ हैं, गाइड, करण अर्जुन, बादशाहो, बॉर्डर, दिल्ली–6, मुगल–ए–आजम, मणिकर्णिका, परमाणु–द स्टोरी ऑफ पोखरण

माधुरी दीक्षित–अनिल कपूर पर फिल्माया 'धक–धक करने लगा मोरा जिया डरने लगा' गीत जयपुर की कनक घाटी में फिल्माया गया और यह गीत आज भारतीय सिनेमा के इतिहास का अमर गीत बन चुका है।

सेलिब्रिटी शादियों ने राजस्थान की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया है–

प्रियंका–निक, कटरीना–विक्की, कियारा–सिद्धार्थ, ईशा अंबानी–आनंद पीरामल, परिणीति–राघव और हॉलीवुड अभिनेत्री एलिज़ाबेथ हर्ले–सबने राजस्थान को ही चुना।

राजस्थान को 2024-25 में प्राप्त सम्मान–

- Most Promising Wedding Destination (पटना)
- Wedding Destination of the Year (हैदराबाद)
- Best Wedding Destination Award (नई दिल्ली)

राज्य की विविधता– रेगिस्तान, पर्वत, वन, झीलें, किले, हवेलियाँ, संगीत, नृत्य और अतिथि सत्कार–इसे विश्व का सबसे आकर्षक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की क्षमता रखती है।

आईफा-2025: राजस्थान को वैश्विक मंच पर पहुँचाने वाला आयोजन

जयपुर में हाल ही में आयोजित IIFA-2025 का सिल्वर जुबली समारोह राजस्थान के लिए ऐतिहासिक रहा। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मंचों में से एक यह आयोजन न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने ले गया, बल्कि फिल्म पर्यटन, होटल उद्योग और इवेंट सेक्टर के लिए नए अवसर भी लेकर आया। ☐☐☐

उदयपुर को मिला 'बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन' अवॉर्ड

झीलों की नगरी उदयपुर ने वेडिंग टूरिज्म में अपने महत्व को एक बार फिर साबित करते हुए आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स–2025 में 'बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन' का खिताब हासिल किया। नई दिल्ली स्थित हयात रीजेंसी में आयोजित समारोह में सिक्किम के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री टी.टी। भूटिया ने राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक श्री आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक (उदयपुर) श्रीमती सुमिता सारोच को प्रदान किया।

उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने उदयपुर बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि "डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद रहा है। हमारे किले, महल और हवेलियां सिर्फ संरचनाएं नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास की जीवंत आत्मा हैं।" यहां की खूबसूरती, वातावरण और परंपराएं शादी को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहने देतीं, यहां वह एक यादगार अनुभव बन जाती है।"

PRAVASI RAJASTHANI DIVAS
10 DEC 2025 • JAIPUR

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

2 साल
नव उत्थान - नई पहचान
बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान

श्री भजन लाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना

1.36 करोड़
पंजीकृत परिवार

₹ 25 लाख
तक का कैशलेस उपचार

1800
से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध

2200
से अधिक पैकेज

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73-डे केयर पैकेज

बच्चों से बुजुर्गों तक हर वर्ग के लिए पैकेज

औसतन प्रतिदिन लाभ लेने वाले मरीज 10000 से अधिक

प्रतिदिन बुक क्लेमकी राशि 10 करोड़ से अधिक

प्रदेश के बाहर उपचार के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द प्रारम्भ

NATIONAL HEALTH MISSION

PM-JAY

MAA-YOJANA

राजस्थान

स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए टोल फ्री नं. 104 /108 पर कॉल करें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

राजस्थानी माइंडसेट– सफलता का अनकहा रहस्य

मारवाड़ी

अयोध्या प्रसाद गौड़

हेड, स्टेकहोल्डर रिलेशन्स

केयर्न ऑयल एंड गैस (वेदांता लिमिटेड)

बाड़मेर (राज.)

ayodhyag@gmail.com

राजस्थान की मिट्टी में कुछ ऐसा है, जो साधारण इंसान को असाधारण व्यापारी बना देती है। दुनिया भर में जब "मारवाड़ी" या "राजस्थानी बिजनेसमैन" का नाम लिया जाता है, तो लोग अपने आप ही सम्मान से सिर झुका लेते हैं। कोलकाता से चेन्नई, मुंबई से लंदन तक, राजस्थानी उद्यमियों का डंका बजता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस रेगिस्तान की धूप में ऐसा कौन–सा जादू है जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी धन और सम्मान बढ़ाता चला जाता है?

जोखिम लेने की आदत

राजस्थानी व्यापारी जोखिम से डरता नहीं, उसे गले लगाता है। लेकिन यह जोखिम अंधा नहीं होता। बचपन से ही बच्चे दुकान पर बैठकर ग्राहकों को तौलना, माल की कीमत समझना और मुनाफे का हिसाब लगाना सीखते हैं। मेरे पड़ोस में किशोरवय में लड़के हिसाब–किताब और क्रेडिट–डेबिट संभालने लगते हैं। यही वजह है कि जब बाकी लोग कॉलेज में डिग्री ले रहे होते हैं, तब राजस्थानी युवा पहले से ही बिजनेस की बारीकियां जान चुका होता है। जोखिम लेते हैं, पर कैलकुलेटेड।

पैसा ही पैसे को खींचता है

राजस्थानी घर में एक कहावत बहुत प्रचलित है– "नकद ही नारायण है"। इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल पैसे की पूजा करते हैं, बल्कि यह कि हम पैसे की कीमत समझते हैं। एक रुपया बचाना मतलब एक रुपया कमाना। मैंने अपनी मां को देखा है जो आज भी घर में बची हुई रोटी को सुखाकर चूरमा बनाती हैं। फिजूलखर्ची नाम की कोई चीज नहीं।

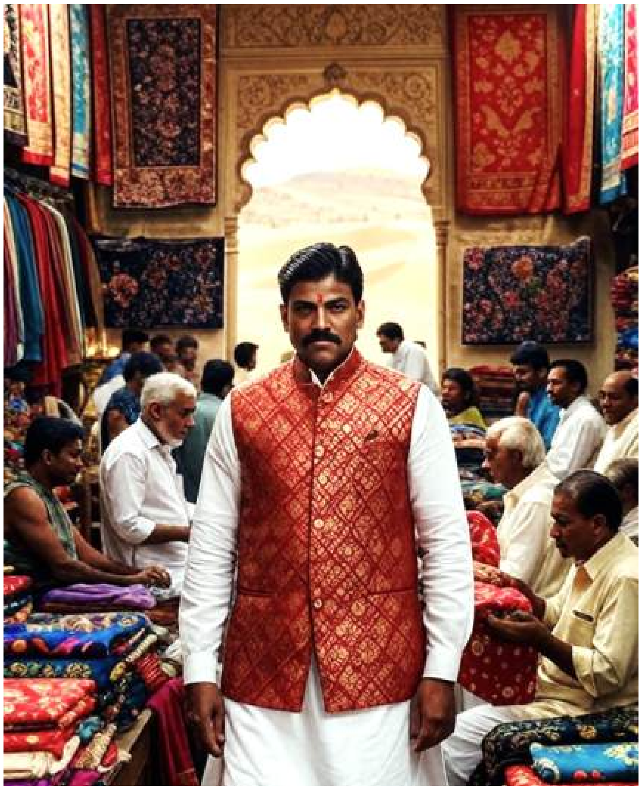

लग्जरी खरीदनी भी हो, तो पहले यह सवाल जरूर पूछते हैं– "इसे बाद में बेच सकेंगे या नहीं?" यही सोच आज की पीढ़ी को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में आगे रखती है।

संयुक्त परिवार – ताकत का असली स्रोत

आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है, पर राजस्थानी अभी भी बीस और पच्चीस लोगों के संयुक्त परिवार में रहते हैं। इसमें स्वतंत्रता कम लगती है, लेकिन सुरक्षा और अवसर बहुत ज्यादा हैं। बिजनेस में नुकसान हुआ? चिंता मत करो, चाचा–ताऊ मिलकर नया माल खड़ा कर देंगे। किसी को नया बिजनेस शुरू करना है? पूंजी घर से ही जुट जाएगी, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। यही सामूहिक ताकत मारवाड़ियों को बाहरी उधार और ऊंचे ब्याज से बचाती है। यही कारण है कि उन्नीसवीं सदी में जब बाकी समुदाय साहूकारों के जाल में फंसे थे, मारवाड़ी खुद साहूकार बन गए।

विश्वास और रिश्ते – सबसे बड़ी पूंजी

राजस्थानी व्यापारी का "बही–खाता" केवल नंबरों का नहीं, विश्वास का भी होता है। एक बार जिसके साथ हाथ मिला लिया, पीढ़ियों तक रिश्ता चलता है। कोलकाता के जूट मिलों से लेकर दुबई के डायमंड मार्केट तक, राजस्थानी नेटवर्क इतना मजबूत है कि बिना बैंक गारंटी के करोड़ों का माल एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है। "मेरा माल, मेरा भाई" – यही नीति है।

अनुशासन और धैर्य

आसाम में जोरहाट से सटे छोटे गांव में मैने मारवाड़ियों की कई दुकानें देखीं। उनकी दिनचर्या बहुत ही अनुशासन वाली है। सुबह पांच बजे उठना, पूजा–पाठ के बाद दुकान खोलना, रात दस बजे तक हिसाब करना – यह दिनचर्या नहीं, साधना है। राजस्थानी व्यापारी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। कीमत गिरी है, तो माल रख लो, एक दिन जरूर चढ़ेगी। यही धैर्य आज स्टॉक मार्केट में भी काम आता है। जब बाकी लोग घबराकर बेच देते हैं, मारवाड़ी खरीदता है।

शिक्षा का नया रूप

पुराने जमाने में पाठशाला कम, दुकान ज्यादा थी। आज भी बिजनेस फैमिली के बच्चे MBA जरूर करते हैं, लेकिन डिग्री से ज्यादा महत्व दुकान पर बिताए समय को देते हैं। कुमकुम जैन अठारह साल की है और कॉलेज के साथ–साथ पापा के टेक्सटाइल शोरूम पर बैठती है। ग्राहक का मन पढ़ना, कपड़े की क्वालिटी पहचानना, बारगेनिंग करना – ये किताबों में नहीं सिखाया जाता।

नई पीढ़ी, नई सोच – फिर भी जड़ें मजबूत

आज का राजस्थानी ळमर्द स्टार्टअप, ई–कॉमर्स, क्रिप्टो, ग्लोबल ट्रेडिंग में है। लेकिन मूल मंत्र वही है – कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ, सही समय पर निवेश करो, और परिवार के साथ मिलकर बढ़ो। हम लग्जरी चाहते हैं, लेकिन उसे भी निवेश की नजर से देखते हैं। कुमकुम की तरह कई लड़कियां हैं जो पच्चीस साल की उम्र तक दुनिया घूमने का प्लान खुद के पैसों से बना रही हैं – वो भी बिजनेस नेटवर्किंग के लिए।

राजस्थानी शुरू से ही भारतीय वाणिज्य का एक रोचक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहा है। वह एक तरफ़ तो अंतिम पैसे तक की हिसाब–किताब करने में माहिर है, दूसरी तरफ़

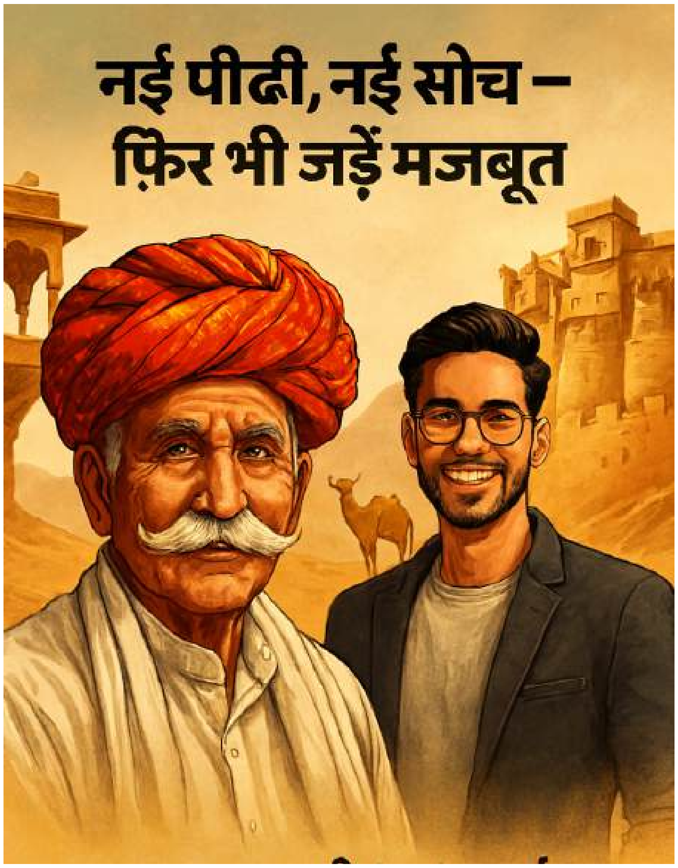

इतना उदार कि ज़रूरतमंद के लिए अपनी जेबें खाली कर देता है, बिना यह सोचे कि बदले में कुछ मिलेगा भी या नहीं। सामान्य "लालची बनिया" की छवि से कोसों दूर ये लोग निःस्वार्थ सहायता के लिए प्रसिद्ध हैं। कितनी ही कहानियाँ मशहूर हैं कि दूर के रिश्तेदार या गाँव के किसी अजनबी को तकलीफ़ में देखते ही मारवाड़ी सेठ तुरंत रुपया भेज देते थे, बेटियों की शादी करवा देते थे, कर्ज़ चुकता कर देते थे–न कोई हिसाब रखते, न कभी उस नेकी का ढिंढोरा पीटते। अकाल हो, महामारी हो या बँटवारे के दंगे, गोदाम खोलकर हज़ारों लोगों को खिलाने वाला अक्सर कोई मारवाड़ी फर्म ही होता था। बदले में बस यही कहते, "हमारे लिए दुआ करना।" यह आपसी सहयोग की भावना पूरे समुदाय में रग–रग में बसी है। गाँव से कलकत्ता, बम्बई या किसी छोटे–से कस्बे में जाने वाला नौजवान सिर्फ़ एक "परचा" (पर्ची) लेकर निकलता था। वहाँ पहुँचा नहीं कि स्थापित मारवाड़ी सेठ–जो ख़ून के रिश्ते में पूरी तरह अजनबी होते थे–उसे घर में जगह देते, खाना खिलाते, व्यापार सिखाते और माल उधार दे देते। न ब्याज, न कागज़ी करार; बस एक मिश्री का टुकड़ा मुँह में डालकर कहते, "भरोसो राखजो।"

मारवाड़ी का सबसे बड़ा गुण है उसका निःस्वार्थ सहयोग। वह अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ता—चाहे व्यापार में हो या जीवन की किसी विपदा में। यही कारण है कि बिना किसी सरकारी मदद के यह समुदाय सैकड़ों वर्षों से देश—विदेश में फैलता चला गया।

अमेरिकी विद्वान थॉमस ए. टिम्बर्ग अपनी क्लासिक किताब "The Marwaris: From Jagat Seth to the Birlas" में कहते हैं: "भारत में, बल्कि शायद दुनिया में कहीं और, ऐसा कुशल, अनौपचारिक मगर लगभग अचूक आपसी सहायता तंत्र नहीं मिलता जो सिर्फ़ प्रतिष्ठा और समुदाय के प्रतिबंध पर टिका हो। ऋण, जानकारी, विवाह—संबंध, दान—सब कुछ अदृश्य मगर अटूट विश्वास के नेटवर्क से बहता है।"

गुरचरण दास अपनी किताब "इंडिया अनबाउंड" में 1947 के बँटवारे का ज़िक्र करते हुए बताते हैं कि लाहौर—कराची के मारवाड़ी व्यापारियों ने चुपचाप बॉर्डर पार करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए ताकि शरणार्थी भाई दिल्ली—कानपुर में नया जीवन शुरू कर सकें— न रसीद, न ब्याज, न कोई प्रचार।

व्यापार में तलवार की तरह तेज़ दिमाग और दिल में समंदर जैसी उदारता का यह अनोखा मेल ही वह जादू है जिसने शेखावाटी के धूल भरे हवेलियों से निकले नंगे पाँव लड़कों को बिड़ला, गोयनका, बजाज, सिंहानिया जैसे उद्योग सम्राट बना दिया। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान का वह पुराना उसूल नहीं भुलायाः "रुपयों हाथ रो, भाई साथ रो"

अंत में राजस्थानी माइंडसेट कोई जादू नहीं है। यह तो बस कुछ साधारण नियमों का पालन है – मेहनत, ईमानदारी, बचत, धैर्य, और परिवार। रेगिस्तान ने हमें सिखाया कि जहां कुछ नहीं उगता, वहां भी हीरे निकल सकते हैं। बस नजर सही होनी चाहिए।

आज जब दुनिया "वर्क—लाइफ बैलेंस" और "फाइनेंशियल फ्रीडम" की बात करती है, तब राजस्थानी चुपचाप पीढ़ियों से दोनों हासिल कर रहा है। शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है – हम ज्यादा बोलते नहीं, हिसाब रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।

जय राजस्थान! जय मारवाड़!

□□□

शौर्य, संस्कृति और कालातीत सौंदर्य का महाकाव्य राजस्थान

'पधारो म्हारे देश'

राज-रंग
संजय कौशिक
जाने-माने लेखक एवं पर्यटन विशेषज्ञ
जयपुर
rajputan@dil.in

राजस्थान, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'राजाओं की भूमि', केवल भारत के मानचित्र पर एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक जीवित अनुभव है। यह वह धरा है जहाँ इतिहास की प्रतिध्वनि हर पत्थर से सुनाई देती है और जहाँ का कण–कण स्वाभिमान और सौंदर्य की गाथा गाता है। अपनी भव्य विरासत, जीवंत सांस्कृतिक रंगों और अद्वितीय भौगोलिक विरोधाभासों के कारण, राजस्थान आज वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक ऐसे नक्षत्र की भाँति चमक रहा है, जिसकी आभा समय के साथ और भी प्रखर होती जा रही है।

इस आलेख में हम राजस्थान के पर्यटन परिदृश्य, इसकी आर्थिक महत्ता और भविष्य की संभावनाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. भौगोलिक विरोधाभास- प्रकृति का अद्भुत कैनवास

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह विशालतम राज्य भौगोलिक विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कृति ने यहाँ सृजन के दो विपरीत रूप एक साथ उकेरे हैं–

स्वर्णिम मरुस्थल (थार)- राज्य का पश्चिमी भाग (जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर) थार के विशाल रेगिस्तान का घर है। यहाँ मीलों दूर तक फैले रेत के सुनहरे धोरे (ँदक क्नदमे) और मरुभूमि की निस्तब्धता पर्यटकों को एक अलौकिक शांति का अनुभव कराती है।

अरावली और हरितिमा- इसके ठीक विपरीत, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक 'अरावली', राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। यह न केवल पारिस्थितिक तंत्र का रक्षक है, बल्कि माउंट आबू जैसे मनोरम हिल स्टेशन और रणथंभौर व सरिस्का जैसे सघन वन्यजीव अभयारण्यों का आश्रय स्थल भी है। पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती के पठार अपनी नदियों और उपजाऊ मैदानों के साथ इस मरुधरा को जीवन प्रदान करते हैं।

2. पर्यटन- राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक प्रमुख स्तंभ है।

रोजगार सृजन- यह उद्योग लाखों हाथों को काम देता है। आलीशान हेरिटेज होटलों से लेकर ऊँट सफारी कराने वाले ग्रामीणों तक, और लोक कलाकारों से लेकर हस्तशिल्प के कारीगरों तक–पर्यटन रोजगार का एक विशाल वटवृक्ष है।

औद्योगिक दर्जा- राजस्थान की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम था कि यह पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य बना। इस कदम ने निवेश के द्वार खोले और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया।

3. वैश्विक आकर्षण- विरासत और आस्था का संगम

आंकड़े गवाह हैं कि भारत आने वाला लगभग हर तीसरा

विदेशी पर्यटक राजस्थान की ओर रुख करता है। राज्य को अक्सर एक 'ओपन आर्ट गैलरी' (Open Art Gallery) की संज्ञा दी जाती है।

शौर्य और स्थापत्य– चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ हो, कुंभलगढ़ की विशाल दीवार, या जैसलमेर का सोनार किला–ये इमारतें केवल पत्थर नहीं हैं, बल्कि राजपूत आन–बान–शान और अद्वितीय वास्तुकला के प्रमाण हैं।

शाही विलासिता– जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का लेक पैलेस राजशाही जीवनशैली की झलक प्रस्तुत करते हैं, जो आज 'लग्जरी टूरिज्म' का पर्याय बन चुके हैं।

धार्मिक सहिष्णुता– राजस्थान सर्वधर्म समभाव की भूमि है। यहाँ पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो सूफी परंपरा का केंद्र है। वहीं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी सूक्ष्म नक्काशी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

4. अमूर्त विरासत– संस्कृति, कला और जायका

राजस्थान की असली आत्मा इसके लोगों, उनके उत्सवों और कलाओं में बसती है।

स्वाद की परंपरा– राजस्थानी रसोई, विशेषकर 'दाल– बाटी –चूरमा', लाल मांस और बीकानेरी भुजिया, अपने तीखे और समृद्ध स्वाद के लिए विश्वविख्यात है।

लोक संस्कृति– यहाँ का संगीत रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ता है। 'कालबेलिया' और 'घूमर' जैसे नृत्य, तथा लंगा–मांगणियार की गायकी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी धाक जमाई है।

रंग-बिरंगा पहनावा– पुरुषों के सिर पर सजी रंगीन साफें (पगड़ियाँ) और महिलाओं की गोटा–पट्टी वाली ओढ़नियाँ मरुस्थल के सूखेपन में रंगों की बहार ला देती हैं।

5. यूनेस्को (UNESCO) की मुहर– वैश्विक मान्यता

संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजस्थान की धरोहरों को दी गई मान्यता इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है–

पहाड़ी किले (Hill Forts) – 2013 में राज्य के छह प्रमुख किलों (चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर) को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।

जयपुर (पिंक सिटी) – 2019 में जयपुर के परकोटा शहर को

उसकी ग्रिड प्लानिंग और वास्तुकला के लिए 'विश्व धरोहर शहर' घोषित किया गया।

प्राकृतिक और खगोलीय स्थल- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (पक्षियों का स्वर्ग) और जंतर–मंतर (खगोलीय वेधशाला) भी इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा हैं।

6. भविष्य की राह- प्रतिस्पर्धा और नवाचार

पर्यटन बाजार में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए और अन्य राज्यों (जैसे केरल, गोवा) से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, राजस्थान को अपनी 'ब्रांडिंग' में नवाचार लाना होगा।

थीम-आधारित पर्यटन- केवल ऐतिहासिक इमारतों तक सीमित न रहकर, 'रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन', 'एडवेंचर टूरिज्म' (हॉट एयर बैलूनिंग, ड्यून बैशिंग) और 'वेलनेस टूरिज्म' पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है।

डिजिटल क्रांति- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल टूर के माध्यम से नई पीढ़ी (Gen-Z) को आकर्षित करना होगा। 'राजस्थान – एक कहानी' जैसे डिजिटल अभियान चलाकर भावनात्मक जुड़ाव बनाना आवश्यक है।

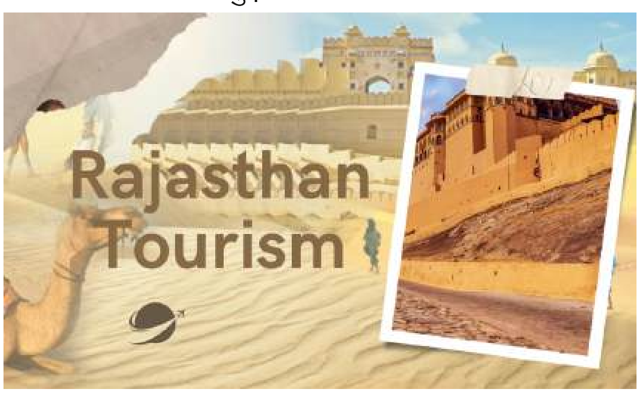

कनेक्टिविटी- छोटे शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई और रेल कनेक्टिविटी को और सुगम बनाना होगा।

अंततः, राजस्थान केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का एक अहसास है। इसकी हवाओं में स्वागत का सुर है और मिट्टी में अपनापन। अपनी गौरवशाली विरासत और आधुनिक दृष्टिकोण के सामंजस्य के साथ, राजस्थान आज भी पूरी दुनिया को बाहें फैलाकर आमंत्रित कर रहा है– **''पधारो म्हारे देश।''**

❑❑❑

RSS Sarsanghchalak Shri Mohan Bhagwat ji discussed about AI based Defence Equipments exhibited and produced by LUB's National Co-Treasurer and Leading Entrepreneur Shri Janak Bhatia at IMS, Bengaluru on 9th Nov. On this occasion, RSS Seh Sarkaryawah Shri (Dr.) Krishna Gopal ji and LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji and IMS President Shri HVS Krishna were also present.

LUB's Jaipur Prant President Shri Mahendra Mishra addressing the Workshop on Cost & Competitiveness in MSMEs conducted at Jaipur on 9th Nov.

LUB's Chandigarh Unit conducted EC in the presence of National GS Shri O.P. Gupta, National VP Shri Arvind Dhumal, Mass Media Convenor Shri Vikrant Sharma, and GS Punjab Shri Vivek Rathore on 15th Nov. During his address, Shri Gupta shared valuable guidance on promoting the MSME sector and vision of Viksit Bharat.

प्रवासी राजस्थानी – 'दिसावर से वापस देस की ओर'

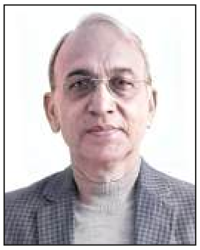

जड़ों की ओर

संपत तोषनीवाल
पूर्व राष्ट्रीय सचिव
लघु उद्योग भारती, दिल्ली
toshniwalsampat@gmail.com

19वीं सदी में रियासतों में बंटा हुआ राजस्थान कृषि, व्यापार, उद्योग और रोजगार की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था। आवागमन के साधन अत्यंत सीमित थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजस्थान के वैश्य समुदाय (माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन आदि) के लोगों ने व्यवसाय के लिए राजस्थान के बाहर देश के अन्य प्रदेशों, मुख्यतः कलकत्ता (अब कोलकाता), असम और महाराष्ट्र में प्रवास आरंभ किया। मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के लोग इसमें अग्रणी थे। उदाहरणार्थ, सेठ शिवनारायण जी बिरला ने सन् 1860 में पिलानी से बंबई (अब मुंबई) जाकर वहाँ रूई का व्यापार आरम्भ किया। यह क्रम निरंतर चलता रहा और आज भी जारी है।

व्यावसायिक कौशल से संपन्न राजस्थान के प्रवासी व्यवसायियों ने अपने परिश्रम के बल पर व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की है। आज देश के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक घराने राजस्थानी मूल के ही हैं, जैसे बिरला, बांगड़, डालमिया, सिंघानिया, रूईया, पोद्दार इत्यादि। इनके अतिरिक्त हजारों अन्य प्रतिष्ठित घराने सम्पूर्ण देश में विद्यमान हैं। आज भारत की प्रत्येक तहसील में राजस्थान के प्रवासी बसे हुए है।

उल्लेखनीय बात यह है कि इन प्रवासियों ने अपने मूल जन्म स्थान से निरन्तर अपना सम्बन्ध बनाए रखा। राजस्थान के लोक–जीवन में एक शब्दावली, "देस–दिसावर" बहुत प्रचलित रही है। 'देस' अर्थात अपना जन्म स्थान, और 'दिसावर' अर्थात अपना कर्मस्थान। एक निश्चित अंतराल के बाद नियमित रूप से अपने जन्म स्थान पर लौटने को एक "दिसावरी" या "मुसाफिरी" कहा जाता था।

न केवल इन प्रवासियों ने अपने 'देस' को समृद्ध बनाया, बल्कि अपने 'दिसावर' में भी सेवा और जनकल्याण के अनेक कार्य किए। उदाहरणार्थ, आज कोलकाता के अनेक सार्वजनिक बड़े अस्पताल और विद्यालय राजस्थानी उद्योगपतियों की ही देन हैं। देश के अन्य भागों में भी ऐसे अनेक उदाहरण है।

आज राजस्थान की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। कृषि, शिक्षा, व्यापार के विकास और बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप राजस्थान आज तीव्र औद्योगिक और आर्थिक विकास के मुहाने पर खड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में उद्योग लगाने का आह्वान कर अत्यंत सकारात्मक पहल की है। 'राइजिंग राजस्थान' अभियान के अंतर्गत एक वर्ष पूर्व मैंने भी प्रदेश के उद्योग विभाग के साथ एक MOU किया था। इस संबंध में मैं राजस्थान सरकार को निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ।

- औद्योगिक विकास हेतु भूमि प्राथमिक आवश्यकता है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अतः प्रवासी उद्यमियों को भूमि रीको (RIICO) द्वारा नीलामी के माध्यम से देने के स्थान पर आरक्षित या रियायती मूल्य पर आवंटित की जाए।
- भूमि आवंटन से लेकर परियोजना पूर्ण करने की अवधि वर्तमान में 3 वर्ष निर्धारित है, जो राजस्थान के स्थानीय निवासियों के लिए तो उचित है, किंतु प्रवासी उद्यमियों के लिए यह अवधि न्यूनतम 5 वर्ष की जाए, क्योंकि प्रवासियों को अपेक्षाकृत अधिक समय लगना स्वाभाविक है।
- राजस्थान वित्त निगम की 'युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत ब्याज में छूट (Interest subvention) की सुविधा वर्तमान में केवल प्रथम 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर उपलब्ध है। इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

प्रवासियों द्वारा अपने प्रदेश में किया गया विनियोजन मात्र इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके साथ प्रवासियों के व्यावसायिक हित जुड़े हुए है, अपितु अपने प्रदेश के प्रति उनका गहरा भावनात्मक लगाव भी इससे जुड़ा हुआ है।

□□□

13th India Industrial Fair (IIF-UDYAM 2025)

A Collective Achievements of Team Spirit & Efforts @ North-East

Report

Partha Pratim Pathak
State President
Laghu Udyog Bharati, Assam
partha.pfreshairindia.com

The 13th India Industrial Fair (IIF-Udyam 2025) emerged as one of the most impactful industrial exhibitions organized by Laghu Udyog Bharati, Purvottar Prant at Veterinary College Ground, Khanapara, Guwahati on 30 Oct.-2 Nov. 2025.

The event was inaugurated in the august presence of the MoS for MSME, Govt. of India, and the Minister of Industries & Commerce, Govt. of Assam, whose participation added stature and inspiration to the four-day event.

More than 300 exhibitors participated from sectors such as Food Processing, Renewable Energy, Electrical & Electronics, Pharmaceuticals, Packaging, Rubber, Waste Management, Handloom, Handicrafts, and Ayurveda. A total of 22,600 visitors attended, reflecting strong interest from across the Northeastern states.

The IIF-Udyam was organized under the guidance of the Chief Minister of Assam Shri (Dr.) Himanta Biswa Sarma and supported by the Ministry of MSME, Govt. of India, the fair successfully brought together entrepreneurs, industry leaders, students, and institutions on a single platform.

Industry-Academia Partnership

A key achievement was the signing of an MoU between the Directorate of Technical Education (DTE), Govt. of Assam, and Laghu Udyog Bharati (Purvottar Prant). This collaboration enables engineering and polytechnic students to participate in internships, industrial visits, and live projects across 850 MSME units associated with LUB. The initiative aims to strengthen industry-ready skills and promote entrepreneurship among youth.

Swabalambi Bharat Abhiyan Highlights

The fair featured a dedicated pavilion showcasing **ten grassroots entrepreneurship models** under the Swabalambi Bharat Abhiyan.

Supported by Bharatiya Kishan Sangh, Seva Bharati,

and Swadeshi Jagaran Manch, these projects highlighted local innovation and self-reliance. Among them, **"Khetiok"** emerged as a major attraction. All participation costs were sponsored by Laghu Udyog Bharati Purvottar, reflecting its commitment to inclusive development.

Business Outcomes: Sales & B2B Orders

The fair recorded strong business activity, with exhibitors reporting **encouraging sales**, steady customer engagement, and **high-interest B2B enquiries**. Many exhibitors received distributorship and supply-chain enquiries, indicating buyer confidence in Northeast-based MSMEs. While sales performances varied, the overall response confirmed that the event provided valuable commercial opportunities for both established and emerging enterprises.

Technology Knowledge & Skill Advancement

IIF-Udyam 2025 served as a knowledge hub for entrepreneurs and students. Seminars addressed crucial themes such as **Artificial Intelligence, Semi-conductor Opportunities, E-Commerce, Banking & MSME Financing, Energy Efficiency, Environ-mental Management, and Women Entrepreneur-**

ship. Participants gained exposure to new machinery, automation technologies, renewable-energy systems, and modern packaging equipment, enabling them to assess technology upgrades and competitiveness.

Market Expansion Opportunities

The fair created significant opportunities for MSMEs to expand into new markets. Exhibitors connected with buyers and distributors from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, and beyond. Startups and women-led enterprises under the "Swayamsiddha" initiative particularly benefitted from the visibility and networking prospects, receiving leads that would otherwise be difficult to access.

Extensive Publicity & Outreach

The event received widespread visibility through outdoor publicity, FM Radio promotion, newspaper advertisements, and extensive statewide publicity conducted through the Assam DIPR. This ensured an exceptional public awareness and strong footfall across all four days.

Conclusion

IIF-Udyam 2025 successfully connected industry, academia, government, and youth on a dynamic platform that highlighted innovation, entrepreneurship, and collaboration. The fair generated strong business interest, inspired new partnerships, and provided exposure to emerging technologies. With its successful outcomes, IIF–Udyam 2025 has set a new benchmark for industrial development in the Northeast and laid the foundation for even greater achievements at IIF–Udyam 2026.

Team for IIF-Udyam

Dedicated Team for IIF-Udyam National Jt. Gen. Secretary Shri Ashish Deorah, Ex Member NWC & Chairman Shri Manoj Lundia, Prant President Shri Partha Pratim Pathak, Vice President Shri Vivek Agarwal, General Secretary Shri Pramod Mour, Treasurer Shri Amit Chirawala, Former Prant President Shri Ravi Sureka, Shri Vikash Agarwal, Dr. Vivek Sharma, Shri Harsh Agarwal, Shri Arup Barpujary, Shri Bijit Prakash, Shri Ankit Nandalal Jodhani, Shri Rajen Kalita, Shri Ambarish Sarma, Md. Samim, Shri Arun Poddar, Shri Sahil Mour, Shri Swarup Paul, Shri Ratan Sikaria, Shri Kanak Jain, Shri Shiv Soni, Shri Rahul Sikaria, Smt. Krishna Kalita, Smt. Kirti Agarwal, Smt. Rupamoni Pathak, Smt. Neha Mehra and Smt. Ranjana P. Bhajanka.

❑❑❑

Odisha Industrial Conclave 2025: A Resounding Success

Report
Saroj K. Sahoo
Prabhari, Odisha State, LUB

LUB's Odisha state recently hosted the Odisha Industrial Conclave-2025, a landmark event that brought together industry leaders, policymakers, and MSMEs to drive growth and development in the state. The conclave was inaugurated by esteemed dignitaries, including the Speaker, Odisha Legislative Assembly, LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, Industry Minister & MSME Minister, Govt. of Odisha.

The event saw the participation of top officials from Govt. of Odisha, including the All India Organising Secretary of Lub, All India President, All India Vice President, Odisha President, General Secretary and all the members of Laghu Udyog Bharati and other organisations from the state. The conclave provided a platform for networking, knowledge sharing, and collaboration, with a focus on empowering MSMEs and promoting industrial growth in Odisha.

The Valedictory session was graced by the Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi, who lauded Laghu Udyog Bharati's efforts in promoting MSMEs and announced the establishment of an office for LUB Odisha. The Chief Minister assured the MSME sector of the government's support, echoing the sentiments of the Industry Minister and MSME Minister, who promised all types of help to MSMEs.

The conclave was a testament to the government's commitment to making Odisha a hub for industrial growth and development. With the Prime Minister's vision for Odisha's progress, the event was a significant step towards realizing this dream.

Chief Minister said it is a dream and love to Odisha of our Beloved Prime Minister as he says Odisha Should be Gate Way of MSMEs in Eastern Part of India as Mission Purvodaya and we are working hard to fulfil it.

In the conclave, the technical support sessions on LEAN, ZED, LUB E-Vyapar Advance Platform (LEAP), banking schemes for MSMEs and Cyber Security were very useful.

Union Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav shared his message for appreciation the People of Odisha. A big thanks to East Coast Railway for their whole hearted support. The Odisha LUB team works very hard since last one month to make it a grand success. Program started with Vandematram by the students of Saraswati Shishu Mandir and the welcome address of Odisha President Shri Gopal Das Agarwal who welcomed the guest with a brief working of LUB Odisha and concluded by Vote of Thanks by Shri Debasish Mohapatra, state treasurer and conclave ended with National Anthem.

An exhibition was also inaugurated by National Org. Secretary and all Ministers visit it to encourage the participants in the venue. Thanks to ESIC and PF, SIDBI, EAST-COST RAILWAY, NSIC, SBI, PNB, CANARA Bank, ZED for supporting the event.

LUB's News in Brief

LUB's Core Committee Meeting was conducted at Head office, New Delhi on 19th Nov. National Org. Secretary Shri Prakash Chandra Ji, Former National President Shri Ghanshyam Ojha & National President Shri M. S. Dadu, National GS Shri OP Gupta and core team members were present. The meeting focused on strengthening the organisation, strategies, impactful MoUs and skill-enhancement training programs.

LUB's National President Shri Ghanshyam Ojha, Former State President Shri Shantilal Balar and Jodhpur Prant GS Shri Suresh Vishnoi met Cabinet Minister Law & Justice Shri Jogaram Patel, BJP State President Shri Madan Rathor, Minister for Social Justice & Empowerment Shri Avinash Gehlot, Minister for Dairy & Gopalan Shri Joraram Kumawat, MoS Industry & Commerce Shri KK Vishnoi and MoS Rural Development Shri Otaram Devasi, Chief Whip Shri Jogeshwar Garg at Jodhpur and discussed about Western Rajasthan Industrial Handicraft Utsav and Stonemart Exhibition on 18th Nov.

73rd meeting of Empowered Committee on MSME was held on 11th Nov. at Reserve Bank of India, New Delhi, chaired by Shri Rohit P. Das, Regional Director, RBI along with representatives of various scheduled and private sector banks, NABARD, SIDBI, MSME-DFO. Laghu Udyog Bharati was represented by Shri CA Manoj Kumar Rungta, General Secretary, Haryana

and Shri Rajesh Gupta, VP, Rajasthan. LUB's delegation raised major issues including to rely on self-certified financials in case of turnover up to Rs.10 crores covered by section 44AB of Income Tax Act,1961, freezing of bank account in case of unintentional receipt of money in chain of cyber-crime and Automatic nullification of expired Bank Guarantees.

LUB's Jaipur Prant introduced Food & Agro Unit in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, National Secretary Smt. Anju Singh, State GS Shri Sudhir Garg, President Shri Mahendra Mishra and GS Ms. Sunita Sharma on 11th Nov. Unit President Shri Pankaj Goyal and Secretary Shri Harsh were nominated.

LUB's MP State EC Meeting was conducted in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, National VP Shri Tarachand Goyal, Former National President Shri Vajubhai Vaghasia, State President Shri Rajesh Mishra and GS Shri Arun Soni and discussed on the Future Agenda on 9th Nov.

□□□

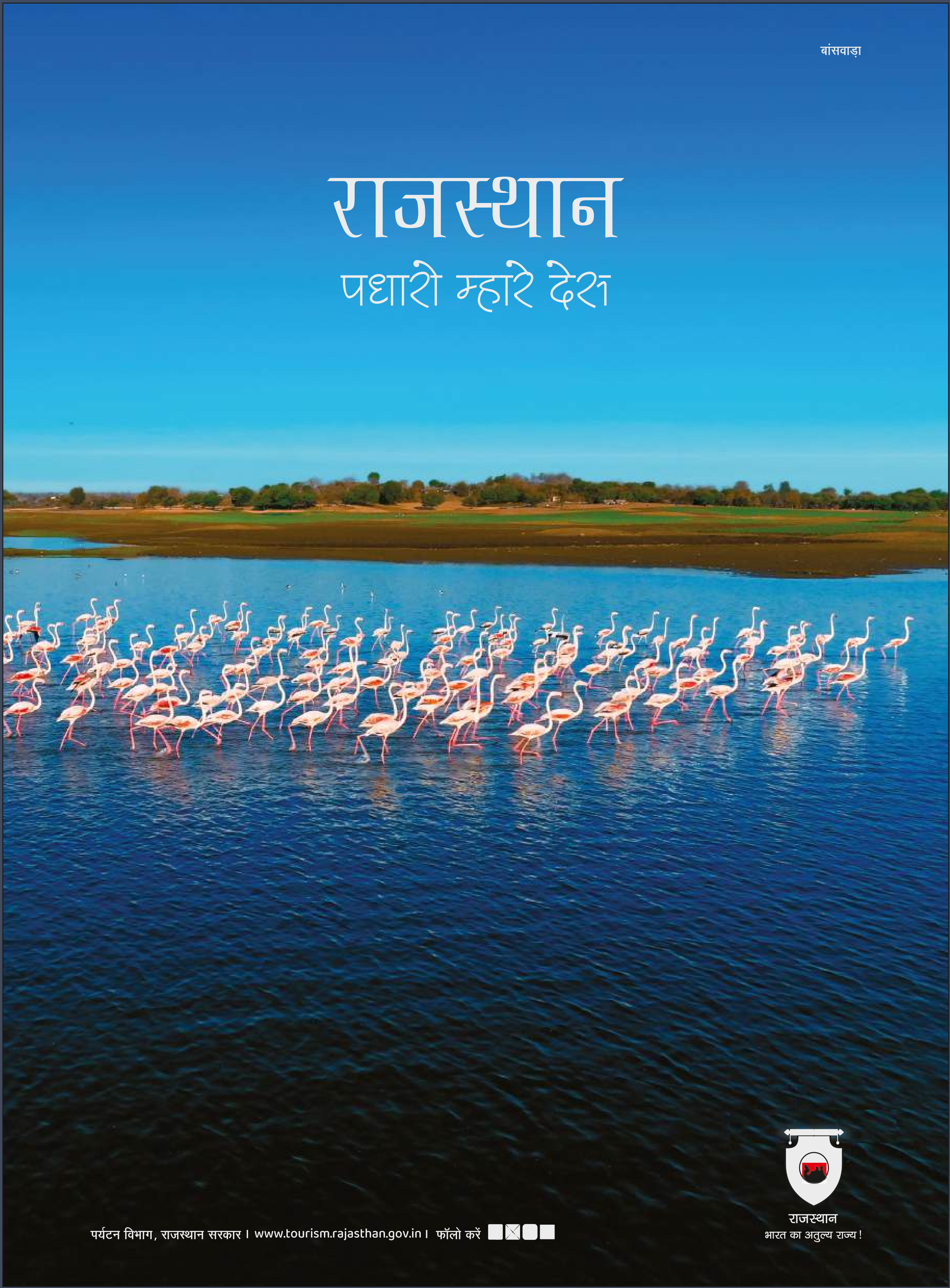
बांसवाड़ा
राजस्थान
पधारो म्हारे देस
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार । www.tourism.rajasthan.gov.in । फॉलो करें
राजस्थान
भारत का अतुल्य राज्य !

UDYOG TIMES
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
30 November-2025
Registration No. RAJBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

सत्यमेव जयते
Government of Rajasthan

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister
India

Shri Bhajanlal Sharma
Hon'ble Chief Minister
Rajasthan

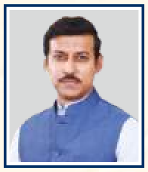

Shri Rajyavardhan Rathore
Hon'ble Minister for
Industry and Commerce
Rajasthan

Shri K.K. Vishnoi
Hon'ble Minister of State for
Industry and Commerce
Rajasthan

INDIA'S BIGGEST
STONE INDUSTRY SHOWCASE

13th
INDIA STONEMART2026
Stone for Sustainability
5 - 8 February, 2026
JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

REGISTER NOW
stonemart-india.in

Organiser
CDOS
Centre for Development of Stones

Principal Sponsor
RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

Co-Organiser
LAGHU UDYOG BHARATI
लघु उद्योग भारती

Fair Sponsor
RK MARBLE
KHOOBSURAT IMAANDAARI

info@stonemart-india.in | www.stonemart-india.in | +91-7300053633

Follow us
lubindia
@lubBharat
laghu-udyog-bharati
lubindia
lub.india

LUB's Monthly Magazine Published by OP Mittal Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019